चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

29 दिसंबर 2014-04 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

पेशावर में

मर गई इंसानियत

पाकिस्तान के पेशावर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी. साथ ही इस हमले में सैकडों लोग घायल हुए. पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है. अब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भारत और दूसरे देशों के नागरिकों को निशाना बनाते रहे लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के पेशावर में आतंक का ऐसा खेल खेला जिससे इंसानियत मर गई. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों और चश्मदीदों ने स्कूल के अंदर की जो कहानी बताई उससे हर इंसान का दिल दहल उठा. पेश है, पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए हमले की पूरी कहानी.

मनीष कुमार

16 दिसंबर के उस दिन, पाकिस्तान के पेशावर शहर में सब कुछ नार्मल था. किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि आने वाले चंद घंटो में पेशावर शहर में मौत का ऐसा तांडव होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा. शहर के कैंट इलाके के बीचों-बीच आर्मी पब्लिक स्कूल स्थित है. यहीं पास में सेना के कोर कमांडर का दफ्तर है. फ्रंट गेट पर सिक्योरिटी थी. गेट पर स्कूल का मोटो लिखा है राइज एंड शाइन. मतलब यह कि बड़ा बनो और पूरी दुनिया में छा जाओ. यह किसी को पता नहीं था कि स्कूल के बच्चे न तो बड़े हो पायेंगे और न ही अपनी चमक से दुनिया को रौशन कर पायेंगे. स्कूल के अंदर हर दिन की तरह बच्चे अपनी-अपनी क्लास में पढ़ रहे थे. कुछ क्लास के बच्चों की परीक्षा थी. कुछ बच्चे परीक्षा खत्म कर धूप में हंसी मजाक कर रहे थे. स्कूल के ऑडिटोरियम में कुछ बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही थी. ज्यादातर बच्चे क्लास रूम में थे. टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे थे.

इस आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे एक कब्रिस्तान है. कब्रिस्तान से सटा एक मोहल्ला है जिसे पेशावर में बिहारी कॉलोनी कहा जाता है. पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी एक कार में आए थे. ये कार इस्लामाबाद से चोरी की गई थी. लोगों का ध्यान हटाने के लिए आतंकियों ने स्कूल के पीछे बिहारी कॉलोनी के पास कार में आग लगा दी थी और कब्रिस्तान की ओर से स्कूल की तरफ बढ़ गए. करीब पौने बारह बजे कब्रिस्तान की ओर से यानि स्कूल के पीछे की दीवार को फांदकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के छह आतंकी स्कूल परिसर में दाखिल हुए. आतंकियों को पता था कि उन्हें क्या करना है. उन्हें न किसी को धमकी देनी थी, न ही किसी को अगवा करना था. उन्हें सिर्फ मौत का खेल खेलना था. इसलिए स्कूल परिसर में दाखिल होते ही उन्हें जहां कहीं भी बच्चे नज़र आये वो उन पर गोलियां दागने लगे.

> एक आतंकी केमिस्ट्री लैब में घुसा था लेकिन बाकी आतंकी दूसरी कक्षाओं की ओर बढ़ गये. हर क्लास की एक ही कहानी थी. आतंकी क्लास में घुसते और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते. गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे दहशत में आ जाते. बच्चों के सिर में गोली, छाती में गोली, आंख में गोली. जो बच्चा इन आतंकियों के सामने आया उसे इन हैवानों ने छलनी कर दिया. हादसे में बचे एक बच्चे ने बताया कि आतंकी उसकी क्लास में घुसते ही गोलियां चलाने लगे.

अजमल खान और आमिर अमीन दोनों परीक्षा देने के बाद कॉलेज के कॉरिडोर मे टहल रहे थे. अचानक से उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी. दोनों ने पलटकर देखा तो उन्हें दो आतंकी नज़र आये जो गोलियां चलाते और चिल्लाते हुये उनकी तरफ बढ़ रहे थे. दोनों इंटरमीडिएट के छात्र थे. उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि स्कूल पर आतंकियों का हमला हो गया है. दोनों भागने लगे. दोनों केमेस्ट्री लैब में जाकर छिप गये, लेकिन एक आंतकी उनके पीछे-पीछे केमेस्ट्री लैब तक पहुंच गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा. आमिर पीछे था, अजमल सामने था, गोलियां अजमल को लग रहीं थीं, खून के छींटे आमिर के शरीर पर पड़ रहे थे. जब आतंकी को यह भरोसा हो गया कि दोनों मारे गये हैं तो वह वहां से चला गया. आमिर की गोद में अजमल की जान गई. वह सदमे में था. वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं आतंकी फिर से वापस न आ जायें. आमिर को भी गोलियां लगी थीं. उसके शरीर से भी खून निकल रहा था. दर्द और सदमे को ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया. अब वह अस्पताल में है, सहमा हुआ है, दोस्तों को याद करता है और केमेस्ट्री लैब की घटना को याद करता है. उसने बताया कि केमेस्ट्री लैब में 4 टीचर और 6 लड़के थे जो वहां छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकियों ने सबको मार डाला. मरने वालों के सिर पर गोलियां लगी थीं.

एक आतंकी केमिस्ट्री लैब में घुसा था लेकिन बाकी आतंकी दूसरी कक्षाओं की ओर बढ़ गये. हर क्लास की एक ही कहानी थी. आतंकी क्लास में घुसते और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते. गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे दहशत में आ जाते. बच्चों के सिर में गोली, छाती में गोली, आंख में गोली. जो बच्चा इन आतंकियों के सामने आया उसे इन हैवानों ने छलनी कर दिया. हादसे में बचे एक बच्चे ने बताया कि आतंकी उसकी क्लास में घुसते ही गोलियां चलाने लगे. पूरी क्लास के सामने महिला टीचर के शरीर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत में भी हुईं आंखें नम

पाकिस्तान के पेशावर में हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की. मोदी ने नवाज को सांत्वना देते हुए कहा कि हमारा देश दुख की घड़ी में आपके साथ हैं. नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह मासूम बच्चों की निर्मम हत्या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ हमला है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी पेशावर के आतंकवादी हमले की भर्त्सना की. संसद के दोनों सदनों में भी इस भयावह नरसंहार पर घोर आक्रोश और दुख व्यक्त किया गया. लोकसभा ने सभी तरह के आतंकवाद से दृढ़ता से मुक़ाबला करने का संकल्प व्यक्त करते हुए एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया. संसद के दोनों सदनों में कुछ पलों का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सिडनी और पेशावर के आतंकी हमलों पर अपनी ओर से लोकसभा में दिए बयान में कहा कि ये दोनों घटनाएं मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए एक पुकार है कि वे मिलकर आतंकवाद का समूल नाश करें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के तमाम स्कूलों में असेंबली के वक्त दो मिनट का मौन रखकर पेशावर के आतंकी हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई. ■

आतंकवाद से पाकिस्तान नहीं लड़ सकता

पेज-03

आम आदमी के ख़ास काम

पेज-04

मांझी सरकार की नाक में फंस गए कुलदीप नारायण

पेज-06

साई की महिमा

पेज-12

...मर गई इंसानियत

पृष्ठ एक का शेष

में आग लगा दी. फिर गोलियों से उसके जलते हुए शरीर को भून डाला. चौथी क्लास के एक छात्र जिशान ने बताया कि आतंकी क्लास में घुसते ही गोलियां बरसाने लगे. सबसे पहले टीचर को निशाना बनाया, इसके बाद बंदूक की नली बच्चों की तरफ मोड़ दी. क्लास रूम में बच्चे अपनी–अपनी सीटों पर बैठे थे इसलिए ये दरिंदे छोटे–छोटे मासूम बच्चों के सीने और सिर को निशाना बनाकर गोलियां दाग रहे थे. कुछ कक्षाओं में भगदड़ मच गई. इस दौरान कुछ बच्चे जमीन पर गिर गए तो इन कायरों ने उनकी पीठ पर गोलियां दाग दीं.

चौदह साल का शाहनवाज़ खान अस्पताल में भर्ती है. वो अपनी क्लास की कहानी बताता है जिससे पता चलता है कि आंतकी कितने निर्दयी और क्रूर थे. उसकी क्लास में टीचर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे. जब अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो टीचर ने कहा कि शायद यह आवाज़ ऑडिटोरियम में चल रहे फर्स्ट एड के डेमोंशट्रेशन से आ रही है. लेकिन जैसे ही गोलियों के साथ बच्चों की चीखें सुनाई दीं तो सब सहम गए. इसके बाद टीचर ने दरवाजे से बाहर झांककर देखा और घबराते हुए बच्चों से बेंच के नीचे छिप जाने को कहा. जब तक टीचर गेट बंद कर पाते, दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गए. शाहनवाज ने बताया कि इसके बाद दो आदमी हाथ में बंदूक लिए क्लास रूम में दाखिल हुए. दोनों ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी. क्लास में घुसते ही एक आतंकी ने कहा कि सब शांत होकर बैठ जाओ और जैसा कहा जाये वैसा करो. इसके बाद एक आतंकी ने कहा कि आठ लोग जो यहां से बाहर जाना चाहते हैं अपने–अपने हाथ खड़े करें. इतना बोलते ही क्लास के सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिये. सभी बच्चे कांप रहे थे और डर के मारे सहमे हुए थे. इसके बात आतंकियों ने आठ बच्चों को चुना और उन्हें ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अपने दोस्तों को देखो. धक्का देकर टीचर को उनकी चेयर पर बैठाया और कहा कि अपने प्यारों को मरते हुए देखो. इसी तरह हमारे बच्चों को भी मारा जा रहा है. इतना कहते ही एक आतंकी ने आठों बच्चों के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया. कुछ तो धड़ाम से जमीन पर गिर गये और कुछ दर्द से कराहते हुए मौत से जूझते रहे. जब तक उनकी मौत नहीं हो गई तब तक गोलियां चलती रहीं. इसके बाद दूसरे आतंकी ने कहा कि अब आठ और बच्चे मुझे चाहिए. कौन–कौन बाहर जाना चाहता है. अपने–अपने हाथ खड़े करो. इस बार क्लास में एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा. इसके बाद आतंकी ने एक बच्चे को पकड़कर खींचने की कोशिश की. लेकिन उसे कुछ बच्चों ने पकड़ लिया. बच्चे आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए थे. इसके बाद दोनों आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दीं. शाहनवाज को दो गोलियां लगीं. उसके क्लास के कई बच्चों की मौत हो गई. टीचर के कंधे में एक और छाती में एक गोली लगी, बावजूद इसके वह बच गए. उनका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है. पत्रकारों ने जब उनसे बात की तो वह फफक–फफक कर रोने लगे. वह कहने लगे कि अल्लाह गवाह है कि मैंने अपने बच्चों की मदद करने की बहुत कोशिश की. लेकिन उन्हें बचा न सका.

चौदह साल का शाहनवाज़ खान अस्पताल में भर्ती है. वो अपनी क्लास की कहानी बताता है जिससे पता चलता है कि आंतकी कितने निर्दयी और क्रूर थे. उसकी क्लास में टीचर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे. जब अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो टीचर ने कहा कि शायद यह आवाज़ ऑडिटोरियम में चल रहे फर्स्ट एड के डेमोंशट्रेशन से आ रही है. लेकिन जैसे ही गोलियों के साथ बच्चों की चीखें सुनाई दीं तो सब सहम गए.

सबसे ज्यादा मौतें ऑडिटोरियम के अंदर हुईं. यहां काफी बच्चे थे. यहां बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही थी. आतंकी यहां सबसे आखिर में पहुंचे थे. ऑडिटोरियम के पीछे का दरवाजा बंद था. आंतकी ऑडिटोरियम में सामने वाले दरवाजे से दाखिल हुए. सबसे ज्यादा खून खराबा ऑडिटोरियम के इसी दरवाजे पर हुआ. जब सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचे तो ऑडिटोरियम के गेट पर उन्होंने बच्चों की लाशों का ढेर देखा. बच्चे अपनी जान बचाकर ऑडिटोरियम से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन आतंकियों की नज़र शायद उसी गेट पर लगी थी. जिस किसी ने भी ऑडिटोरियम से बाहर निकलने की कोशिश की, आतंकियों ने उसे मार गिराया. इसी वजह से गेट पर एक के ऊपर एक लाशें इकट्ठी होती गईं.

सोलह साल का शाहरुख उस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद था. उसने बताया कि अचानक से चार बंदूकधारी आतंकी ऑडिटोरियम में दाखिल हुए और वहां मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया. गोलियों की आवाज के बीच उसने अपने टीचर को यह चिल्लाते हुए सुना कि नीचे लेट जाओ. डेस्क के नीचे छिप जाओ. गोलियों की आवाज बंद होते ही शाहरुख को एक भारी सी आवाज सुनाई दी. उसने कहा कि बहुत सारे बच्चे बेंच के नीचे छिपे हैं मारो उन्हें. बेंच के नीचे गोलियां चलाओ. शाहरुख बेंच के नीचे छिपा था. उसने देखा कि दो काले जूते उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. उसे समझ में आ गया कि ये जूते उन्हीं आतंकियों के हैं जो बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं. शाहरुख के दोनों पैरों में गोलियां लगी थीं. घुटनों के नीचे उसे जोर का दर्द हो रहा था. उसने देखा कि काले जूते वाला शख्स बेंच के नीचे बच्चों को ढूंढ रहा था. बच्चों को देखते ही उनपर गोलियां दाग रहा था. शाहरुख के आखों के सामने मौत मंडरा रही थी लेकिन उसका दिमाग चल रहा था. उसने अपनी टाई निकाली और मोड़ कर अपने मुंह के अंदर ठूंस ली ताकि पैरों के दर्द की वजह से उसकी आह न निकले. वह आंखे बंद करके एक मुर्दा होने की एक्टिंग करने लगा. डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था. आंख बंद करके वह फिर से गोली लगने का इंतजार करता रहा. कुछ देर बाद गोलियों की आवाज शांत हो गई. उसने आंखें खोलकर देखा तो आतंकी वहां से जा चुके थे. शाहरुख ने उठने की कोशिश की लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया. वह रेंगने लगा. रेंगते हुए जब वह ऑडिटोरियम से बाहर निकला और दूसरे कमरे में पहुंचा. वहां उसने स्कूल की एक महिला कर्मचारी को देखा, वह कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसका शरीर जल रहा था. उसके जलते हुए शरीर से खून निकल रहा था. शाहरुख रेंगते हुए उस कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गया और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया. जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अस्पताल के बेड पर था.

स्कूल के अंदर आतंकी खून की होली खेल रहे थे और बाहर पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रही थी. कैंट एरिया नजदीक था, इसलिए मदद समय पर पहुंच गई. स्कूल के बाहर के इलाके को आर्मी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था. स्कूल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे. आर्मी ने अंदर का जायजा लिया और आर्मी स्कूल के अंदर दाखिल हो गई. आतंकी जगह बदल–बदल कर आर्मी से लड़ते रहे. स्कूल परिसर के अंदर आर्मी ने एक तरफ से आतंकियों की खोज शुरू की. यही वह वक्त था जब स्कूल से घायल बच्चों और बच्चों की लाशों को बाहर भेजा जाने लगा. टीवी के जरिए पूरी दुनिया इस खौफनाक मंजर को देख रही थी. एक तरफ सेना बच्चों को अस्पताल भी भेज रही थी दूसरी तरफ आतंकियों के साथ उनकी झड़प भी जारी थी. आर्मी स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स के अभिभावकों की भीड़ जमा थी. अपार हिम्मत वाले पिताओं का चेहरा सहमा हुआ नज़र आ रहा था. गोद सूनी हो जाने का खौफ स्कूल के बाहर खड़ी हर मां की आंखों में साफ–साफ नज़र आ रहा था. स्कूल के बाहर आलम यह था कि जिनके बच्चे इस स्कूल मे नहीं पढ़ते थे वह भी फूट–फूटकर रो रहे थे.

पाकिस्तानी एजेंसियों के हवाले से यह खबर आई कि हमलावर लगातार अपने गिरोह के सरगना से बात कर रहे थे. एक आतंकी ने अपने आकाओं से फोन पर बात कर यह पूछा कि सारे बच्चों को उन्होंने मार दिया है, अब उन्हें आगे क्या करना है? उन्हें आदेश मिला कि आर्मी भी स्कूल के अंदर दाखिल हो गई है आर्मी से लड़ो और उन्हें मारो. पकड़े जाने से पहले खुद को बम धमाके से उड़ा लो. आंतकवादियों ने अपने आकाओं के हर हुक्म का पालन किया और एक–एक करके छह में से चार आतंकियों ने आत्मघाती बम धमाके में खुद को मार डाला. अन्य दो आतंकियों को पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने मार गिराया.

इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान ने ली. यह फजलुल्लाह का नेटवर्क है. सभी हमलावर तहरीक–ए–तालीबान पाकिस्तान के सदस्य थे. ये एक आतंकी संगठन है लेकिन ये खुद को इस्लामिक जिहाद करने वाले सैनिक मानते हैं. तहरीक–ए–तालिबान द्वारा घोषित तीन प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: पाकिस्तान में शरिया क़ानून स्थापित करना, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह और अफ़ग़ानिस्तान में नाटो सेना के खिलाफ मुहिम चलाना. फजलुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी के मुताबिक स्कूल पर हमला करके वे पाकिस्तान सरकार से बदला ले रहे हैं. यह नार्थ–वजीरिस्तान में चल रहे सैनिक ऑपरेशन और पुलिस कस्टडी में मारे गए तालिबानी साथियों की मौत का बदला है. स्कूल में हमला होने के 2 घंटे के अंदर ही तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी ले ली, नहीं तो पाकिस्तान में यह अफवाह फैलने लगी थी यह हमला भारत द्वारा प्रायोजित है. जिस वक्त स्कूल के अंदर आर्मी ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त ही तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान ने यह भी कहा कि स्कूल में दाखिल आंतकवादी लगातार उनके संपर्क में हैं. पाकिस्तानी तालिबान ने यह भी कहा कि आंतकियों को ये हिदायत दी गई थी कि वे छोटे बच्चों को न मारें. अजीब बात है कि बड़ों को ढूंढने वह स्कूलों में जाते हैं. जब बच्चों को नहीं मारना था तो स्कूल में ये आतंकी क्या करने करने गये थे?

पाकिस्तान में इस हादसे को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है. पाकिस्तान सरकार की तरफ से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बातें हो रही हैं. नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान द्वारा स्कूल पर हमला करने का यह कोई पहला वाकया नहीं है. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा स्कूलों पर हमले हो चुके हैं. सैकड़ों बच्चे और बच्चियों की मौत पहले भी हो चुकी है. लेकिन पाकिस्तान में आतंकी संगठन का वर्चस्व तब भी कायम था और आज भी कायम है. पेशावर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है क्या पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो पाएगा? क्या पाकिस्तान में फल–फूल रहे आतंकी संगठनों का खात्मा हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को पाकिस्तानी सरजमीं से बाहर फेंकने में कामयाब हो पायेगी? या यह घटना भी पिछले हजारों हमलों की तरह भुला दी जायेगी? ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 06 अंक 43
दिल्ली, 29 दिसंबर 2014–04 जनवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

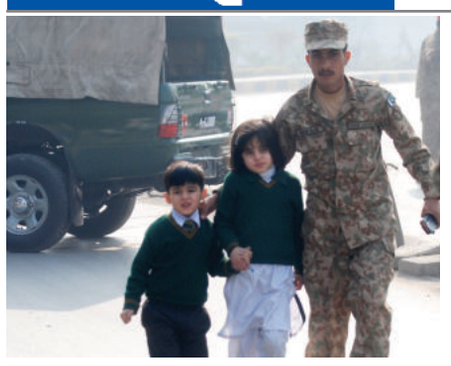

> पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार एक कमज़ोर सरकार है. सेना और आईएसआई इसकी पकड़ से बाहर हैं. उसे इस बात का डर है कि अगर आतंकियों और इस्लाम के नाम पर ज़हर घोलने वालों के ख़िलाफ़ वह कोई क़दम उठाती है तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे. नवाज शरीफ पंजाब से हैं और उनकी पार्टी पंजाबियों की पार्टी मानी जाती है. पाकिस्तान की राजनीति पंजाबियत और इस्लाम की दो धुरियों के इर्द–गिर्द घूमती है. पाकिस्तान में सेना हो, व्यापार हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सभी पर पंजाबियों का क़ब्ज़ा है. पाकिस्तान में चल रहे अलग–अलग आन्दोलन, दरअसल पंजाबियों के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है.

आतंकवाद से पाकिस्तान नहीं लड़ सकता

मनीष कुमार

पेशावर में बच्चों की निर्मम हत्या के एक दिन बाद 26/11 हमले के मास्टर माइंड ज़की–उर–रहमान–लखवी को जमानत मिलने से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है. पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बयान ने पाकिस्तान की हकीकत को उजागर कर दिया. साथ ही जब घोषित आतंकवादी हाफिज सईद ने सरेआम टीवी पर पेशावर हमले में भारत का हाथ होने वाला बयान दिया तो यह बात तय हो गई कि इतने बच्चों की हत्या के बाद पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ लड़ाई बेमानी है. जिस देश में आतंकियों के सरगना को वीआईपी का दर्जा मिला हो, वो आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है? जिस देश में आतंकी संगठनों को सरकार के पैसे से पाला–पोसा जाता हो, वो आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है? जो देश दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह देता हो, वह देश आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है? जिस देश की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती हो, वह देश आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है? दरअसल, पाकिस्तान अपने ही विरोधाभास का शिकार बन गया है. पाकिस्तान आतंकवाद से क्यों नहीं लड़ सकता है, इसे समझना जरूरी है...

सबसे पहले मुंबई हमलों के मास्टर माइंड जकी–उर–रहमान लखवी की करते हैं. वह रावलपिंडी की जेल में बंद है. वैसे तो वह कहने को जेल में बंद था लेकिन वहां उसके पास हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं. जेल में रहते हुए उसके पास कई फोन थे, टीवी पर खबरें देखने को मिलती थीं. अपने दोस्तों और आतंकियों से मुलाकात करने की छूट थी. और तो और जेल में रहते हुए वह एक पुत्र का पिता भी बना. लखवी की कहानी पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के आतंकियों से प्रेम का उदाहरण है. लखवी आतंकियों का सरगना है. उसने जेल में रहते हुए सरकारी वकील की हत्या करवा दी थी, जो उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा था. आईएसआई ने भविष्य में उठने वाले सवालों को आंकते हुए उसे जेल से बाहर भेजने की योजना बनाई थी. आईएसआई ने यह भांप लिया कि आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होगी, उसमें मुंबई धमाकों के गुनाहगारों और दाउद इब्राहिम को भारत के सुपुर्द करने की मांग उठेगी. यही वजह है कि लखवी को जमानत दी गई. आईएसआई ने सरकारी वकील को भी पेश नहीं होने दिया. भारत ने इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया. पाकिस्तान की जनता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान की सरकार को लखवी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी. सवाल यह है कि सेना और आईएसआई के विरोध के बावजूद क्या पाकिस्तान सरकार आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर पायेगी?

पेशावर हमला पाकिस्तान के लिए अभिशाप और वरदान दोनों है. पाकिस्तान के पास यह मौका है कि जनता के साथ मिलकर आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा कर दे तो यह घटना पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हो सकती है नहीं तो यह एक ऐसा अभिशाप होगी जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित पाकिस्तान नहीं बना सके. सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जनता आतंकवाद से ऊब गई है. वह चाहती है कि पाकिस्तान की धरती से आतंक का नामो–निशान मिट जायेगा. लेकिन हकीकत में जिन्हें आतंकवाद से लड़ना है वे दुविधा में हैं. यह दुविधा इसलिए है क्योंकि पेशावर हमले से पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा खुलकर सबके सामने आ गया है. एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जिसके ऊपर जनता और अंतरराष्ट्रीय दबाव है कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन वह लाचार है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जो कि दुविधा में है, क्योंकि वह पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकती है लेकिन कश्मीर और अफगानिस्तान में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. पाकिस्तानी सेना अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान का फर्क ढूंढने में लगी है. तीसरा पहलू पाकिस्तान की आईएसआई है जो स्पष्ट रूप से आंतकी संगठनों को बचाने में लगी है. 140 बच्चों की मौत के बाद भी जिस देश में आतंक और हिंसा के खिलाफ लड़ने पर कन्फ्यूजन हो, तो यह मान लेना चाहिए कि वह देश आतंकवादियों से नहीं लड़ सकता है. पाकिस्तान की सरकार की क्या मजबूरी है? सेना क्यों दुविधा में है और आईएसआई का क्या गेम प्लान है? इसे समझना जरूरी है.

पाकिस्तान में सत्ता के तीन ध्रुव हैं. इसमें सबसे ताकतवर पाकिस्तानी सेना है. आतंकवाद, विदेश नीति, आर्थिक नीति और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की रजामंदी के बगैर नहीं लिया जा सकता है. पाकिस्तान की सेना के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है. यह षडयंत्र रचने और आंतक फैलाने में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है. आईएसआई ही पाकिस्तान की नीतियों को सफल या विफल करती है. यह खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों की देखरेख करती है. भारत में जितने भी धमाके होते हैं या फिर जितने भी आंतकवादी सक्रिय हैं उनके तार आईएसआई से जुड़े हैं. आईएसआई इतनी शक्तिशाली है कि यह पाकिस्तान की सरकार के अस्तित्व को तय करने की ताकत रखती है. पाकिस्तान की मीडिया आईएसआई की कठपुतली है. जो मीडिया हाउस उसके खिलाफ जाने का हिम्मत जुटाता है, उसे आईएसआई तबाह कर देती है और पाकिस्तान में कोई आवाज भी नहीं उठती है. आईएसआई, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के आंतकी संगठनों के बीच एक सूत्र का काम करती है. यही वजह है कि पेशावर में हुए हमले के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया. तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की सरकार है जिसकी कोई नहीं सुनता. यह आर्मी और आईएसआई पर निर्भर सरकार है. पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई एक साथ यह फैसला करें कि आतंकवाद को खत्म करना है अन्यथा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कितनी भी कोशिश कर लें पाकिस्तान में आतंकवादी सुरक्षित ही रहेंगे.

आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है. यह सर्वशक्तिमान है. इसके आगे प्रजातांत्रिक सरकार की भी नहीं चलती. 1948 में इसे पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया था. यह उस वक्त सेना की खुफिया एजेंसी थी. इसकी ताकत में तब इजाफा हुआ जब पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल जिया उल हक़ का कब्जा हो गया. तब से यह दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बन गई, जिसका काम आंतकवादी तैयार करना और दुनिया

पेशावर हमला पाकिस्तान के लिए एक अभिशाप और वरदान दोनों है. पाकिस्तान के पास यह मौका है कि जनता के साथ मिल कर आंतकवाद को पूर्ण रूप से खत्म कर दे तो यह घटना पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हो सकती है नहीं तो यह एक ऐसा अभिशाप होगी जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित पाकिस्तान नहीं बना सके. सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जनता आंतकवाद से ऊब गई है.

के देशों में आतंक का निर्यात करना हो गया है. पिछले कई दशकों से पाकिस्तान में जितने भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बने वो आईएसआई की देखरेख में बनाये गए. यह पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम करती है. यह शायद दुनिया की अकेली एजेंसी है जिसके सर्वोच्च अधिकारी सीधे आर्मी से नियुक्त होते हैं. सेना का लेफ्टिनेंट जनरल ही आईएसआई का मुखिया होता है. आईएसआई को सरकार के बजट से पैसा मिलता है. साथ ही इसे सेना से अन–एकाउंटेड पैसा भी मिलता है. दरअसल, सच्चाई यह है कि आईएसआई साल भर में कितना पैसा खर्च करती है, कहां करती है, कैसे करती है, इसका पता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है. इससे भी गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत भी नहीं है कि वो इस खुफिया एजेंसी पर लगाम लगा सकें. कश्मीर हो या अफगानिस्तान, यहां जितने भी आतंकी संगठन हैं या फिर आतंकी संगठनों के समर्थक हैं वे सभी आईएसआई से जुड़े हैं. भारत में पिछले दो दशकों में जितने भी बम धमाके हुए, उनमें आईएसआई का हाथ रहा है.

जनरल जिया–उल–हक़ के जमाने से पाकिस्तान के समाज, राज्य और यहां तक की सेना का तालिबानीकरण होने लगा. जनरल जिया ने आईएसआई के जरिए पाकिस्तान में विरोधियों का मुंह बंद कराया और इसी के जरिये पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता को फैलाया, जिसने आगे चलकर आतंकवाद का रूप ले लिया. अफगानिस्तान में जनरल जिया ने अमेरिकी विदेश नीति के साथ धार्मिक कट्टरता का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया, जिससे

पाकिस्तान आज तक बेसुध पड़ा है. आईएसआई को इतना ताकतवर बनाया गया कि यह एजेंसी अफगानिस्तान और भारत को तबाह करने की तैयारी करने लगी. अफगानिस्तान में जहां आईएसआई ने मुजाहिद्दीनों की फौज बना कर रूस से लड़ाई लड़ी. वहीं भारत को तबाह करने के लिए पंजाब और कश्मीर में आंतकवादी संगठनों को तैयार किया और हजारों भारतीयों का खून बहाया. यह आईएसआई की देन है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद की राजधानी बन गया. विकीलीक्स ने कई बार यह साबित किया है कि कैसे दुनिया भर के आंतकी संगठनों के तार आईएसआई से जुड़े हैं. यह आतंक का ट्रेनिंग कैंप चलाती है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग देती है और उन्हें दुनिया भर में निर्यात करती है. आईएसआई आतंकवादी पैदा करने की मशीन है. पाकिस्तान की जनता और सरकार को इस बात पर आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है. पाकिस्तान को अगर आतंकवाद से लड़ना है तो आईएसआई को या तो खत्म करना होगा या आईएसआई की शक्तिओं को कम करना होगा. लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान सरकार यह काम करने में असमर्थ है. जब तक पाकिस्तान में आईएसआई शक्तिशाली रहेगा, तब तक पाकिस्तान से आंतकवाद के खिलाफ किसी तरह की निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि हमला कैसा भी हो, बच्चे मरें या औरतों को जिंदा जलाया जाये, आईएसआई आंतकवादी संगठनों का बाल भी बांका नहीं होने देगी.

पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार एक कमज़ोर सरकार है. सेना और आईएसआई इसकी पकड़ से बाहर हैं. उसे इस बात का डर है कि अगर आतंकियों और इस्लाम के नाम पर ज़हर घोलने वालों के ख़िलाफ़ वह कोई क़दम उठाती है तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे. नवाज शरीफ पंजाब से हैं और उनकी पार्टी पंजाबियों की पार्टी मानी जाती है. पाकिस्तान की राजनीति पंजाबियत और इस्लाम की दो धुरियों के इर्द–गिर्द घूमती है. पाकिस्तान में सेना हो, व्यापार हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सभी पर पंजाबियों का क़ब्ज़ा है. पाकिस्तान में चल रहे अलग–अलग आन्दोलन, दरअसल पंजाबियों के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है. जैसे कि बलूचिस्तान के लोग अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ़ पंजाबियों के हित में सोचती है. पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और संगठित क्षेत्रों पर पंजाबियों का एकाधिकार है, तो पाकिस्तान के समाज पर मौलाना और मौलवियों की मज़बूत पकड़ है.

पाकिस्तान में धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की अपनी अलग ताक़त है. इन नेताओं को जनरल ज़िया के शासनकाल के दौरान हर तरह की मदद दी गई. वे ताक़तवर बन गए. इनमें हाफ़िज सईद का नाम सबसे ऊपर है. हाफ़िज मोहम्मद सईद जमात–उद–दवा का आमिर यानी अध्यक्ष है. हाफ़िज सईद का आतंक से पुराना रिश्ता है. 1990 में सईद ने लश्कर–ए–तैय्यबा का गठन किया. लश्कर सऊदी के पैसे और आईएसआई के संरक्षण में चलने वाला संगठन है. जब उस पर प्रतिबंध लगा तो उसने जमात–उद–दावा के नाम से अपना संगठन चलाना शुरू कर दिया. हैरानी की बात यह है कि इस संगठन का आतंकियों के साथ रिश्ता है, इसके बावजूद जमात–उद–दावा को एक एनजीओ मान कर पाकिस्तान की सरकार ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के नाम पर उसे करोड़ों रुपये दिये. पाकिस्तान में मीडिया रिपोर्ट छापती रही, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी चेतावनी देते रहे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने जमात–उद–दावा के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की. हाफिज सईद की न सिर्फ़ पाकिस्तान के सरकारी तंत्र पर पकड़ है, बल्कि वह उन्हें इस्तेमाल करना भी जानता है. हाफ़िज़ सईद का एक साथ पंजाबी और जिहादी होना ही पाकिस्तान की सरकार के लिए दुविधा पैदा करता है. यही वजह है कि हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी. हाफ़िज़ सईद को आईएसआई का समर्थन प्राप्त है. पाकिस्तानी सेना से उसकी सांठगांठ है. दरअसल, आईएसआई और सेना के साथ मिलकर हाफ़िज़ सईद और लखवी ने मुंबई हमले को अंजाम दिया था.

अगर कोई अपने घर में जहरीले सांपों को पाले और यह सोचे कि सांप सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा यह उस व्यक्ति की मूर्खता है. पिछले कई दशकों से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईराक, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, रूस और अफ्रीका के कई देशों में आतंकवादियों की सप्लाई करता रहा है. पाकिस्तान आतंकवाद की राजधानी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आंतकी संगठनों को ट्रेनिंग देती रही हैं. पाकिस्तान और दुनिया भर के कई जानकारों ने इस पर कई किताबें भी लिखीं, कई रिपोर्टें भी आईं और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल भी उठे, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा. दरअसल, पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसने आंतकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाया है. अगर पाकिस्तान के अंदर आंतकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कट्टरवादी संगठन इसका विरोध करेंगे. कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठायेगा. रही बात सेना की तो वह पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकती है लेकिन दूसरे आंतकी और कट्टरवादी संगठनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी. ये सब आर्मी द्वारा ही तैयार किए गए दस्ते हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना कश्मीर और अफगानिस्तान में करती है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही इन आंतकी संगठनों की जननी है. ऐसे में वह हर कदम का विरोध करेगी जो आतंकी संगठनों के लिए नुक़सानदेह होगा. पाकिस्तान में एक लाचार सरकार है. आतंकियों की सहयोगी खुफिया एजेंसी और सेना है. ऐसे में आंतकवाद के खिलाफ किसी निर्णायक लड़ाई की उम्मीद करना बेमानी है. रही बात पेशावर हादसे की तो जिस तरह पिछले 1000 हमलों को पाकिस्तान ने भुला दिया, उसी तरह इसे भी लोग कुछ दिन बाद भूल ही जायेंगे. ■

manishbph244@gmail.com

आम आदमी के खास काम

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चिवांग नारफेल

कृत्रिम ग्लेशियर बना कर बुझाई लोगों की प्यास

79 साल के चिवांग नारफेल एक अवकाशप्राप्त सिविल इंजीनियर हैं. 1966 में जब वे लद्दाख के जांसकार में काम कर रहे थे तब उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को अपने काम में मदद के लिए ट्रेनिंग दी. उनकी मामूली ट्रेनिंग से गांव के लोग कुशल मिस्त्री बन गए. नारफेल को यह देख कर अच्छा लगा. बाद में उन्होंने देखा कि गांव के लोगों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. नारफेल ने तब इस समस्या के समाधान के लिए खुद को समर्पित कर दिया. आज उन्हें आईस मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. नारफेल ने लद्दाख में दस कृत्रिम ग्लेशियर बना कर लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाई.■

बिनालक्ष्मी नेप्रम

मणिपुर की विधवाओं के लिए जीने की आशा

नेप्रम ने अपना जीवन मणिपुर में फैली हिंसा की वजह से विधवा बनी सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए झोंक दिया. नेप्रम ऐसी महिलाओं को अपना छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करने में मदद की. आसान लोन दिला कर सिलाई मशीन जैसे उपकरण के सहारे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की. इसके बाद उन महिलाओं का बैंक खाता भी खुलवाया. नेप्रम ने इन विधवाओं को दोबारा जीने का साहस दिया. ■

जाधव प्यांग

1 आदमी ने बना दिया 1360 एकड़ का जंगल

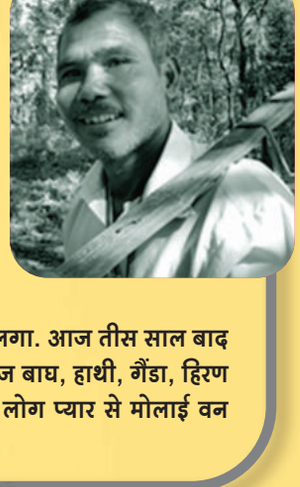

तीस साल पहले एक युवा ने पहला पेड़ लगाया था. तीस साल बाद वह एक पेड़ 1360 एकड़ के जंगल में फैल चुका है. असम के जोरहट में जब प्यांग ने बाढ़ से तबाह हुए इलाके में भीषण गर्मी से सांपों को मरते हुए देखा तो उसके मन में इन जीवों के लिए कुछ करने का ख्याल आया. प्यांग ने वन विभाग से मिल कर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे (जोरहट में) पेड़ लगाने में मदद की अपील की. लेकिन वन विभाग ने प्यांग को कहा कि तुम खुद पेड़ लगाओ, हम कोई मदद नहीं करेंगे. वन विभाग के इस रवैये से भी प्यांग का हौसला नहीं टूटा. प्यांग अपना गांव छोड़ कर इसी इलाके में रहने लगे. पहले बांस का पेड़ लगाना शुरू किया. बाद में हर तरह के पेड़ लगाए. देखते ही देखते वह इलाका पेड़ों से घिरने लगा. आज तीस साल बाद यहां पर 1360 एकड़ का जंगल बन चुका है. इस जंगल में आज बाघ, हाथी, गैंडा, हिरण और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी रहते है. इस जंगल को यहां के लोग प्यार से मोलाई वन कहते हैं. जाधव प्यांग का घर का नाम मोलाई ही है.■

सिंधुताई सापकाल

अनाथ बच्चों की मां

महाराष्ट्र की 68 साल की सिन्धुताई उत्साह से लबरेज हैं. उन्हें लोग अनाथ बच्चों की मां के नाम से जानते हैं. उनके आंचल में एक-दो नहीं बल्कि हजार बच्चे दुलार पाते हैं. महज 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह एक अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया. चौथे दर्जे तक पढ़ाई पूरी हो चुकी थी. कुछ सालों बाद आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो ससुराल वालों का विरोध सामने आया और उन्हें घर से निकाल दिया गया. तब वो गर्भवती थीं. कुछ महीनों बाद तबेले में एक बेटी को जन्म दिया और अगले तीन वर्ष ट्रेनों में भीख मांगकर गुजारा करते हुए बीते. संघर्ष के दिनों में उन्हें बेटी को एक अनाथाश्रम में रखने की नौबत आ पड़ी. बेटी को छोड़ने के बाद रेलवे स्टेशन पर जब एक निराश्रित बच्चा पड़ा मिला तो उनके मन में विचार आया कि ऐसे हजारों बच्चे और भी हैं. उनका क्या होगा? इसके बाद शुरू हुआ उनका नया जीवन. उनका एक प्रयास आज महाराष्ट्र की 5 बड़ी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है. इन संस्थाओं में जहां 1 हजार अनाथ बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, वहीं विधवा व परित्यक्ताओं को भी इनमें आसरा मिला है. ताई सबकी मां हैं और सभी के पालन-पोषण व शिक्षा-चिकित्सा का भार उन्हीं के कंधों पर है. ताई आज भी अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं चूकतीं. वे कहती हैं कि मांगकर यदि इतने बच्चों का लालन-पालन हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं. रेलवे स्टेशन पर मिला वो पहला बच्चा आज उनका सबसे बड़ा बेटा है और पांचों आश्रमों का प्रबंधन उसके कंधों पर हैं. अपनी 272 बेटियों का वे धूमधाम से विवाह कर चुकी हैं और परिवार में 36 बहुएं भी आ चुकी हैं.■

डॉ. मापुस्कर

स्वच्छ भारत के लिए 50 साल से प्रयासरत

डॉ. मापुस्कर पिछले 50 सालों से ग्रामीण स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र के पुणे के देहु गांव से इनका काम शुरु हुआ. डॉ. मापुस्कर को पहली नौकरी स्वास्थ्य निदेशालय में मिली और पहली पोस्टिंग हुई देहु गांव में. वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही शौचालय नहीं है. सो सबसे पहले उन्होंने अपने लिए शौचालय बनवाया. दवाईयों के कार्टून से शौचालय की दीवार बनाई. धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वो जिस भी बिमारी का इलाज कर रहे है वो सब की सब स्वच्छता से जुडी हुई हैं. उन्होंने लोगों से सफाई के महत्व के बारे में बात करनी शुरू की. 1963 में ग्राम सभा के फंड से उन्होंने एक सर्वे किया और पाया कि गांव के 86 फीसदी घर संक्रामक बीमारी से संक्रमित थे. तत्काल उन्होंने दवा दे कर गाववालों का इलाज किया लेकिन यह भी समझाया कि एक बार में खर्च आता है एक हजार रूपये और ऐसा हर तीन महीने पर करना पड़ेगा. इससे अच्छा है कि घर में 400 रूपये में एक शौचालय बनवा लिया जाए. लोगों को शौचालय के महत्व के बारे में समझाने में थोड़ा वक्त लगा. उन्होंने बडे स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया 1980 तक गांव के 90 फीसदी घरों में शौचालय बन चुका था. 1990 में डॉ. मापुस्कर ने बायो गैस शौचालय बनाया. इससे खाद और गैस भी बनती था जिससे एक परिवार को सात सौ रूपये की कमाई भी होती थी. डॉ. मापुस्कर को इस काम के लिए राष्ट्रपति से 2007 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है.■

राजेश कुमार शर्मा

फ्लाईओवर को ही बना दिया स्कूल

दिल्ली के शकरपुर में एक किराना दुकान चलाने वाले राजेश कुमार शर्मा रोजाना दो घंटे मजदूरों और रिक्शा चलाने वाले के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं. उनका यह स्कूल एक मेट्रो पुल के नीचे चलता है. उन्होंने यह स्कूल लगभग 140 छात्रों के साथ शुरू किया था और आज उनमें से 70 छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिला पा चुके हैं. राजेश रोजाना दो घंटे अपनी दुकान अपने छोटे भाई पर छोड़कर बच्चों को यहां पढ़ाने आते हैं. राजेश कुमार का उद्देश्य होता है कि उनके स्कूल के बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला हो जाये. शोषित गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए विशेष रूप से तैयार करते हैं. उन्होंने यह स्कूल लगभग 140 छात्रों के साथ शुरू किया था और आज उनमें से 70 छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिला पा चुके हैं. राजेश कुमार शर्मा कहते हैं कि कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल के लिए नहीं भेजना चाहते थे. उनका मानना था की यह बच्चे पढ़ाई न करके अगर कुछ काम करें तो परिवार की आमदनी में इजाफा होगा. राजेश कुमार गर्व के साथ कहते हैं की उन्होंने बच्चों के माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए राजी कर लिया है.■

बाबर अली

सबसे युवा हेडमास्टर

बाबर अली ने अपने गांव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का जिम्मा उठा रखा है. उनके सामने अच्छे-अच्छे स्कूलों के हेडमास्टर भी फेल हैं. सुबह की शिफ्ट में अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद बाबर घर आकर गांव के हर बच्चे को शिक्षित करने में लग जाते हैं. बाबर अली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने घर को ही स्कूल में तब्दील करके रख दिया और उसे आनंद शिक्षा निकेतन नाम दिया है. इस स्कूल में बाबर गांव के सारे बच्चे, लगभग 800, को शिक्षा देते हैं. बाबर के इस स्कूल से प्रभावित हो कर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस अनोखे स्कूल को मान्यता दे दी है. बाबर अली को दुनिया का सबसे युवा हेडमास्टर कहा जाता है.■

अरुणिमा सिन्हा

अपंगता जिनकी ताकत बन गई और एवरेस्ट जिनसे हार गया

अरूणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की निवासी हैं. वह 12 अप्रैल 2011 में जब लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं, उस दौरान ट्रेन में चेन खींचे जाने का विरोध करने पर गुंडो ने उन्हें पद्मावति एक्सप्रेस से नीचे फेंक दिया था. वह एक चलती हुई ट्रेन से टकराईं और बुरी तरह घायल हो गईं थीं. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसका बायां पैर काट दिया गया था. लेकिन अरूणिमा का जीवन इससे खत्म नहीं हुआ. उनका हौसला देखिए कि पांव कटने के बाद भी उन्होंने दुनिया की सबसे उंची चोटी पर जाने का निर्णय लिया. अरुणिमा सिन्हा ने देश का सिर शान से ऊंचा कर दिया है. उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया और इसी के साथ अपन पैर गंवाकर एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं.■

सब्बाह हाजी

लाखों की नौकरी छोड़ कश्मीर में स्कूल चला रही हैं

दुबई में जन्मी सब्बाह हाजी ने सुनहरे करियर को छोड़ अपने गांव में ही स्कूल खोलने का फैसला क्यों लिया? दुबई में उसके पिता एक शिपिंग कंपनी में मैनेजर थे.1997 में उसका परिवार बेंगलूरु आ गया. 2009 में जब वो डोडा जिले में अपने पैतृक गांव ब्रेसवाना आई तो देखा कि यहां के दो पीढ़ी के लोगों ने अब तक शिक्षा नहीं ली है. ऐसा आतंकवाद और सरकारी उपेक्षा के कारण था. आतंकवाद की वजह से तब सरकारी स्कूल बंद थे. बाद में भी स्थिति बेहतर नहीं हुई. सब्बाह ने एक स्कूल खोलने की सोची. मई, 2009 में उसने गांव में अपनी पैतृक जमीन पर हाजी पब्लिक स्कूल खोला. स्कूल में दो कमरे थे और अब इसमें छह कमरे हैं. यहां चौथी कक्षा तक पढ़ाई होती है. स्कूल में इस समय 150 छात्र और 15 शिक्षक हैं.■

डॉ. लक्ष्मी गौतम

वृन्दावन की विधवाओं का सहारा

वृन्दावन में देश भर से विधवाएं आ कर रहती है. उनकी हालत इतनी दयनीय है कि सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है. डॉ. लक्ष्मी गौतम वृन्दावन में ही प्रोफेसर है. डॉ. लक्ष्मी गौतम इन विधवाओं की जिन्दगी को तो गरिमामय बनाने का काम कर ही रही हैं साथ ही उनके अंतिम संस्कार का भी प्रबन्ध करती हैं. वो इन विधवाओं के लिए खाना, कपड़े और दवाईयों का भी प्रबंध करती हैं. उन्हें भावनात्मक सहारा और पेंशन मिल सके, इसकी जिम्मेदारी भी डॉ. लक्ष्मी गौतम निभाती है. सुबह-सुबह डॉ. लक्ष्मी सड़क किनारे घूमकर ऐसी विधवा महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए उठवाती हैं जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता. अब तक ऐसी 500 विधवाओं का अंतिम संस्कार वे करवा चुकी हैं.■

2014 की प्रमुख घटनाएं

प्रत्येक वर्ष की तरह साल 2014 कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाएगा. यह साल भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ. राजनीतिक मोर्चे पर जहां लगभग 25 सालों बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली वहीं सामाजिक कार्यों को लेकर देश के समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला. खेलों की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने खेलों को अलविदा कह दिया. इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं...

1 जनवरी: अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत ने घोटाले का आरोप झेल रहे ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड (एडब्लूआईएल) के साथ 3,726 करोड़ रुपये का वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा रद्द कर दिया. इस सौदे के मुताबिक कंपनी को 12 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने थे. जिनमें से कंपनी 2 हेलीकॉप्टर पहले ही भारत के हवाले कर चुकी थी.

1 जनवरी: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल अस्तित्व में आ गई. इस बिल को राज्यसभा में 17 दिसंबर, 2013 को पारित किया गया था. इसके अगले ही दिन लोकसभा ने भी इसे परित कर दिया था.

2 जनवरी : दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध किया. केजरीवाल ने 28 दिसम्बर 2013 को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.विधान सभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.

5 जनवरी : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी डी-5 का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ सफल प्रक्षेपण किया. इसके साथ ही अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला छठवां देश बन गया.

6 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया. कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने पिछले साल नवंबर में जस्टिस गांगुली पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. 2 जनवरी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की राय भेजे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

7 जनवरी : भारत ने चांदीपुर प्रक्षेपण रेंज से पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया. .

9 जनवरी : भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े, जिनकी गिरफ्तारी ने भारत-अमेरिका के राजनयिक रिश्तों में तनातनी पैदा कर दी थी, को राजनयिक संरक्षण के तहत भारत भेज दिया गया. देवयानी पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नौकरानी के वर्क वीजा के सिलसिले में ग़लत बयानी से काम लिया था.

10 जन्वरी 2014 : गुजरात के आनंद मे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन युवा भारत को शिक्षित करने (टुवर्ड्स एजुकेटिंग यंग इंडिया) के उद्देश्य से हुआ.

15 जनवरी : अमेरिका ने 1.5 लाख डॉलर कीमत की 11वीं और 12वी शताब्दी की मूर्तियां भारत के हवाले कीं. यह मूर्तिया भारतीय मंदिरों से चोरी करके अमेरिका लाई गई थीं.

26 जनवरी : गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे थे. वे तीन दिन की सरकारी यात्रा पर भारत आये थे.

29 जनवरी : नई दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में अरुणाचल परदेश के विधायक के पुत्र निदो तानिया (19) को उसकी पोशाक को लेकर हुए विवाद के बाद दो दुकानदारों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया जिसके बाद यहां पूर्वोत्तर के छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए धरना-प्रदर्शन किया.

30 जनवरी : ई-प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत कोच्ची मे हुई. इस सम्मेलन में सरकार के तरीकों व प्रकृति दोनों ही क्षेत्र की चुनौतियों व उपलब्धियों को सुधारने के लिए ध्यान आकर्षित किया गया.

11 फरवरी : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का विरोध कर रहे सीमांध्र क्षेत्र के 6 कांग्रेसी सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया.

12 फरवरी : दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, भूतपूर्व मंत्री मुरली देवड़ा, हाइड्रोकार्बन्स के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल वी के सिब्बल पर प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करने और केजी-डी 6 बेसिन में कथित मिलीभगत के आरोप में एफ़आईआर दर्ज कराई.

13 फरवरी : भारत में अमेरिका की राजदूत नैंसी पॉवेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से गांधीनगर में मुलाक़ात की. 2005 में अमेरिका द्वारा मोदी को राजनयिक वीजा दिए जाने से इंकार के बाद इस तरह की पहली मुलाक़ात थी. सितंबर 2013 में ही भाजपा ने मोदी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था. हालांकि अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सफाई दी थी कि मोदी पर वीजा की पाबन्दी जरी रहेगी.

14 फरवरी : अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया. उनका कहना था कि विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश करने में नाकाम रहने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया था. उनकी सरकार देश की सबसे कम दिन चलने वाली सरकारों में से एक थी. यह सरकार केवल 49 दिन तक चली. केंद्र सरकार की सहमति के बाद 17 फ़रवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

17 फ़रवरी: केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में शोर-शराबे के बीच वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. यह यूपीए-2 का आखिरी बजट था.

19 फ़रवरी : राज्य सभा ने स्ट्रीट वेंडर्स बिल 2014 पास कर दिया, लोक सभा ने 6 सितंबर 2013 को इस बिल को पास कर दिया था.

20 फ़रवरी : राज्य सभा ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य बनाने को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया. लोकसभा पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी थी.

28 फ़रवरी : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर लिया. अपने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने में कथित रूप से असफल रहने से जुड़े मामले में अदालत में पेश नहीं होने के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

11 मार्च : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 11 जवानों समेत 15 लोग मारे गए.

20 मार्च : वरिष्ठ अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 99 वर्ष की उम्र में निधन.

27 मार्च : श्रीलंका की नौसेना ने 24 भारतीय मछुवारों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया.

27 मार्च : डब्लूएचओ भारत और समूचे दक्षिण-पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया.

4 अप्रैल : भारत ने अपना दूसरा नेविगेशन सेटेलाइट आई आर एन एस एस -1बी को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया.

7 अप्रैल : 16 वीं लोक सभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ. नौ चरणों में होने वाले ये चुनाव 12 मई को समाप्त हुए.

7 अप्रैल : औरंगाबाद (बिहार) में एक बम धमाके में सीआरपीएफ़ के 2 जवान शहीद हो गए.

12 अप्रैल : छत्तीसगढ़ के बस्तर और बीजापुर जिलों में सात चुनाव कर्मियों के और पांच सीआरपीएफ़ जवानों समेत 14 लोग मारे गए.

16 अप्रैल : सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक बराबरी का हक है.

17 अप्रैल : रोबिन के. धवन को भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ़ नवल स्टाफ नियुक्त किया गया.

24 अप्रैल : झारखंड के दुमका जिले में माओवादियों ने दो चुनाव, पांच सुरक्षा कर्मियों समेत छह लोगों की हत्या कर दी.

16 मई : 16वीं लोक सभा चुनाव के नतीजे घोषित. एनडीए गठबंधन ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए लोक सभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया. 1984 लोक सभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला हो. 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी. लेकिन इस चुनाव में सत्ताधारी यूपीए गठबंधन को केवल 61 सीटें मिलीं जबकि पिछली लोकसभा में उनके 218 संसद थे. कांग्रेस पार्टी ने भी अब तक का अपना सबसे ख़राब प्रदर्शन किया. पार्टी को केवल 45 सीटें मिलीं.

26 मई : नरेन्द्र मोदी ने अन्य मंत्रियों के साथ देश के 15 वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया. 16 वीं लोक सभा के नौवें चरण का मतदान संपन्न हुआ. ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ समेत सभी सार्क देशों को राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे.

2 जून : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के मुताबिक आंध्रप्रदेश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया. इसके बाद तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया है. अगले 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की राजधानी हैदराबाद बना रहेगा.

3 जून : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का नई दिल्ली में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया.

4. जून : पुलिस ने पूर्वी राज्यों से तस्करी कर केरल ले जा रहे 500 से अधिक बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया.

8 जून : हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर आये हैदराबाद के 24 छात्र व्यास नदी में डूब गए. यह घटना मंडी जिले के थालौत में घटी, जहां एक हाइड्रोपावर प्लांट से बिना किसी चेतवनी के पानी छोड़ दिया गया था.

30 जून : इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-सी23 समेत पांच विदेशी उपग्रह कक्षा में स्थापित किया.

5 जुलाई : इराक में आईएसआईएस आतंकवादियों की गिरफ्त से निकली 46 भारतीय नर्सों को लेकर एयर इंडिया का विमान कोच्चि पहुंचा. 46 नर्सों की सकुशल वापसी पर सुकून व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया.

10 जुलाई : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में नवनिर्वाचित एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया.

18 जुलाई : ओड़िशा के गंजम जिले के बरहमपुर में सुरक्षाबलों ने शीर्ष माओवादी कमांडर सब्यसाची पांडा को गिरफ्तार कर लिया. राज्य पुलिस की माओवादियों के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया.

18 जुलाई : लोक सभा चुनाव में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ख़राब प्रदर्शन की नैतिक ज़िम्मेदारी ले ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया. 20 जुलाई को जीतन राम मांझी नए मुख्मंत्री बने.

3 अगस्त : सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन एसके जैन को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया. उन पर बहुचर्चित कोयला घोटाले में आरोपी दो कंपनियों से 60 लाख रुपये की घूस लेने का आरोप था.

16 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेश निर्मित सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज तक भारत में रक्षा के क्षेत्र में देश में जितने भी निर्माण हुए हैं, उनमें आईएनएस कोलकाता सबसे बड़ा निर्माण है.

22 अगस्त : प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास यूआर अनंतमूर्ति का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया. अनंतमूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने बयान की वजह से चर्चा में थे.

25 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2011 तक के कुल 218 कोल ब्लॉक में से 4 को छोड़कर बाकी 214 कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द कर दिया. जिन कंपनियों के आवंटन रद्द नहीं हुए वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों हैं.

25 अगस्त : लोक सभा में हार के बाद एक साथ आये लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार ने 10 विधान सभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में से 6 पर जीत दर्ज की.

28 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जन-धन योजना की शुरुआत की. इस अवसर पर एक दिन में 1.5 करोड खाते खोलने और 1.5 लाख लोगों के बीमे का रिकार्ड बना. इस योजना के तहत साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य था.

4-10 सितंबर : जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ यहां बीते करीब छह दशकों में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी. राहत कार्य में असफलता की वजह से राज्य सरकार की बहुत आलोचना हुई. बाढ़ की तबाही की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल दीपावली कश्मीर में मनाने का फैसला किया.

5 सितम्बर : भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को पॉवर जनरेशन के लिए यूरेनियम सप्लाई करेगा.

16 सितम्बर : उत्तर प्रदेश में हुए विधान सभा की 11 और लोक सभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 8 सभा और एक लोकसभा सीट पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया.

24 सितम्बर : इसरो का मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित कर इतिहास रच दिया. भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है

24 सितम्बर : इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक रजत शर्मा वर्ष 2014-2015 के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के नए अध्यक्ष 24 सितंबर 2014 को नियुक्त किए गए. एबीपी न्यूज के अशोक वेंकटरमानी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया.

27 सितम्बर : एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दे दिया.

29 सितम्बर : एआईएडीएमके नेता एवं तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने 29 सितंबर 2014 को चेन्नई में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. उनके साथ उनके कैबिनेट के 32 मंत्रियों ने भी शपथ ली.

30 सितंबर : नासा और इसरो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत धरती की निगरानी करने वाले उपग्रह एनआईएसएआर और भविष्य के मंगल ग्रह मिशन में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे.

2 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया.

10 अक्टूबर : वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की मलाल युसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई.

12 अक्टूबर : चक्रवात हुदहुद ने आँध्रप्रदेश में तबाही मचाई.

8 नवम्बर : छत्तीसगढ़ के विलासपुर नसबंदी शिविर में 11 महिलाओं की ऑपरेशन के बाद कथित लापरवाही से मौत हो गई.

1 दिसम्बर : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों एक हमले में 14 सी आर पी एफ जवानों को शहीद कर दिया.

2 दिसम्बर : महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एआर अंतुले का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.

5 दिसम्बर : जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के एक मिलिट्री कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में 11 सैनिक और पुलिस कर्मी शहीद हो गए.

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सब से लम्बे समय तक मुख्य मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं.

12 दिसम्बर : सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाले के आरोप में पश्चिम बंगाल के परिवहन और खेल मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया.

16 दिसम्बर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेश्वार के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए आतंकी हमले में मारे गए बच्चों के प्रति सवेंदना व्यक्त करते हुए भारतीय स्कूलों में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की.

18 दिसम्बर : 26/11 के मुंबई हमलों के आरोपी ज़किउर रहमान लखवी को पाकिस्तानी अदालत ने ज़मानत दे दी. ■

पटना उच्च न्यायालय में सरकार की किरकिरी तो हुई ही, कुलदीप नारायण प्रकरण राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी आलोचना का कारण बन गया है. सूबे के विपक्षी राजनीतिक दल जीतनराम मांझी सरकार पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त के पक्ष में खड़े हो गए हैं. हालांकि ये दल सामान्य नागरिक सुविधा के फ्रंट पर नगर की बदहाली के लिए दो दिन पहले तक निगम प्रशासन के खिलाफ खड़े थे.

मांझी सरकार की नाक में फंस गए कुलदीप नारायण

कुलदीप नारायण ने कोई पौने दो साल पहले नगर निगम के शीर्ष नौकरशाह का यह पद संभाला था और उन दिनों वे सारे लोग जश्न मना रहे थे जो पिछले कई महीनों से उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं. वस्तुतः कुलदीप ने जैसे ही राजधानी के बिल्डिंग माफिया की ओर नजर डाली कि उन पर हमले आरंभ हो गए और तब से हमले बढ़ते गए. हालत, यह हो गई कि पटना हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कुलदीप के तबादले पर रोक लगा दी. आदेश दिया कि अदालत की अनुमति के बगैर उनको नगर आयुक्त के पद से हटाया नहीं जा सकता है. वस्तुतः गत वर्षों में पटना और इसके आसपास के छोटे-छोटे नगरों- गंगा के पार हाजीपुर, सोनपुर, दिघवारा आदि भी- में राज्य के बड़े-बड़े बिल्डरों ने अपना काम आरंभ किया और बहुमंजिली रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का संजाल तैयार हो गया.

सुकान्त

यह साफ होने में अभी वक्त लगेगा कि बिहार सरकार की नाक कटेगी या पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण का सीना थोड़ा और चौड़ा होगा. इसके साथ यह भी साफ होगा कि अदालत के आदेश से बचने के लिए बाईपास की खोज की सरकार की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने को न्यायपालिका क्या करती है? राज्य सरकार ने श्री नारायण को, सरकारी आदेशों-निर्देशों के पालन व नागरिक सुविधाओं के विकास-विस्तार में उनकी कथित लापरवाही के आरोप में, निलंबित करने का आदेश जारी किया है. चूंकि श्री नारायण को उनके पद से हटाने पर पटना हाइकोर्ट ने रोक लगा रखी थी इसीलिए न्यायालय ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है. असलियत तो यही है कि श्री नारायण अदालत के आदेश के रक्षा-कवच में इस पद पर हैं, जबकि राज्य सरकार किसी भी सूरत में इस पद पर उन्हें देखना नहीं चाहती. अदालत ने कोई एक साल पहले उनके तबादले पर रोक लगा दी थी और उन्हें निगरानी के मामलों, जो मुख्यतः अवैध भवन निर्माण से जुड़े हैं, को निपटाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. इसीलिए अदालत, नौकरशाही और राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी समझ है कि श्री नारायण के तबादले में विफल सत्ता ने उनसे मुक्ति के लिए बाईपास खोज लिया. सामान्य सी बातों को आधार बनाकर बिल्डिंग माफिया के दबाव में उनको निलंबित कर दिया गया. अब हाइकोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला के आने तक श्री नारायण अपने पद पर बने रहेंगे और वे केवल निगरानी के मामलों को देखेंगे. सो, अब राज्य सरकार और कुलदीप नारायण सहित सभी को इस फैसले की प्रतीक्षा है. सरकार की नाक बचेगी कि नारायण का सीना चौड़ा होगा!

कुलदीप नारायण ने कोई पौने दो साल पहले नगर निगम के शीर्ष नौकरशाह का यह पद संभाला था और उन दिनों वे सारे लोग जश्न मना रहे थे जो पिछले कई महीनों से उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं. वस्तुतः कुलदीप नारायण ने जैसे ही राजधानी (बिहार ही कहिए) के बिल्डिंग माफिया की ओर नजर डाली कि उन पर हमले आरंभ हो गए. और तब से हमले बढ़ते गए, उनके स्वरूप बदलते गए. हालत, यह हो गई कि पटना हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उनके के तबादले पर रोक लगा दी. आदेश दिया कि अदालत की अनुमति के बगैर उनको नगर आयुक्त के पद से हटाया नहीं जा सकता है. वस्तुतः गत वर्षों में पटना और इसके आसपास के छोटे-छोटे नगरों, गंगा के पार हाजीपुर, सोनपुर, दिघवारा आदि भी, में राज्य के बड़े-बड़े बिल्डरों ने अपना काम आरंभ किया और बहुमंजिली रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों का संजाल तैयार हो गया. पटना नगर निगम क्षेत्र में तो कोई भी बड़ा भूखंड अब शायद ही हो. भवन निर्माण के सिलसिले में दबंग बिल्डरों ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख (उसमें जाति और धन की भूमिका बड़ी रही है) का जम कर इस्तेमाल किया व नियम-कायदों की जमकर धज्जिया उड़ाई. इतना ही नहीं गंगा की परित्यक्त रेतीली जमीन को भी इन दबंग बिल्डरों ने नहीं बख़्शा. दक्षिण से उत्तर की ओर भागती गंगा की रेतीली जमीन पर शहर के दबंग कब्जा कर अपार्टमेंट खड़े कर रहे हैं. इन दबंग बिल्डरों की कृपा से गंगा की पेट में छह-सात साल के दौरान बहुमंजिली इमारतों का सिलसिला तैयार हो गया है. बाद में एक याचिका के आधार पर इन मकानों व इमारतों के अवैध अतिक्रमण के होने का मामला सामने आया और इससे जुड़े निगरानी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अदालत ने नगर आयुक्त को आदेश दिया. इसी प्रकरण में उनके तबादले पर रोक लगी थी. जांच के सिलसिले में अवैध निर्माण या अतिक्रमण के अब तक कोई साढ़े चार सौ मामले दायर किए गए गए. इनमें से कोई डेड़ सौ मामलों की सुनवाई हो चुकी है और कोई सौ मामलों में नगर आयुक्त का फैसला आ गया है. संयोग से इनमें से काफी संख्या में वैसी बहुमंजली रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें हैं जिनका निर्माण सत्ता की राजनीति से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जुड़े दबंगों ने करवाया है. कुछ तो सत्ताधारी दल के दबंग विधायक के बताए जाते हैं, कुछ में बिल्डिंग-माफिया के संरक्षक राज्य के कुछ बड़े नेताओं का पैसा लगा है. रसूख का अंदाजा लगाने के लिए एक ही उदाहरण काफी होगा. पटना में जदयू के कुख्यात और बाहुबली विधायक ने एक मॉल बनवाया. इसके कुछ हिस्सों के निर्माण पर नगर निगम ने रोक लगाई. रोक के बावजूद पटना के फ्रेजर रोड पर यह मॉल बना, प्रशासन ने निगम के आदेश को लागू कराने की कभी कोई पहल ही नहीं की. यह दबंगई की लंबी कड़ी का एक हिस्सा भर है. विपक्ष भी ऐसे दबंग बिल्डरों से अछूता नहीं है. विपक्ष के कई नेता इस बिल्डिंग सेक्टर के खुले हितैषी हैं. पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ की टिप्पणी है: हम जानते हैं कि यह बिल्डरों के दबाव में लिया गया निर्णय है. दूसरा कारण, यह भी प्रतीत होता है कि अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ विजिलेंस केस के आदेश में सख्ती बरती जा रही है जिससे बिल्डर परेशान हैं. राज्य सरकार के आदेश के प्रेरक-तत्वों को लेकर उच्च न्यायालय शायद इससे कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता.

पटना उच्च न्यायालय में सरकार की किरकिरी तो हुई ही, कुलदीप नारायण प्रकरण राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी आलोचना का कारण बन गया है. सूबे के विपक्षी राजनीतिक दल जीतनराम मांझी सरकार पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त के पक्ष में खड़े हो गए हैं. हालांकि ये दल सामान्य नागरिक सुविधा के फ्रंट पर नगर की बदहाली के लिए दो दिन पहले तक निगम प्रशासन के खिलाफ खड़े थे. कुछ हफ्ते पहले जब हाइकोर्ट ने पटना को देश की सबसे गंदी राजधानी बताया था तब ये दल निगम प्रशासन की निष्क्रियता के लिए उसे निशाना बना रहे थे. अब मांझी सरकार के निर्णय ने इन दलों को कुलदीप नारायण के साथ कर दिया. भाजपा के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने तो विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत रंज़िश के कारण ऐसी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. आईएएस एसोसिएशन की राज्य शाखा ने आंदोलन की चेतावनी दी है और मामले को दिल्ली तक ले जाने की धमकी दी है. बिहार प्रशासनिक सेवा के संगठन बासा ने भी आंखें लाल कर ली हैं. पर, सबसे दिलचस्प स्थिति पटना नगर निगम की है. यहां निर्वाचित वार्ड पार्षद (वार्ड कमिश्नर) तो दो धड़े में हैं ही, अधिकारी-कर्मचारी भी दो खेमों में बंट गए हैं. कुलदीप के समर्थक पार्षद व अधिकारी-कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं. नगर आयुक्त समर्थक तबका पटना में धरना प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है. पर, दूसरा धड़ा अभी खामोश है और उसे भी सरकार की ही तरह अदालत के निर्णय का इंतजार है. कुलदीप के पक्ष में पार्षदों की गोलबंदी का एक कारण भाजपा का उनके साथ होना और दूसरा नगर निगम को भंग करने की सरकार की पहल भी रही है. नगर निगम की अराजक स्थिति के कारण सरकार ने इसे भंग करने की चेतावनी दे दी है. अर्थात पटना के निगम पार्षद पहले से ही सरकार के विरोध में सड़क पर आ रहे थे या आने को बेताब थे और अब कुलदीप नारायण प्रकरण ने उन्हें गोलबंदी का नया आधार दे दिया.

राज्य सरकार ने कुलदीप नारायण के निलंबन आदेश में हालांकि उन बिंदुओं की चर्चा की है जिनके कारण ऐसा कठोर कदम उठाया गया है. सरकार ने कहा है कि नगर आयुक्त को एक महीना पहले (11 नवम्बर) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पांच मामलों पर उनसे सफाई मांगी थी. इनमें मच्छर मारने के लिए फॉगिंग मशीन न खरीदने, कचरा प्रबंधन के उपाय न करने, शहर की सफाई में कोताही, अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण पर रोक में विफल रहने का मामला था. कुलदीप ने अपने जवाब में उपलब्ध रकम के उपयोग न होने की बात स्वीकार करते हुए अधिकांश काम न होने के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया था. लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. अब अदालत ने साफ कर दिया है कि कुलदीप नारायण पटना नगर निगम के नगर आयुक्त-शीर्ष कार्याधिकारी-तो रहेंगे, पर वह केवल निगरानी के मामलों को निपटाएंगे और न्यायालय उनसे उनकी जिम्मेदारी के निर्वहन का हिसाब लेगा. नगर निगम के अन्य कार्य दूसरे अधिकारी देखेंगे. अर्थात पटना नगर निगम क्षेत्र की नागिरक सुविधाओं के लिए कुलदीप नारायण जिम्मेदार नहीं रहेंगे. वस्तुतः पटना एक नई परिस्थिति में है जहां नगर आयुक्त तो होंगे, पर नागरिक सुविधाओं के लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे. हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि कानूनी तौर पर जिन कार्यों के लिए नगर आयुक्त ही सीधे रूप से जिम्मेदार हैं, वे काम कैसे होंगे. पटना नगर निगम पिछले कई वर्षों से राजनेता और नौकरशाहों के लिए फुटबॉल मौदान की तरह है. नगर आयुक्त अधिकारी अपने ढंग से नगर सरकार का संचालन चाहता है और महापौर (मेयर) और उनकी सशक्त समिति अपने तरीके से. पार्षदों का समूह तीन खेमों में होता रहा है- एक मेयर खेमा, दूसरा उप महापौर खेमा और तीसरा निर्दल. पर, सभी के अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, इस आधार पर वे सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं. लेकिन सुविधा के नाम पर विधायक और सांसदों की तरह वे भी एकजुट होते हैं. ये लाभ-लोभ उन्हें गोलबंद करता है. यह गोलबंदी कभी महापौर के पक्ष विपक्ष में होती है, कभी सरकार के पक्ष-विपक्ष में तो कभी कुलदीप नारायण जैसे अफसर के पक्ष-विपक्ष में. लेकिन इतना तो तय है कि भोग तो पटना के आम लोगों को ही भोगना पड़ता है. कुलदीप नारायण आज कुछ लोगों के नायक बन गए हैं, पर जब पटना के बाशिंदों को बेहतर नागरिक सुविधा देने या उनके विस्तार और विकास की बात चलेगी, तो उनके खाते में भी कुछ खास होगा, ऐसा नहीं लगता है.■

कुलदीप नारायण ने अपने जवाब में उपलब्ध रकम के उपयोग न होने की बात स्वीकार करते हुए अधिकांश काम न होने के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया था. लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. अब अदालत ने साफ कर दिया है कि कुलदीप नारायण पटना नगर निगम के नगर आयुक्त- शीर्ष कार्याधिकारी- तो रहेंगे, पर वह केवल निगरानी के मामलों को निपटाएंगे और न्यायालय उनसे उनकी जिम्मेदारी के निर्वहन का हिसाब लेगा. नगर निगम के अन्य कार्य दूसरे अधिकारी देखेंगे. अर्थात पटना नगर निगम क्षेत्र की नागिरक सुविधाओं के लिए कुलदीप नारायण जिम्मेदार नहीं रहेंगे. अब पटना एक नई स्थिति में है जहां नगर आयुक्त तो होंगे, पर नागरिक सुविधाओं के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे.

कुलदीप नारायण

feedback@chauthiduniya.com

खेलों में खास नहीं रहा साल

साल-2014 भारत के लिए खेलों के लिहाज से मिलाजुला रहा. इस साल ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों और इंचियोन एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. क्रिकेट में भारत को टी-20 विश्वकप के फाइनल में श्रीलंका से हार मिली. भारतीय फुटबॉल की दशा दिशा बदलने के उद्देश्य से इंडियन सुपर लीग की शुरूआत की गई. हॉकी में 16 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता. कुल मिलाकर यह साल भारत के लिए मिला जुला रहा...कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में नहीं आई, लेकिन इस साल कई खेलों की लीग्स की शुरुआत होने से खेलों के भविष्य के लिए बेहतर संकेत दिखाई दिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेट

फिल ह्यूज की मौत

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की घरेलू क्रिकेट में शेफील्ड शील्ड और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान शॉन एबॉट की गेंद लगने की वजह से मौत हो गई. गेंद लगने के बाद वह मैदान में बेहोश होकर गिर पड़े थे. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन किया गया. लेकिन

दो दिन बाद उनकी मौत हो गई. 30 नवंबर को फिल 26 वर्ष के होने वाले थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैच खेले जिनकी 49 पारियों में उन्होंने 32.65 की औसत से 1535 रन बनाए. उनके नाम तीन शतक और सात अर्धशतक दर्ज हैं. उन्होंने अपने करियर के दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया था. वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज थे. उन्होंने 25 एकदिवसीय मैचों में 35.91 की औसत से 826 रन बनाए. फिल अपने पदार्पण एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे. ■

टी-20 विश्वकप

बांग्लादेश में आयोजित पांचवें टी-20 विश्वकप में बाज़ी इसबार श्रीलंकाई टीम के नाम रही. भारतीय टीम को फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा. हार का ठीकरा 2011

में भारत को विश्वचैंपियन बनाने में अहम रोल अदा करने वाले युवराज सिंह पर फूटा. फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने लसिथ मलिंगा की कप्तानी में बेहतरीन गेंदबाज़ी की और भारतीय टीम को मजह 130 रनों पर रोक दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने कुमार संगकारा की 52 रनों की नाबाद पारी की बदौलत छह विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. तीसरी बार टी20 विश्वकप के फाइनल में पहुंची श्रीलंका ने 1996 के बाद कोई विश्व खिताब हासिल करने में सफलता हासिल की.■

रोहित शर्मा का दोहरा शतक

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एकदिवसीय क्रिकेट में दूसरी बार दोहरा शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया है. श्रीलंका के खिलाफ वापसी करते हुए पारी की शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा ने 264 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अपनी मैराथन पारी के दौरान रोहित ने केवल 173 गेंदों का सामना किया. पारी के दौरान रोहित ने 33 चौके और नौ छक्के भी जड़े. रोहित ने इस पारी के दौरान वीरेंद्र सहवाग के 219 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा. इसके पहले रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में नवंबर, 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेली थी. एकदिवसीय मैचों में अबतक चार दोहरे शतक लगे हैं. चारों दोहरे शतक भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं.■

264 रन

रोहित शर्मा ने 264 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अपनी मैराथन पारी के दौरान रोहित ने केवल 173 गेंदों का सामना किया.

फॉर्मूला वन

ब्रिटेन के फार्मूला वन चालक लुइस हैमिल्टन ने साल 2014 की ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीत ली . इससे पहले वह 6 साल पहले 2008 में चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुए थे. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले अश्वेत फॉर्मूलावन चालक थे. इस सीजन उन्होंने मर्सिडीज टीम के लिए ड्राइविंग करते हुए 19 में से 11 रेस में जीत हासिल की. पिछले चार सीजन रेडबुल टीम के सबेस्टियन व्हीट्ल ने चैंपियनशिप का खिताब जीता था. उन्होंने अपने करियर में लगातार पांच रेसों में पहली बार जीत हासिल की. यह साल भारतीय फॉर्मूला वन प्रेमियों के लिए निराशाजनक रहा. इस साल नोएडा के बुद्ध इंटरनेश्नल सर्किट में इंडियन ग्रां प्री आयोजित नहीं हुई. ■

फीफा विश्वकप

ब्राजील में खेले गए 20 वें फीफा विश्वकप फाइनल में जर्मनी अर्जेंटीना को हराकर विश्व खिताब पर कब्जा कर लिया. विश्वकप का अंत बड़े ही रोमांचक अंदाज में हुआ. रियो-डि-जेनेरियो में खेले गए फाइनल मुकाबले के एक्सट्रा टाइम में जर्मनी के 22 वर्षीय खिलाड़ी मारियो गोएत्जे ने मैच के 113 वें मिनट में बेहतरीन गोल कर जर्मनी को चौथी बार विश्व चैंपियन बना दिया. इससे पहले वेस्ट जर्मनी ने वर्ष 1990 में अर्जेंटीना को ही हराकर विश्वकप पर कब्जा किया था. एकीकरण के बाद जर्मनी की यह पहली विश्वकप जीत है. इस बार जर्मनी वन नेशन वन ड्रीम को मूल मंत्र बनाकर विश्वकप में उतरा था. यह पहला मौका था जब कोई यूरोपीय टीम अमेरिकी धरती पर विश्वविजेता बनने में कामयाब हुई है. कप्तान फिलिप लाह्म और उनकी टीम ने एकीकृत जर्मनी का विश्वविजेता बनने का 24 साल लंबा इंतजार खत्म कर दिया. अर्जेंटीना के कप्तान लॉयोनेल मेसी का विश्वखिताब जीतने का सपना टूट गया, लेकिन उन्हें विश्वकप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और गोल्डन बॉल पुरस्कार से नवाजा गया. जबकि कोलंबिया के जेम्स रोड्रिग्ज को गोल्डन बूट और जर्मन गोलकीपर मैनुएल न्युअर को गोल्डन ग्लव पुरस्कार से नवाजा गया. ■

बैडमिंटन

सटार शटलर सायन से आगे भी भारत में बैडमिंटन की इबारत लिखी जाने लगी है. पीवी संधु, पी कश्यप, के श्रीकांत, गुरसाईं दत्त ने भी इस साल अपनी छाप विश्व बैडमिंटन जगत में छोड़ी. साल के समाप्त होते-होते भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ नई उपलब्धियां हासिल कीं. सायना नेहवाल और के श्रीकांत ने चाइना ओपन सुपर सीरीज का खिताब जातकर इतिहास रच दिया. के श्रीकांत ने पांच बार के विश्व चैंपियन लिन डैन को फाइनल मुकाबल में मात दी. पीवी संधु ने भी अपनी स्थिति को और बेहतर किया. लगातार दूसरे साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्यपदक जीता. साथ ही एशियाई खेलों में कांस्य पदक अपने नाम किया. उन्होंने लगातार दूसरे साल मकाऊ ओपन जीता और साल का पहला खिलात अपने नाम किया. पी कश्यप ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. भारतीय टीम ने दिल्ली में आयोजित उबेर कप का कांस्य पद अपने नाम किया.■

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के परिणाम भारतीय खिलाड़ियों के लिए संतोषजनक रहे. भारत 2010 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने में नाकामयाब रहा. इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाला दल पिछली बार की तुलना में काफी छोटा था, बावजूद इसके भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. भारत की ओर से 14 स्पर्धाओं में कुल 215 खिलाड़ियों ने शिरकत की. भारतीय दल ने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल 64 पदक अपने नाम किए. पदक तालिका में भारत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मेजबान स्कॉटलैंड के बाद पांचवें स्थान पर रहा. इंग्लैंड ने 58 स्वर्ण, 59 रजत और 57 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया. ऑस्ट्रेलिया (49 स्वर्ण, 42 रजत,46 कांस्य) पदक तालिका में दूसरे, कनाडा (32 स्वर्ण,16 रजत, 34 कांस्य) तीसरे जबकि मेजबान स्कॉटलैंड (19 स्वर्ण,15 रजत,19 कांस्य) चौथे स्थान पर रहा. राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का यह चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. वेल्स की जिम्नास्ट फ्रैंकी जोन्स को राष्ट्रमंडल खेलों में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया. जोन्स ने ग्लास्गो में रिदमिक जिम्नास्टिक में एक स्वर्ण और पांच रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते. डेविड डिक्सन अवार्ड राष्ट्रमंडल खेलों में एक एथलीट को उसके असाधारण प्रदर्शन तथा टीम के लिए योगदान के लिए दिया जाता है.■

बॉक्सिंग

भारतीय मुक्केबाजों के मुक्के का दम इस साल भी दिखाई दिया. पहले तो एमसी मेरी कॉम ने एशियाई खेलो में स्वर्ण पदक जीता. लेकिन सरिता देवी के साथ अन्याय भी हुआ. इसके बाद विरोध स्वरूप सरिता देवी ने कांस्य पदक लेने से इंकार करके खलबली मचा दी. अंततः सरिता ने माफी मांगी और कांस्य पदक स्वीकार किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने सरिता के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया.■

टेनिस

साल 2014 भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के लिए उपलब्धियों भरा रहा और बाकी सितारे जूझते रहे. इस साल सानिया ने अपने करियर का तीसरा मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. सानिया ने ब्रूनो सोरेस के साथ मिलकर यूएस ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता. 28 वर्षीय सानिया ने साल का आखिरी खिताब जीतकर सत्र का शानदार अंत किया. यह कारनामा भारत के लिएंडर पेस और महेश भूपति जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके. वरिष्ठ पुरुष खिलाड़ियों के एशियाई खेलों से हटने के बाद सानिया ने कमान संभाली और भारत को साकेत मियनेनी के साथ मिलकर मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक जीता. महेश भूपति ने टेनिस से संन्यास लिया. और आईपीटीएल की शुरुआत की. इस साल सानिया सात डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और कारा ब्लैक के साथ तीन खिताबों पर कब्जा भी किया, वहीं युगल रैंकिंग में सानिया ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की.■

स्क्वैश

साल 2014 भारतीय स्क्वैश के लिए उपलब्धियों से भरा रहा. दीपिका पल्लीकल और ज्योशना चिनप्पा की जोड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों के महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता.

दीपिका ने एशियाई खेलों में एकल स्पर्धा का कांस्य पदक भी जीता. कॉमनवेल्थ खेलों की सफलता का सिलसिला एशियाई खेलों में भी जारी रहा. सौरभ घोषाल एशियाई खेलों में पुरुष एकल का रजत पदक प्राप्त किया. उन्हें फाइनल मुकाबले में 2-3 के नजदीकी अंतर से हार मिली.■

एशियाई खेल

इंचियॉन में हुए एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन पिछले एशियाई खेलों की तुलना में फीका रहा है. जहां ग्वांगजो एशियाई खेलों में भारत को 14 स्वर्ण पदक मिले थे, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 11 स्वर्ण पदक ही जीत पाए. भारत पदक तालिका में आठवें स्थान पर रहा. पुरुष हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर स्वर्ण पदक हासिल किया. अपनी साख के अनुरूप मेरी कॉम ने भी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता. भारत ने कुल 57 पदक जीते जिसमें ग्यारह स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पादक शामिल थे. चीन पदक तालिका में 151 स्वर्ण,108 रजत और 83 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष पर रहा. मेजबान दक्षिण कोरिया 79 स्वर्ण, 71 रजत और 77 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. जापान ने 200 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया जिसमें 47 स्वर्ण, 76 रजत और 77 कांस्य पदक शामिल हैं.■

आईएसएल का आरंभ

भारत को विश्वकप में खेलता देखने के उद्देश्य से आठ टीमों की फ्रेचायजी वाले इंडियन सुपर लीग की शुरुआत इस साल हुई. जिसकी तारीफ फीफा ने भी की. आईएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को भी पायदा पहुंच रहा है. भारतीय गोलकीपरों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका मनमोह लिया है. आने वाले समय में देश की युवा पीढ़ी फुटबॉल में करियर को देखते हुए फुटबॉल को गंभीरता से लेगी. 2017 में भारत में फीफा अंडर-17 विश्वकप का आयोजन हो रहा है. आईएसएल से भारत की तैयारियों को मजबूती भी मिल रही है.■

Hero INDIAN SUPER LEAGUE IMG RELIANCE STAR

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आम आदमी की सुरक्षा के लिए हम कितने तैयार हैं

मैं नहीं जानता कि पुलिस के पास कितने हथियार हैं. लेकिन इतना पता है कि पुलिस के पास एक रिवॉल्वर है जिसके इस्तेमाल वो नहीं करती क्योंकि इसके इस्तेमाल में समस्या आती है. लेकिन किसी बार पर छापा मारने में कोई समस्या नहीं आती. किसी अमीर आदमी के बेटे को डिटेन करने (पकड़ने) और उनसे पैसा लेने में कोई समस्या नहीं आती.

मैं यह कॉलम एक अत्यंत ही दुःखद घटना (नृशंस हत्याकांड) के साये में लिख रहा हूं. ऐसी घटना हाल फिलहाल किसी ने न देखी थी न सुनी थी. हर बच्चा भगवान का बच्चा है, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो. ये जो भी आतंकवादी हैं, उन्होंने सिर्फ लागों को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए ऐसा किया. लेकिन इन आतंकियों ने बच्चों के साथ जो किया वह अक्षम्य है. बच्चों की इनसे या इनकी बच्चों से क्या दुश्मनी थी? हाफिज सईद और परवेज मुशर्रफ इस बात के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं. उनके मुंह से यह सब सुनना मजाकिया लगता है. कुछ संगठन हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली है. इसमें भारत कहां से आ गया? मैं इसे उनकी बेहतरीन योजना मानता हूं कि अपनी हर समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दो. हमारा दिल, हमारी भावना उन शोक संतृप्त परिवारों के साथ है जैसा कि उन्होंने कहा कि इन छोटे ताबूतों को उठाना बहुत भारी है. जब बच्चे की मौत होती है तो माता-पिता पर क्या गुजरती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत-पाकिस्तान की बात करने की जगह उन परिवारों के लिए सहानुभूति महसूस करनी चाहिए. इस मामले में भारत-पाकिस्तान की बात अप्रासंगिक है.

इस घटना के बाद हम कहां खड़े हैं इस पर विचार करना चाहिए. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) की बैठक होनी चाहिए. हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. भारत में लगभग सभी शहरों (बड़े और छोट) में आईएसआई और इंडियन मुजाहिद्दीन के स्लीपर सेल मौजूद हैं और अपने ऑपरेशन चला रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र की बात कर सकता हूं, मुंबई की बात कर सकता हूं. दो साल पहले की बात कर रहा हूं. यहां की पुलिस अनौपचारिक रूप से स्लीपर सेल की जानकारी के बारे में बता चुकी है. यह भी कह चुकी है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रही है. अब यह बकवास नहीं है तो क्या है? पुलिस को एक काम करने के लिए पैसा दिया जाता है. अगर उन्हें पता है कि कहीं अपराध हो रहा है तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की क्या जरूरत है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बैठक करके एक विशेषाधिकार प्राप्त सेल बनाना चाहिए, जो इन स्लीपर सेल्स को पूरी तरह से खत्म कर सके. यह रातोंरात नहीं हो सकता. इसमें दो या पांच साल लग सकते हैं. लेकिन इसकी शुरुआत अभी होनी चाहिए.

हमारे देश में अगर ये तथाकथित स्लीपर सेल्स हैं तो ये फिलहाल सोये हुए हैं और सीमापार से संकेत मिलने का इंतजार भर कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम आग के साथ खेल रहे हैं. हमारा कोई मुख्यमंत्री क्या सोचता है, क्या करता है, कोई नहीं कह सकता. लेकिन हम इस तरह का एक नरसंहार भारत में हो, यह त्रासदी बर्दाश्त नहीं कर सकते. सौभाग्य से 26/11 के बाद अभी तक हम बचे हुए है. 26/11 में सीएसटी स्टेशन पर हमने बहुतों को खोया है. मैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बयान को समझ सकता हूं. उन्होंने नवाज शरीफ को सांत्वना दी है. यह सब ठीक है. लेकिन अब हमें धरातल पर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोग हमें एक सॉफ्ट स्टेट मानते रहेंगे. कोई भी देश खुद की रक्षा नहीं कर सकता, यदि बाहर यह संदेश जाये कि वह एक सॉफ्ट स्टेट है.

बलात्कार की घटना के साथ भी यही सब कुछ लागू होता है. दुनियाभर में बलात्कार होते हैं. बलात्कार भी अन्य अपराध की तरह ही एक अपराध है. लेकिन दुःखद यह है कि लोगों के बीच यह आम धारणा बन चुकी है कि बलात्कारी बच निकलेगा. इस अपराध से सख्ती से निपटना चाहिए. दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वह अन्य के लिए उदाहरण बन जाए. अपराधी को ऐसी सजा मिले जिससे गलत लोगों में भय पैदा हो और निर्दोष के मन में विश्वास जागृत हो. दुर्भाग्य से हमारा सिस्टम बहुत ढ़ीला है. इसलिए ऐसा नहीं हो पाता. छोटे-मोटे अपराध के मामलों में पुलिस हमेशा कार्रवाई करने के लिए तैयार है. वह मुंबई के सब-अर्बन इलाके में जाकर किसी बार में छापा मारेगी जहां ड्रग्स की खपत होती है. बड़े परिवार के बीस-तीस लोगों को पकड़ लेंगे और उनसे पैसे ले लेंगे. कुल मिलाकर कुछ निकलेगा नहीं. पुलिस को ऐसे अपराधों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. अगर अमीर लोग ड्रग्स खरीद कर, उसका सेवन कर खुद को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा होने दें. उनकी देखभाल करना उनके माता-पिता का काम है. जनता का पैसा उनपर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए. बच्चियों को बचाने की जरूरत है, निर्दोष लोगों को आतंकियों से बचाने की जरूरत है. इन सब कामों के लिए पुलिस की हमें जरूरत है.

बलात्कार की घटना के साथ भी यही सब कुछ लागू होता है. दुनियाभर में बलात्कार होते हैं. बलात्कार भी अन्य अपराध की तरह ही एक अपराध है. लेकिन दुःखद यह है कि लोगों के बीच यह आम धारणा बन चुकी है कि बलात्कारी बच निकलेगा. इस अपराध से सख्ती से निपटना चाहिए. दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वह अन्य के लिए उदाहरण बन जाए. अपराधी को ऐसी सजा मिले जिससे गलत लोगों में भय पैदा हो और निर्दोष के मन में विश्वास जागृत हो.

मैं नहीं जानता कि पुलिस के पास कितने हथियार हैं. लेकिन इतना पता है कि पुलिस के पास एक रिवॉल्वर है जिसके इस्तेमाल वो नहीं करती क्योंकि इसके इस्तेमाल में समस्या आती है. लेकिन किसी बार पर छापा मारने में कोई समस्या नहीं आती. किसी अमीर आदमी के बेटे को डिटेन करने (पकड़ने) और उनसे पैसा लेने में कोई समस्या नहीं आती. पुलिस ही सॉफ्ट हो गई है. पुलिस राज्य का विषय है. लेकिन राजनाथ सिंह को सभी राज्य के गृह मंत्रियों और गृह सचिवों की बैठक बुलानी चाहिए और गंभीरता से इस समस्या का समाधान करना चाहिए. यह बात करनी चाहिए कि अगर पुलिस वालों का वेतन बढ़ाना है, उन्हें इंश्योरेंस (बीमा) देना है तो दीजिए, लेकिन हमें मजबूत कदम उठाने ही होंगे और हमारे पुलिस बल को मजबूत बनाना होगा. आम आदमी के मन में विश्वास पैदा करना होगा कि हम असुरक्षित नहीं है. उनके लिए बेहतर किया जाना बाकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोरारजी और जेपी के बीच मतभेद थे

मोरारजी भाई के अपने राज्य गुजरात में विद्यार्थियों का नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब प्रारंभ में राजनेताओं को लगा था कि विद्यार्थियों का सोडावाटरी जोश है, जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा. लेकिन उनकी आशा के विपरीत जब यह आंदोलन भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट विधायकों के विरुद्ध एक जन-आंदोलन का रूप ग्रहण करने लगा, तब सारे लोग चौंके. गुजरात के विद्यार्थियों ने जयप्रकाश जी को बुलावा भेजा ताकि वे आएं और उनका मार्गदर्शन करें. इससे पहले जयप्रकाश युवकों के नाम अपनी प्रसिद्ध अपील जारी कर चुके थे. जयप्रकाश ने विद्यार्थियों से सीधा सवाल पूछा, विधानसभा भंग होने के बाद क्या? उन्होंने सलाह दी कि आंदोलन को विधायक दिशा देनी चाहिए. मोरारजी भाई को यही बात कचोट गई. उनके राज्य में जयप्रकाश सलाह दे रहे हैं और विद्यार्थी उन्हें न पूछकर जयप्रकाश से मार्गदर्शन मांग रहे हैं. विद्यार्थियों का जयप्रकाश की ओर झुकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि रविशंकर महाराज को छोड़कर गुजरात के किसी भी वरिष्ठ नेता ने तब तक उनके आंदोलन का समर्थन नहीं किया था.

जब वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को लगा कि हम पीछे रह गए और जनता आगे बढ़ गई है, तब उन्होंने जोर-शोर से आंदोलन का समर्थन करना प्रारंभ किया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. नवनिर्माण समिति के छात्रों ने लगभग एक स्वर से सभी प्रकार के अवसरवादियों का, जिनमें देसाई भी शामिल थे, विरोध किया. विधानसभा विसर्जन के लिए जब आंदोलन गांव-गांव में फैलने लगा, तभी मोरारजी भाई ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 11 मार्च 1974 से उपवास करने की घोषणा कर दी. इसमें उन्होंने किसी की सलाह नहीं ली थी. नवनिर्माण समिति के नेताओं से भी नहीं. यह उपवास गुजरात के छात्र आंदोलन का माखौल था.

17 मार्च, 1974 को मोरारजी भाई ने गुजरात के गांधी पं. रविशंकर महाराज के हाथ से फलों का रस लेकर अनशन तोड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा-पूर्ति के लोभ में जनता के एक शक्तिशाली और संगठित आंदोलन की आधारशिला भी तोड़ दी. मोरारजी भाई के उपवास का वहां के छात्र नेताओं पर क्या असर पड़ा, इसका संकेत दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक में 24 मार्च, 1974 को मनीष जानी और अशोक पंजाबी के वक्तव्य से मिलता है-सब जानते हैं कि आंदोलन हमने किया और विधानसभा भंग क्यों हुई. मोरारजी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. चिमन भाई को भी फालतू महत्व दिया जा रहा है, उनकी बात कोई नहीं मानता. कुछ बड़े किसान मानते भी होंगे तो गुजरात में सिर्फ वे ही तो नहीं हैं. रविशंकर महाराज से हमें बहुत मदद मिली. उनमें हमारी बड़ी श्रद्धा है. जे.पी के भाषणों से पहली बार हमें समझ पड़ा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है. हमने तो उनसे कहा था कि वह हमारा नेतृत्व करें, पर उन्होंने मंजूर नहीं किया. वह कह गए थे कि फिर आऊंगा.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

गुजरात में ही दोबारा फिर आंदोलन संगठित होना शुरू हुआ. इस बार मांग थी, चुनाव तत्काल कराए जायें. विधानसभा भंग हुए एक साल बीत चुका था. बिहार में प्रारंभ हुआ आंदोलन देश के पैमाने पर अपना असर दिखला रहा था. सारा देश एक स्वर से जयप्रकाश की आवाज में अपनी आवाज मिला रहा था. दिल्ली में जे.पी के आमंत्रण पर 25-26 नवंबर को राजनीतिक दलों के नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन भी हो चुका था, जिसमें एक समन्वय समिति का निर्माण किया गया था. गुजरात के विद्यार्थी और लोक स्वराज्य आंदोलन को जे.पी ने स्पष्ट सलाह दी थी कि इसी सवाल पर जन संगठन बनाओ और उसके द्वारा जन आंदोलन खड़ा करो.

मोरारजी भाई ने पुनः चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली में 6 अप्रैल 1975 से अनशन प्रारंभ कर दिया. इस घोषणा में पहले उन्होंने किससे सलाह ली, पता नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि जयप्रकाश से सलाह नहीं ली थी. जनता के स्तर पर होने वाली हलचल की पुनः भ्रूण हत्या हो गई.

मोरारजी भाई ने पुनः चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली में 6 अप्रैल 1975 से अनशन प्रारंभ कर दिया. इस घोषणा में पहले उन्होंने किससे सलाह ली, पता नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि जयप्रकाश से सलाह नहीं ली थी. जनता के स्तर पर होने वाली हलचल की पुनः भ्रूण हत्या हो गई. चुनाव टालने के विरुद्ध जो जन आंदोलन उठ रहा था, वह एक व्यक्ति के अनशन की तुलना में छोटा कर दिया गया. मोरारजी ने उसके साथ आपातकाल (बाह्य) को समाप्त करने की मांग जोड़ दी थी. 12 अप्रैल की सुबह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित ने मोरारजी भाई से 10 मिनट तक बातचीत की. भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री ने आपातस्थिति हटाने के पक्ष में उस समय की प्रधानमंत्री के तर्क सुनने के बाद उमाशंकर दीक्षित और अपनी बातचीत को गोपनीय कह कर आपात स्थिति के निर्णय को आपात स्थिति के अभ्यस्त दो बड़े लोगों के बीच का मामला बना दिया और अपनी अधूरी मांग की पूर्ति के आश्वासन पर अनशन समाप्त कर दिया. इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया कि 7 जून के आसपास चुनाव कराएं जायेंगे, पर उन्होंने मोरारजी भाई की दूसरी मांग(आपातकाल की समाप्ति) स्वीकार नहीं की. लोक स्वराज्य आंदोलन के नेताओं का जनसंगठन बनाने और जन आंदोलन खड़ा करने का सारा सपना सिर्फ एक आदमी के कारण धूल-धूसरित हो गया.

सम्भवतः जयप्रकाश जी मोरारजी भाई के सीमित उद्देश्यों से वाकिफ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने एक वक्तव्य में यह साफ कर दिया कि वे गुजरात के चुनाव अभियान में सक्रिय हिस्सा नहीं लेंगे. गुजरात लोक संघर्ष समिति ने जयप्रकाश के पिछली सलाह के अनुसार एक ही चुनाव चिन्ह रखने की मांग की, जिसे मारारजी भाई ने नहीं माना. मोरारजी भाई ने अपनी ज़िद में आकर जनता मोर्चा को लगभग तोड़ ही दिया था. पर एन मौके पर अन्य नेता जयप्रकाश जी को अहमदाबाद लाने में सफल हो गए. उनके कारण यह विघटित होने से बच गया. मोरारजी भाई अपने राज्य में घटी घटनाओं से भी यह नहीं समझ पाए कि वह जयप्रकाश जी की तरह लोकप्रिय और स्वीकार्य नहीं हो सकते. जनसंघ के नेताओं ने उसी समय कहा कि मोरारजी भाई गुजरात को अपनी निजी संपत्ति समझ रहे हैं, इसीलिए वे जयप्रकाश जी के गुजरात संबंधी किसी सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

हमारे सांसद देशद्रोही हैं...

भारत की संसद में महान विद्वान सांसद हैं. लोकसभा हो या राज्यसभा, इन सांसदों से मिलने पर लगता है कि इनसे बड़ा बुद्धिमान और इनसे ज्यादा समझदार देश में कोई है नहीं. इस समझदारी पर उनकी आरती उतारी जाए, ऐसा मन करता है. सांसदों के बारे में अगर कोई बात करें, उसे सांसद संसद के अपमान की संज्ञा से विभूषित करने लगते हैं. लेकिन वक्त आ गया है कि इन सांसदों के बारे में हम भी बात करें और आप भी बात करें. जब तक देश की जनता सांसदों के बारे में बात नहीं करेगी, तब तक इन सांसदों को अपना बुनियादी कर्तव्य भी याद नहीं आएगा.

संसद इसलिए होती है कि उसमें देश से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत हो, उनका विश्लेषण हो और उनका हल कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर फैसला हो. लेकिन, देश की बुनियादी समस्याओं पर इस संसद में कभी बहस होती ही नहीं है. सरकार आधे-अधूरे मन से या अपनी बुद्धिमत्ता से जो फैसले लेती है, उन फैसलों को विश्लेषित करने का भी काम संसद में नहीं होता. ज्यादातर सांसद तो संसद में वो कागज पढ़कर भी नहीं जाते, जो उनके यहां संसद की कार्यवाही की जानकारी देने के लिए रोज सुबह भेजे जाते हैं. हम यह बात इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि अगर वे उन कागजों को पढ़कर जाते, जो उनके यहां रोज सुबह संसद का सचिवालय भेजता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में कुछ तो सार्थकता नज़र आती. अगर एक सर्वे करें, जिसे हम नहीं करना चाहते, कि देश की दस बुनियादी समस्याएं क्या हैं और उनकी प्राथमिकतायें क्या हैं. अगर ये कोई सांसदों से पूछे तो उसके मजेदार उत्तर मिलेंगे. लेकिन जो भी उत्तर मिले, उन उत्तरों के ऊपर भी कभी संसद में गंभीर बहस हुई हो और उस बहस का कोई हल निकला हो, ऐसा संसद के बाहर बैठने वाले लोगों को कुछ पता नहीं. अभी ताजा-ताजा एक उदाहरण सामने आया है.

पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने देश में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की. आधार कार्ड के ऊपर साठ हजार करोड़ रुपये का बजट बिना संसद की जानकारी में लाये, मंत्रिमंडल ने पास कर दिया और उसके ऊपर खर्च करना भी शुरू कर दिया. बहुत बड़े बिजनेसमैन नंदन नीलेकणी को इस योजना का मुखिया बनाया गया. उन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप चुन लिए जिनका अस्तित्व संदेह के घेरे में है. इसका परिणाम जो होना था, वह हुआ. बहुत सारी जगहों पर गलत आधार कार्ड बने, दो-दो आधार कार्ड बने. गलत पते से आधार कार्ड बने और हर उस व्यक्ति को आधार कार्ड मिल गया जिनको नहीं मिलना चाहिए था. पर ये दूसरी तरह की बहस है. सवाल अभी दूसरा है.

मुख्य सवाल आधार कार्ड को लेकर दूसरा है. पहला, सांसदों को पता नहीं है कि आधार कार्ड की सारी जानकारी कहां भेजी जा रही है. सांसदों को यह भी पता नहीं है कि आधार कार्ड का मतलब दुनिया की उन बड़ी कंपनियों के पास हमारी देश के हर व्यक्ति की बुनियादी जानकारी भेजना है, जो मल्टीनेशनल कहलाती हैं और जो देश में व्यापार करना चाहती हैं. आधार कार्ड का दूसरा उद्देश्य अमेरिकी सरकार के पास हमारी सारी बुनियादी जानकारी भेजना है ताकि वह देश में कैसी सरकार हो, कैसा विपक्ष हो, कैसे सुप्रीमकोर्ट के जज हों और कैसे सेना के अफसर हों, इसका विश्लेषण कर सकें और उस पद पर भविष्य में आने वाले हर व्यक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सके. शायद इसका साधारण भाषा में अर्थ यह होता है कि देश के ऊपर बिना हमला किए, देश को अपना गुलाम बना लेना. देश को गुलाम बना लेने का मतलब देश के हर व्यक्ति को आर्थिक या दूसरे तरीकों से अपने दबाव में लगातार बनाए रखना. मल्टीनेशनल कंपनियां या अमेरिकी सरकार में काम करने वाले लोग हमारे देश के दुश्मन समूहों को ये जानाकरी भेज सकते हैं. इस बात का भी खतरा है कि अभी तक जितनी जानकारियां अमेरिका के पास गई हैं वो जानकारियां पाकिस्तान और चीन के साथ शायद बांटी जा चुकी हैं. इस आधार कार्ड में उपलब्ध जानकारी के हिसाब से अमेरिका में बैठा हुआ, हिन्दुस्तान के ऊपर नजर रखने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री, हिन्दुस्तान का सेना नायक, हिन्दुस्तान के मुख्य न्यायाधीश और हिन्दुस्तान का प्रत्येक वह व्यक्ति जो हिन्दुस्तान में जरा भी महत्व रखता है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है. अब इसके लिए किसी व्यक्ति के निजी स्टाफ को घूस देने की जरूरत नहीं है. आवागमन सहित सारी जानकारियां आधार कार्ड के जरिए अमेरिका में बैठे हुए उस सेल के पास हैं, जो सेल हिन्दुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा का विश्लेषण करती है. तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को भी अमेरिका कहीं न कहीं प्रभावित भी कर रहा है और नियंत्रित भी कर रहा है.

सवाल उठता है कि आधार कार्ड बनने के बाद, इसकी जानकारी या इसके बनाने का जिम्मा अमेरिकी तकनीकि विशेषज्ञों को क्यों दिया गया? क्या हमारे देश में अपना सर्वर बनाया नहीं जा सकता था? क्या जानकारी हम अपने पास नहीं रख सकते थे? फिर अगर कोई भीतराघात होता या हमारी जानकारी विदेशों में जाती तो हमारे अपने लोग इसके लिए जिम्मेदार होते या हम उसके ऊपर तकनीकी पहरा बैठा सकते थे. पर हमने जान-बूझकर ये सारी जानकारी विदेशियों के हाथ में दे दी.

हिटलर ने जब हत्याएं कीं, तो उन सारे यहूदियों के नाम, पता, उन्हें अमेरिका की आईबीएम कंपनी ने उपलब्ध कराये थे. जर्मनी में आधार कार्ड जैसे शिनाख्ती कार्ड आईबीएम ने ही बनाये थे. अब भारत के मासूम और समझदार सांसदों को देशद्रोही कहें या नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये अज्ञानी हैं, इतना तो पहली ही नज़र में समझ सकते हैं. क्योंकि देश की संपूर्ण जानकारी जब विदेशों में भेज दी गई और वे अंजान बन रहे हैं, या चुप हैं. अब इन सभी सांसदों से कहा गया है कि वे अपना आधार कार्ड फौरन बनवा लें.

हमारे संवादाताओं ने संसद के सांसदों से बातचीत की जिसमें सांसदों की एक बड़ी संख्या को यह पता ही नहीं है कि आधार कार्ड क्यों बना, आधार कार्ड के परिणाम क्या आने वाले हैं, आधार कार्ड का किसलिए इस्तेमाल होने वाला है? मुसलमान सांसदों की तो और खराब स्थिति है. उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जिस तरीके से दुनिया में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है और जिसका असर हिन्दुस्तान में भी दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल इस देश के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी किया जा सकता है. आधार कार्ड को कंट्रोल करने वाली बड़ी कंपनियों के मालिक इज़रायल से जुड़े हुए हैं और ये सांसद संसद की सुविधा का भोग करते हुए इस बात से अंजान हैं कि उनकी पूरी कौम के सामने किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात सिरे से खारिज कर दी. वहां पर मुकदमा चल रहा है कई भूतपूर्व जज और बड़े विशेषज्ञ आधार कार्ड से उत्पन्न खतरे के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि लगभग यह फैसला है कि आधार कार्ड को कहीं पर अनिवार्य न माना जाये. लेकिन भारत की मौजूदा सरकार आधार कार्ड को हर जगह अनिवार्य बना रही है. वस्तुत: भारत की सरकार सुप्रीमकोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रही है. इसका एहसास न राज्यसभा के सांसदों को है न लोकसभा के सांसदों को है. किसी ने एक शब्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार कार्ड को लागू करने की केंद्रीय सरकार की मंशा के ऊपर न राज्यसभा में कहा, न लोकसभा में कहा.

सुप्रीमकोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में नहीं आता है कि बड़े पैमाने पर केंद्रीय सरकार के फैसले अखबारों में छप रहे हैं और उसके फैसले के खिलाफ केंद्रीय सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य करती जा रही है. वहीं सुप्रीमकोर्ट के माननीय जज इस फैसले को पढ़ते हुए केंद्रीय सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.

सवाल उठता है कि आधार कार्ड बनने के बाद, इसकी जानकारी या इसके बनाने का जिम्मा अमेरिकी तकनीकि विशेषज्ञों को क्यों दिया गया? क्या हमारे देश में अपना सर्वर बनाया नहीं जा सकता था? क्या जानकारी हम अपने पास नहीं रख सकते थे? फिर अगर कोई भीतराघात होता या हमारी जानकारी विदेशों में जाती तो हमारे अपने लोग इसके लिए जिम्मेदार होते. या हम उसके ऊपर तकनीकी पहरा बैठा सकते थे. पर हमने जान-बूझकर ये सारी जानकारी विदेशियों के हाथ में दे दी.

इससे भी मजे की बात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो सरकार में आते हैं तो आधार कार्ड को नहीं मानेंगे. भारतीय जनता पार्टी ऑन रिकार्ड कह चुकी है कि अगर वो सत्ता में आती है तो आधार कार्ड को बैन (प्रतिबंधित) कर देगी. लेकिन अचानक वित्त मंत्री अरुण जेटली से नंदन नीलेकणी की मुलाकात होती है. लगभग एक घंटे बंद कमरे में बातचीत होती है और श्री अरुण जेटली और भारत की सरकार कांग्रेस से ज्यादा सख्त रूप से आधार कार्ड को लागू करने में लग जाती है. न भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने वायदे पर कायम रहती है और न श्री नरेंद्र मोदी पुराने वायदे पर कायम रहते हैं. आखिर में आपको बता दें कि हिटलर ने जब हत्याएं कीं, तो उन सारे यहूदियों के नाम, पता, उन्हें अमेरिका की आईबीएम कंपनी ने उपलब्ध कराये थे. जर्मनी में आधार कार्ड जैसे शिनाख्ती कार्ड आईबीएम ने ही बनाये थे. अब भारत के मासूम और समझदार सांसदों को देशद्रोही कहें या नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये अज्ञानी हैं, इतना तो पहली ही नज़र में समझ सकते हैं. क्योंकि देश की संपूर्ण जानकारी जब विदेशों में भेज दी गई और वे अंजान बन रहे हैं, या चुप हैं. अब इन सभी सांसदों से कहा गया है कि वे अपना आधार कार्ड फौरन बनवा लें. सभी सांसद बनवाएंगे भी, क्योंकि जब देश की जानकारी बाहर चली गई है, तो इन नए चुने सांसदों की जानकारी भी तो विदेशों में जानी है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का विचार ढह रहा है

जिन्ना ऐसा देश नहीं चाहते थे जो धर्म के आधार पर चले. वे धार्मिक इंसान नहीं थे और इस्लाम की विचारधार पर बहुत ध्यान नहीं देते थे. देवबंद के भक्त मुसलमान और दूसरी संस्थायें मुस्लिम स्टेट की विचारधारा के खिलाफ थीं क्योंकि यह इस्लाम की विचारधारा के ख़िलाफ था. जिन्ना एक उदारवादी संवैधानिक राष्ट्र चाहते थे. जिसमें मुसलमानों का आधिक्य हो.

हाफिज सईद ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान की स्थापना एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुई थी जहां भविष्य में शरिया कानून लागू होना था. वे वर्तमान प्रारूप से बुरी तरह खफा हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट बनने में दिक्कतें आ रही हैं. इमरान खान भी दूसरे कारणों से सिस्टम से खफा हैं.

बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान जंग में मिली हार की वर्षगांठ पर पाकिस्तान के स्वरूप को लेकर विचार करने का समय आ गया है. इसपर विचार करने पर हमें इस बात की जानकारी भी मिल सकती है कि आखिर देश अपने आपको बर्बाद कैसे करते हैं. किसी भी अन्य बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कैसे देश आखिर अपने राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं. जिसमें इतिहास के भीतर काफी गड़बड़ियां नज़र आती हैं.

मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे. वे एक उदार कांस्टीट्यूशनलिस्ट थे. जो गोपाल कृष्ण गोखले की परंपरा के थे और उन्होंने कोर्ट में बाल गंगाधर तिलक का केस भी लड़ा था. 1916 में लखनऊ में कांग्रेस की एक मीटिंग में वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे. वे गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने से दुखी थे. उन्होंने खिलाफत का समर्थन नहीं किया था. वे आधुनिकतावादी पहले थे और मुसलमान बाद में. इसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और लंदन जाकर वकालत करने लगे.

यही वह समय था जब उन्होंने अपने राष्ट्र की कल्पना को साकार किया. पूरे यूरोप में उस समय नए राष्ट्र बन रहे थे. ये सारी होमोजीनियस कम्यूनिटी थीं, जिनकी भाषा एक थी. उस समय बने नए यूरोपीय देशों के की एक ही भाषा थी और एक ही इतिहास. जिन्ना ने अपने राष्ट्र का विचार यहीं से उठाया, लेकिन उनका मूल आधार धर्म था. वे अंग्रेजों के जाने के बाद अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिक अधिकार वाला एक राष्ट्र चाहते थे. जहां उनके अधिकार उन्हें पूरी तरह मिल सकें. लेकिन उन्हें मिला एक नेशन स्टेट.

जिन्ना ऐसा देश नहीं चाहते थे जो धर्म के आधार पर चले. वे धार्मिक इंसान नहीं थे और इस्लाम की विचारधार पर बहुत ध्यान नहीं देते थे. देवबंद के भक्त मुसलमान और दूसरी संस्थायें मुस्लिम स्टेट की विचारधारा के खिलाफ थीं क्योंकि यह इस्लाम की विचारधारा के ख़िलाफ था. जिन्ना एक उदारवादी संवैधानिक राष्ट्र चाहते थे. जिसमें मुसलमानों का आधिक्य हो.

उनकी मौत के बाद एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का विचार ढहना शुरु हो गया. ब्रिटिश भारत में रह रहे अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान गए ही नहीं. उन्होंने पंजाबी, पठान और पश्चिमी पाकिस्तान की सिंधी भाषा या संस्कृति को साझा नहीं किया. उन्होंने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को अपना भाई-बहन माना ही नहीं. पाकिस्तान 1971 में दो भागों में टूट गया. फिर भी इसकी समस्याएं खत्म नहीं हुईं. एक राष्ट्र के रूप में यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच लटकता रहा. चार अलग-अलग क्षेत्रों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने का कोई उपाय नहीं है. उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो समावेशी विकास और जुड़ाव की बात कर सके. पाकिस्तान में ललो तंत्र के कमजोर होने का यही कारण है.

इस्लामबाद के उदय के बाद से ही इसे आतंकवादियों की आंतरिक तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान को धर्म के हिसाब से चलाना चाहते हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में तालिबान के साथ युद्ध की स्थिति में है. लेकिन तालिबान राष्ट्र का निर्माण नहीं करता है. वे कुछ कट्टर अल्पसंख्यकों द्वारा बाकी पर शासन करना चाहते हैं. अगर सेना हस्तक्षेप न करे तो तालिबान आम जनता के ऊपर अपने विचार थोपना शुरु कर देगी.

राष्ट्रीयता की कमजोरी ही पाकिस्तान में सभी पक्षों को भारत के साथ दुश्मनी करने के लिए प्रेरित करती है और कश्मीर को इसके लिए एक कारण बनाती है. राष्ट्र के रूप में कई वजहों से एक अपूर्ण प्रोजेक्ट बन कर रह गया है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है धर्म. यहां तक कि एक अद्वैतवादी भी अलग-अलग भाषाओं में बोलने और विभिन्न ऐतिहासिक विरासत वाले लोगों को साथ नहीं बांध सकता. कश्मीर जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो सभी पाकिस्तानियों को ललचाता है.

यह एक दूर का सपना है और वे जानते है कि वे इसे कभी हासिल नहीं कर पायेंगे. यह मानना मुश्किल है कि जमीन का यह टुकड़ा चार भाषाओं और क्षेत्रों में असमान रूप से बंटे एक राष्ट्र को एक साथ ला सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

डेंटल क्लीनिक में भी हो सकता है

एचआईवी/हेपेटाइटिस संक्रमण

डॉ. सुमित दुबे

क्या आप भी बिना सोचे-समझे किसी भी डेंटल क्लीनिक मे इलाज के लिए पहुंच जाते हैं? अगर हां, तो जरा संभल जाइए! यदि आपके डॉक्टर ने क्लीनिक के उपकरणों को सही तरीके से स्टेरलाइज नहीं किया है तो यहां से आप हेपेटाइटिस और एचआईवी/एड्स के संक्रमण की चपेट मे आ सकते हैं. मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के एक्स सीनियर कंसलटेंट डॉ. सुमित दुबे इस बारे में दे रहे हैं पूरी जानकारी:

डॉ. सुमित दुबे

शुरुआत में नहीं दिखते हैं लक्षण

एचआईवी/एड्स अथवा हेपेटाइटिस के बारे में जब तक मरीज को पता लगता है तब तक यह बीमारी उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुकी होती है. इस बीमारी के अधिकतर मामलों में मरीज में संक्रमण होने के पांच सालों बाद लक्षण सामने आते हैं. ऐसे में यह याद रखना बेहद मुश्किल होता है कि इसकी वजह क्या थी? इसकी कई वजहें हो सकती हैं. डेंटल क्लीनिक विजिट भी इनमें से एक वजह हो सकती है.

हर साल लाखों लोग आते हैं इन बीमारियों की चपेट में

देश में एड्स का पहला मामला 1986 में दर्ज किया गया था. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक भारत में साल 2011 में 1.48 लाख लोगों की मौत एड्स से हुई थी. इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक देश में हर साल 2.4 लाख लोग हेपेटाइटिस-बी वायरस संबंधी जटिलताओं का ग्रास हर साल बनते हैं. आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों ही बीमारियों के मामले में स्थिति गंभीर है. इसके पीड़ितों के इलाज के साथ-साथ एचआईवी और हेपेटाइटिस वायरस के प्रसार को रोकने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. डेंटल क्लीनिकों में बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल मरीजों पर किया जाता है, ऐसे में यह जगह संक्रामक बीमारियों के प्रसार हेतु हाई-रिस्क जोन में आती हैं. ये वे जगहें होती हैं जहां संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्कता होती है.

अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर है सबसे बड़ा खतरा

भारत में छोटे शहरों और कस्बों में हर दो कदम पर जेन्ट्स सैलून की तरह छोटे-छोटे डेंटल क्लीनिक खुले हुए हैं. दांतों की देखभाल का 97 प्रतिशत हिस्सा बाजार अनियोजित क्षेत्र के हाथों में है ऐसे में एक आम दिशा-निर्देश बनाकर हर जगह इसका पालन करवाना टेढ़ी खीर है. मौजूदा समय में ऐसे डेंटल

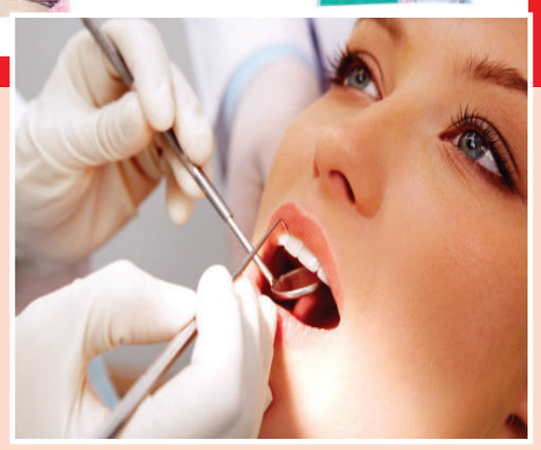

सेंटर महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां सभी मानकों का गंभीरता से ध्यान रखा जाता है.

इन बातों पर करें गौर

-मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानें: मरीज की जांच शुरू करने से पहले इसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है. अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप इलाज के दौरान ज्यादा सावधानी बरतेंगे और इलाज में इस्तेमाल किए गए औजारों की सफाई ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे.

- औजारों की कैटेगरी के हिसाब से करें स्टेरलाइज: औजारों के स्टेरलाइजेशन का बेहतरीन परिणाम तभी मिल सकता है जब आप गंभीरता पूर्वक इन उपकरणों की श्रेणी के हिसाब से उनका स्टेरलाइजेशन करें. इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

1. **क्रिटिकल इन्स्ट्रुमेंट-** ये उपकरण कोशिकाओं को भेदते हैं और रक्त ब्लड के संपर्क में आते हैं. हर बार इस्तेमाल के बाद इन्हें अच्छी तरह से स्टेरलाइज करना जरूरी होता है. इसके लिए ऑटोक्लेव यानी स्टीम हीटिंग, ड्राई हीट अथवा हीट केमिकल वैपर का इस्तेमाल किया जाता है. क्रिटिकल इन्स्ट्रुमेंट में फोरसेप, स्कल्पेल और सर्जिकल बर्स आदि शामिल हैं.

2. **सेमी-क्रिटिकल इन्स्ट्रुमेंट-** ये औजार, जैसे कि मिरर, दोबारा इस्तेमाल योग्य इंप्रेशन ट्रे आदि कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आते हैं लेकिन ये खुली हुई त्वचा के संपर्क में आते हैं. ऐसे में संक्रमण फैलाने की वजह जरूर बन सकते हैं. इन्हें भी स्टेरलाइज करने की जरूरत होती है. अगर इन उपकरणों को स्टेरलाइज नहीं किया जा सकता है तो इन्हें संक्रमण मुक्त करने के लिए उच्च-कोटि के डिसइन्फेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

3. **नॉन-क्रिटिकल इन्स्ट्रुमेंट-** इन इपकरणों से संक्रमण के प्रसार का खतरा बेहद कम होता है क्योंकि ये शायद ही खुली हुई त्वचा के संपर्क में आते हैं. इनमें एक्स-रे हेड्स, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर कफ आदि इस श्रेणी में आते हैं. लेकिन इन्हें भी डिस-इनफेक्टेंट से साफ जरूर किया जाना चाहिए.

- इस्तेमाल न होने पर पैक करके रखें औजार: सभी औजारों को स्टेरलाइज करने के बाद इन्हें पाउच में पैक करके यूवी चैंबर में रखें ताकि ये दोबारा संक्रमित होने से बचे रहें. सबसे अच्छा और उपयुक्त तरीका होता है इस पाउच को मरीज के सामने खोलें ताकि वह भी इस बात को लेकर पूरी तरह संतुष्ट रहे कि यहां स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया सही ढंग से अपनाई जाती है.

- डिस्पोजेबल चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल- जहां भी डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल हो सकता है वहां इन्हें ही अपनाना चाहिए. सिरिंज, कार्टिजेज, ग्लास, पट्टी, दस्ताने आदि को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए. जितना ज्यादा डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल होगा संक्रमण का खतरा उतना कम रहेगा.

-उपयुक्त स्टेरलाइजेशन के लिए बीजाणुओं की जांच- कई बार ऑटोक्लेव सही ढंग से काम नहीं करता है. ऐसे में स्टेरलाइजेशन का कोई फायदा नहीं होता. ऐसे में क्रॉस कंटैमिनेशन और संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है. डेंटल क्लीनिकों को बीजाणु जांच जरूर करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऑटोक्लेव सही ढंग से काम कर रहा है अथवा नहीं.■

feedback@chauthiduniya.com

ईको सेंसिटिव जोन के मसले पर राजनीति

आपदा के बाद हुई क्षति की भरपाई के लिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी व स्वच्छता अभियान के संचालन के लिए राज्य को 10 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग शामिल है. ऋषिकेश का आईडीपीएल कारखाना व एचएमटी जैसे उपक्रमों को दोबारा शुरू करने की मांग पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरना चाहती है. आईडीपीएल व एचएमटी दोनों मुद्दे कांग्रेस के दस साल के कार्यकाल में भी प्रमुखता से उठे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

केंद्र सरकार की ओर से गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक ईको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के निर्णय के खिलाफ पूरे प्रदेश में फिर से राजनीति गरमाने लगी है. राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्र लिख कर केंद्र सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया है. दूसरी तरफ राज्य के भाजपा नेता भी इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं. ईको सेंसिटिव जोन से प्रभावित गंगा घाटी के ग्रामीण भी इस फैसले के खिलाफ भाजपा के साथ लामबंद होने लगे हैं. यह मसला कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है. गंगोत्री से उत्तरकाशी तक ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने से गंगा सहित अन्य कई नदियों में निर्माणाधीन और प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो गये हैं. गंगा की अविरलता और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार पहले ही गंगा घाटी में निर्माणाधीन 600 मेगावाट क्षमता की लोहारी नागपाला, 450 मेगावाट क्षमता की पाला मनेरी सहित कई प्रस्तावित छोटी-बड़ी जल विद्युत परियाजनाओं को बंद करने का फरमान जारी कर चुकी है. सरकार के इस निर्णय का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था. लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिकों और बांध विरोधियों के विरोध के कारण सरकार अपने निर्णय पर अड़िग रही. इस निर्णय से खासकर 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने वाली लोहारी नागपाला जलविद्युत परियोजना पर एनटीपीसी करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी. परियोजना निर्माण में जल, जंगल और जमीन को जो नुकसान होना था और इसकी भरपाई करना संभव नहीं है. क्षेत्र के लोगों के लिए खोखले हुए पहाड़ों का हर दिन दरकना परेशानी का सबब बना हुआ है. गंगा वैली में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से शुरू कराने का राज्य सरकार प्रयास कर रही थी.

ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए तैयार किये गये ड्राफ्ट में तय मानकों के अनुसार नदी तट से पांच किमी के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. साफ है कि गंगा वेली में जो स्थिति वर्तमान समय में है, उसमें किसी तरह छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवन, सड़क और निजी भवनों का निर्माण भी बिना अनुमति के इस क्षेत्र में नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा खनन आदि पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. ईको सेंसिटिव जोन को लेकर दो साल पहले भी क्षेत्र में खूब हल्ला हुआ है. भाजपा सहित कई संगठनों से जुड़े लोगों ने इसके विरोध में कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया. इतना ही नहीं कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था और इस कानून को रद्द करने का जनता को आश्वासन दिया था. अब केंद्र में भाजपा की सरकार है और ईको सेंसिटिव जोन घोषित करना या न करना केंद्र के निर्णय पर ही निर्भर है. फिर भी भाजपा की राज्य इकाई ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है. इसने राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय विधायकों को भी घेरना शुरू कर दिया है. देखना यह है कि भाजपा का विरोध ईको सेंसिटिव जोन को हटाने में कितना कामयाब होगा. यह तो आने वाला समय ही बतायेगा. फिलहाल स्थानीय विधायक व राज्य सरकार के समक्ष यह मसला काफी पेचिदा हो गया है. इसका सीधा असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ने की भी पूरी संभावना है.

बहरहाल, कई मुद्दों पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एजेंडे में जल विद्युत परियोजनाओं का मुद्दा ही नहीं है, जबकि जल विद्युत परियोजनाओं का मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज्वलंत है. दिलचस्प बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है, उनमें कई ऐसे हैं जिन पर दस साल से सियासत हो रही है. मसलन, एक मांग यह है कि राज्य के समुचित विकास के लिए अगले दस वर्षों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की शुरुआत की जाए. विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग राज्य सरकार साल 2010 से लगातार करती आ रही है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. इस बीच राज्य की पांच लोकसभा सीटों में चार कांग्रेस के पास थी.

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा ग्रीन बोनस, आपदा के बाद हुई क्षति की भरपाई के लिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी व स्वच्छता अभियान के संचालन के लिए राज्य को 10 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग शामिल है. ऋषिकेश का आईडीपीएल कारखाना व एचएमटी जैसे उपक्रमों को दोबारा शुरू करने की मांग पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरना चाहती है. आईडीपीएल व एचएमटी दोनों मुद्दे कांग्रेस के दस साल के कार्यकाल में भी प्रमुखता से उठे हैं.

वर्ष 2004 से 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार रही है. जिन सात मुद्दों को लेकर कांग्रेस दिल्ली में राज्य की आवाज उठाने जा रही है इनमें केंद्र सरकार की सेवाओं में राज्य को आरक्षण की परिधि में लाया जाए. चूंकि सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां जिन राज्यों की उत्तराखंड के समान हैं, वे राज्य केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

2014: विश्व की प्रमुख घटनाएं

दुनिया एक गांव बनती जा रही है. ग्लोबलाइजेशन का असर आज दुनिया के हर एक देश पर पड़ रहा है. ऐसे में दुनिया के किसी भी हिस्से में घटने वाली छोटी सी छोटी घटना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वर्तमान समय में प्रत्येक घटना पर निगाह रखना, उससे रूबरू होना, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जरूरत भी बन गई है. बीतते साल कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना जिसका दूरगामी असर होने वाला है. इसलिए यह जरूरी है कि हम एक बार 2014 की प्रमुख वैश्विक घटनाओं पर एक नजर डालें.

6 जनवरी : अमेरिकी गृह मंत्री जॉन केरी इजराइल-फिलिस्तीन के बीच बातचीत के किसी फ्रेमवर्क पर सहमती के बिना ही अपने चार दिन के पश्चिम एशिया दौरे से वापस स्वदेश लौट गये.

8 जनवरी : एक फ्रेंच कोर्ट ने एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर नकाब पहने के जुर्म में 150 यूरो का जुर्माना किया और एक महीने के निलंबन की सजा सुनाई.

12 जनवरी : बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्री परिषद् ने शपथ ली.

22 जनवरी : पर्यटन उद्योग को हो रहे नुक़सान के मद्देनज़र थाईलैंड ने बैंकाक से स्टेट ऑफ इमरजेंसी हटाने का फैसला किया.

28 जनवरी : यूक्रेन के प्रधानमंत्री म्कोला अजारोव ने देश की राजनीतिक अस्थिरता के शांतिपूर्ण हल के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

29 जनवरी : मेहदी जोमा ट्युनिशिया के प्रधानमंत्री बने. इस सरकार ने अरब क्रांति के बाद देश में पैदा हुई राजनितिक अस्थिरता से निपटने के लिए बनी इस्लामिस्ट सरकार की जगह ली.

30 जनवरी : भारत सरकार और फिजी ने डबल टैक्सेशन अवाइडेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किये.

31 जनवरी : पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदालत में हाज़िर नहीं होने के लिए की अपील के जवाब में एक गैर ज़मानती वारंट जारी किया.

11 फरवरी : चीन और ताइवान के अधिकारियों ने 1949 में चीनी गृह युद्ध के खात्मे के बाद पहली बार द्विपक्षीय वार्ता की.

20 फ़रवरी : जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लगभग 100 टन रेडियो एक्टिव पानी का रिसाव हुआ.

22 फ़रवरी : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने सीरिया को मानवीय आधार पर सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी.

22 फ़रवरी : मैटीओ रेंजी इटली के नये प्रधानमंत्री चुने गए. उन्होंने एनरिको लेटा की जगह ली.

28 फ़रवरी : भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये.

01 मार्च : रुसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने कीव में रूसियों की सुरक्षा की बात करते हुए अपनी सेना क्रीमिया भेज दी. रूस के इस क़दम की पूरी दुनिया में निंदा की गई. ओबामा ने इसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करार दिया.

7 मार्च : सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड (अख्वानुल मुसलमीन) को आतंकी संगठन घोषित किया.

8 मार्च : मालदीव, श्रीलंका एवं भारत के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई. बैठक में तीनों देशों ने निर्धारित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की.

17 मार्च : क्रीमिया की संसद ने यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और औपचारिक तौर पर रूस से क्रीमिया को अधिग्रहित करने की अपील की. 16 मार्च को क्रीमिया के तकरीबन 97 प्रतिशत लोगों ने यूक्रेन से अगल होने की इच्छा जाहिर की.

17 मार्च : सीरिया की सेना ने हिजबुल्लाह की सहायता से लेबनान की सीमा से लगे याब्रौद शहर को विद्रोहियों के कब्जे से वापस छीन लिया.

24 मार्च : दो घंटे की सुनवाई के बाद मिस्र के मताय शहर की एक आदालत ने 529 लोगों को मौत की सजा सुनाई. इन पर आरोप था कि इन्होंने राष्ट्रपति मुहम्मद मोरसी को अपदस्थ किये जाने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों की हत्या की.

26 मार्च : उत्तरी-कोरिया ने मध्यम दूरी की दो मिसाइलों का परीक्षण किया जो जापान और उत्तर कोरिया के बीच समुद्र में गिरा. 2009 के बाद यह पहली ऐसी घटना है.

31 मार्च : उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवादिती पश्चिमी सीमा पर गोलाबारी हुई.

31 मार्च : मनुएल वॉल्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए.

1 अप्रैल : जापान कैबिनेट ने हथियारों के निर्यात पर खुद के लगाये दशकों पुराने प्रतिबंध को समाप्त करने को मंजूरी दी. जापान में यह प्रतिबंध 1967 से लगे थे.

05 अप्रैल : तालिबान की चुनाव बॉयकाट की धमकियों के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक रहा.

14 अप्रैल: नाइजीरिया की इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोकोहरम ने 280 लड़कियों का अगवा किया.

15 अप्रैल : इराक ने विवादित अबू ग़रीब जेल को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की. यह वही बदनाम जेल है जिसमें अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने इराकी कैदियों के साथ शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार किया था.

4 मई : वियतनाम ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन के जहाजों से वियतनाम के जहाजों पर हमले हुए हैं.

17 मई : अफ्रीकी देश माली में सरकार और विद्रोही तौरेग लड़ाकों के बीच हुई झड़पों में 50 से अधिक सैनिक मारे गये.

20 मई : थाईलैंड के आर्मी चीफ ने पुरे देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी. 22 मई को उन्होंने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट किया.

25 मई : पेट्रो पोरोशेनको ने युक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता.

28 मई : मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अबुल फतह अल-सीसी को कामयाबी मिली. उन्हें 90 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल हुए.

31 मई : अमेरिका ने तालिबान द्वारा बंधक बनाए गए अपने सैनिक ब्रिगेडियर बर्गडहल की रिहाई के बदले ग्वातनामो-बे जेल में बंद 5 शीर्ष तालिबान नेताओं को छोड़ दिया. अफ़गानिस्तानी राष्ट्रपति हामिद करज़ई को इस समझौते की जानकारी अंत तक नहीं थी.

2 जून : फिलिस्तीन की एकता सरकार में हमास भी शामिल.

3 जून : एक विवादास्पद चुनाव में सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल असद पुनः निर्वाचित हुए.

9 जून : तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हमला कर दिया. आतंकी संगठन और सेना के बीच हुई गोलीबारी में कुल 29 लोग मारे गए.

11 जून : आईएसआईएस ने इराक के मोसुल शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया.

20 जून : यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेनको ने एक हफ्ते के एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की. इस से पहले विद्रोहियों ने युक्रेन के एक मालवाहक फौजी जहाज़ को मार गिराया था.

30 जून : हांगकांग के एक लोकतंत्र समर्थक ग्रुप ने जनमत संग्रह करवाया. जिसमें 8 लाख लोगों में से 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस द्वीप के चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव में यहां के नागरिकों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होनी चाहिए. इस जनमत संग्रह के बाद हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए थे.

1 जुलाई : यूक्रेन के आतंकियों ने हवाई हमले कर के पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया. इस दौरान एक महीने में तकरीबन 1130 लोग मारे गए जिसमें 800 आम नागरिक थे.

1 जुलाई : आईएसआईएस ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रखते हुए अपना क्षेत्र इराक के अनबार प्रोविंस (पश्चिमी बगदाद) तक बढ़ा लिया.

2 जुलाई : वेस्ट बैंक में तीन इजरायली युवाओं की हत्या और एक लापता फिलिस्तिनी युवक का शव मिलने के बाद इलाके में तनाव बढ़ा. पूर्वी येरूशलम में दंगा भड़का और दोनों देशों के बीच राकेट हमले शुरू हो गये. एक महीने तक यही माहौल बना रहा. इसमें 1410 फिलिस्तीनी और 59 इजरायली नागरिक मारे गये.

17 जुलाई : मलेशियन एयरलाइन्स की एसटरडर्म से क्वालालंपुर जा रही फ्लाइट संख्या एमएच-17 यूक्रेन के नजदीक क्रैश हो गया. इस हादसे में फ्लाइट में सवार सभी 298 यात्रियों की मौत हो गई. इस मामले में कहा गया कि इसे इसे विद्रोहियों ने मार गिराया.

24 जुलाई : यूक्रेन के प्रधानमंत्री यात्सेन युक ने इस्तीफा दिया.

07 अगस्त : राष्ट्रपति ओबामा ने आईएसआईएस पर अमेरिका की ओर सीमित हवाई हमले शुरु किए जाने को स्वीकृति दी.

19 अगस्त : आईएसआईएस ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की गला काटकर हत्या की.

31 अगस्त : चीन ने हांगकांग में लोकतांत्रिक चुनाव की मांग को खारिज किया.

01 सितंबर : एक लाख तीस हजार कुर्दिश शरणार्थी उत्तर-मध्य सीरिया से भाग कर तुर्की पहुंचे.

02 सितंबर : आईएसआईएस ने दूसरे अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सोटलॉफ की गला रेत कर नृशंस हत्या की.

18 सितंबर : स्कॉटलैंड के लोगों ने ब्रिटेन से अलग राष्ट्र बनाने के लिए हुए जनमत संग्रह में प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया.

28 सितंबर : हांगकांग में चल रहे जनविरोध को खत्म करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई शुरु हुई.

14 अक्टूबर : अमेरिका ने आईएसआईएस पर नियंत्रण के लिए सीरिया के नजदीक कोबानी पर हवाई हमला किया.

12 अक्टूबर : बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोराल्स तीसरी बार चुनाव में विजयी हुये.

13 अक्टूबर : फिलिस्तीन को राजनयिक पहचान देने के लिए ब्रिटेन ने वोट किया. 12 के मुकाबले 274 वोट से ब्रिटिश संसद ने इसे मंजूर किया.

22 अक्टूबर : कनाडा की संसद पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया.

11 नवंबर : चीन और अमेरीका के बीच जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ. योजना के मुताबिक साल 2030 तक दोनों देश उत्सर्जन वृद्धि को रोकेंगे.

16 नवंबर : 43 कॉलेज छात्रों के अपहरण और कथित तौर पर उनकी हत्या के मसले पर मैक्सिको में हजारों लोगों ने विरोध किया.

22 नवंबर : अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अगले साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने की हामी भरी.

23 नवंबर : ईरान ने अमेरिका और पांच अन्य देशों के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के संबंध में ऐतिहासिक समझौता किया.

25 नवंबर : हांगकांग में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी.

29 नवंबर : मिस्त्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को उनके ईपर लगे सारे आरोपों से बरी कर दिया.

2 दिसंबर : इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहु ने दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल दिया और फिर से चुनाव के लिए कहा.

14 दिसंबर : हांगकांग विरोध समाप्त हुआ. चीन ने किसी भी तरह की रियायत नहीं दी. लेकिन प्रदर्शकारियों ने यह जता दिया कि वे सरकार का विरोध कर सकते है और उसे चुनौती दे सकते हैं. 1989 के थ्यानमेन स्कवैयर विरोध के बाद यह चीन में हुआ पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन है.

15 दिसम्बर : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक अदालत ने पूर्व सेना अध्यक्ष कर्नल बेदी मोबुली इंगाएंगेला को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में उम्र क़ैद की सजा सुनाई.

16 दिसंबर : आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान ने पेशावर के एक स्कूल में घुस कर हजारों बच्चों को बंधक बनाकर फायरिंग की. इस नृशंस हत्याकांड में 140 बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए. तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ये हमला उन्होंने सेना से बदला लेने के लिए किया था. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

> प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है, उसे जीवनपर्यन्त कोई दुःख नहीं होता. चिंता न करो, यह उदी लो और उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ. ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा. यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा, उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा.

बाबा रोगों को दूर करते हैं

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो

नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे. उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था. उन्होंने कई डॉक्टरों से उसका इलाज कराया. यहां तक कि उसकी शल्य-चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई फायदा न हुआ. उसको असहनीय कष्ट था. उनके मित्र और संबन्धियों बालक के माता-पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईबाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग ठीक करने के लिए हैं. अतः माता-पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए. उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री-चरणों में बालक को डाल दिया और विनती की कि बाबा, इस बालक की रक्षा कीजिए. प्रभु हमें तो केवल आपका ही भरोसा है. प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है, उसे जीवनपर्यन्त कोई दुःख नहीं होता. चिंता न करो, यह उदी लो और उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ. ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा. यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा, उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा. बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया. वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर देखने लगे. रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया. माता-पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए.

यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई. इसी समय जब वे कार्यवश मुंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे मुंबई चले गए. वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन मुंबई में उन्हें लगातार तीन रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो. तब डॉक्टर ने अपना विचार परिवर्तित कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्यय किया. मुंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई चिन्ह दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े. उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः साधारण स्थिति पतर पहुंच गया. तब वे अपने निश्चयानुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया. बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए. डॉक्टर वहां चार दिन ठहरे और उदी तथा आर्शीवाद प्राप्त कर घर वापस आ गए. एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण वीजापुर को हो गया. भतीजे का रोग दूर होना, उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साई के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी.

बाबा की दूसरी कथा.....

डॉक्टर पिल्लै बाबा के एक निष्ठवान भक्त थे. इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे. उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही रहें. एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया. वे काकासाहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कराण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं. जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें. मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले दस जन्मों में भोगने को तैयार हूं. तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई. साई तो दया के अवतार ही थे. वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे. उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है. कर्मों का फल दस जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा. केवल दस दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे. मैं तो यहां तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूं. प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए. जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहां ले आओ, मैं सदा के लिए उनको कष्टों से छुटाकारा कर दूंगा. तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया. बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा मिल जाए. पिल्लै के पैर पर सफाई करने वाले व्यक्ति का पैर पड़ गया और उनके नासूर से कीड़े निकल गए. जिसके बाद बाबा उनसे कहा जाओ अब आराम करो, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा. हमारे कर्म ही सुख:दुख के कारण होते है, इसलिये जैसी भी परिस्थित आए, उसी में सन्तोष करना चाहिए. ईश्वर ही सब को फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है. ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो. वे ही तुम्हारी चिन्ता दूर करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

जानकारीपूर्ण समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र दिनांक (24-11-2014 से 30-11-2014) पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की कहानी त्रिया-चरित्र पढ़ा और आगे भी चौथी दुनिया समचार पत्र में प्रकाशित कहानी पढ़गा, समाचार पत्र में कहानी बहुत अच्छी होती हैं. गंगा मुक्ति अभियान में निर्णायक लड़ाई का संकल्प शीर्षक एवं स्वास्थ्य से संबंधी कॉलम में टीबी से बचाव के लिए कई नई जानकारी मिली. आशा है कि चौथी दुनिया समाचार पत्र में आगे भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण आलेख पढ़ने को मिलते रहेंगे.

-विनोद कुमार तिवारी, फारबिसगंज, बिहार.

भारतीय राजनीति

आज सजग नागरिक भी है, नेतृत्व भी है और दिशाएं भी स्पष्ट हैं, मोदी जी की अमेरिकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यस्था की प्रगति, रोजगार सृजन और साथ ही अर्न्तराष्ट्रीय बिरादरी के सामने राष्ट्र की सकारात्मक, समावेशी और समरस छवि का निर्माण करना था, ताकि विदेशी निवेश देश में आ सके. यह सर्वविदित है कि गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के मुताबिक गंदगी और उससे उपजी बीमारियों की वजह से एक औसत भारतीय को वर्ष में लगभग 6500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है और यह चोट सबसे अधिक मध्यम वर्ग और गरीबों पर ही पड़ती है. एक साफ पारदर्शी समाज तभी ही बनेगा, जब हम चाहेंगे. स्वच्छ भारत अभियान के समक्ष मौजूद चुनौतियों को पूरा करने के लिए नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा. कहा भी गया है कि स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है. आचरण के बिना ज्ञान केवल भार होता है. इंसान के रोबिटीकरण का यह दौर बेहद यातनादायक है. इससे बाहर निकलने की इच्छाशक्ति दिखानी होगी हर भारतीय को. भारतीय राजनीति में जितने भी माननीय नेता हैं उनके लिए एवं समस्त पार्टियों को राष्ट्र हित के लिए आत्मचिंतन का समय है. नए तरीके से मोदी जी ने जैसे देश में अभियान छेड़ा है उसकी पूरी विश्व में सराहना हो रही है. 125 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े होने की चाहत हमारे प्रधानमंत्री में दिखती है वह भी बिना किसी भेदभाव के जो भारतीय राजनीति की अच्छी शुरूआत है.

-गौरव निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

भारत का मान बढ़ाया

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों और अमेरिका के लोगों का दिल जीता है, वह अद्भुत है. 1989 में एक नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अमेरिका को प्रभावित किया था. विश्व धर्म की उदारता व विशालता से परिचित कराया था. एक राजनेता नरेन्द्र मोदी ने पुन: वर्षों बाद अपने विजन के माध्यम से विदेशियों का अपनी प्रतिभा का लोहा मानने को विवश कर भारत का मान बढ़ाया है.

-राज किशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सरकार का कामकाज

चौथी दुनिया समाचार पत्र का मैं नियमित पाठक हूं. आलेख-अखिलेश सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, कुछ में है दम, बाकी सब बेदम(01 दिसंबर-07दिसंबर 2014) पढ़ा. तथ्यपरक आलेख है. प्रभात रंजन दीन ने सही कहा है कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्रियों में है दम, बाकी सब बेदम. सरकार की कार्यप्रणाली पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव कई बार सवाल उठा चुके हैं और अखिलेश सरकार को आगाह भी कर चुके हैं. यूपी सरकार योजनाओं की घोषणा तो खूब करती है, लेकिन उस पर अमल कम ही होता है. अखिलेश सरकार को अपने कार्यप्रणाली सुधार लाना चाहिए. अगर अखिलेश सरकार इसी तरह कार्य करती रही, तो उसे आगमी यूपी विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है.

-कमल किशोर पांडेय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

संस्कृति की पहचान

हिन्दुस्तान विश्व संस्कृति की जननी है. इसी पावन धरती से अच्छाई, आविष्कार, खोज, चरित्र, आस्था, दैविक शक्ति, भक्ति एवं उपासना इत्यादि गुणों का आर्विभाव हुआ. यहीं से सब चीजें विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया, लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में ही उन सब चीजों का अभाव होता जा रहा है. आखिर क्यों? अगर लोग अपने अंदर झांक कर देखे तो इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा. मेरी नजर में इसका कारण लोगों का चारित्रिक पतन, नैतिक पतन, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान न होना और विदेशों की गलत चीजों की नकल करना है. नकल करना बूरी बात नहीं है, लेकिन नकल करें, लेकिन अच्छाईयों का न कि बुराईयों का.

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी में इन सब गुणों का समावेश है, तभी तो इतने विरोध के बाद भी पूर्ण बहुमत से सत्ता पर आसिन हुए. उनका विरोध देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा था. मगर वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, कर्मठता, स्वाभिमान, देश के लिए कुछ करने की चाहत के आगे सारे विरोधी परास्त हो गए. अच्छे दिन भी आएंगे, सबका साथ सबका विकास भी सार्थक होगा. मोदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सब ठीक हो जाएगा. जब उन्होंने जनता से साठ महीने का समय मांगा है, तो कम से कम साठ महीने तो इंतजार करना चाहिए. सरकार बने 6 महीने ही हुए हैं, अभी से हाय तौबा मचाने लगे हैं.

-बबीता कुमारी, समस्तीपुर, बिहार.

कहानी

सच्चा मित्र

गोलू-मोलू नाम के दो लड़के थे और दोनों पक्के दोस्त थे. गोलू जहां दुबला-पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल-मटोल था. दोनों एक-दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती. एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला. उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था.

उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी. दोनों चल दिए जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा. उसे देखकर दोनों भय से थर-थर कांपने लगे. तभी दुबला-पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था. उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया. उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते. वह तुरंत जमीन पर लेट गए और सांस रोक ली. ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण हैं ही नहीं. भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया.

जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था. भालू तुमसे कुछ कह रहा था. क्या कहा उसने ?

मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर न बुलाओ और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा. उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है.

सुनकर गोलू शर्मिन्दा हो गया. उसे अभ्यास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी. उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई. ■

शिक्षा-सच्चा मित्र वही है जो संकट के काम आए.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

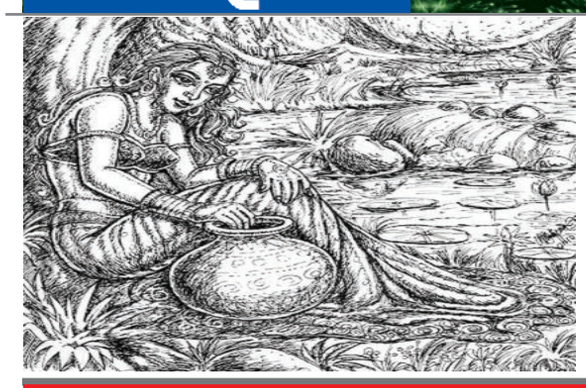

मगन दास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया. मुस्करा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूं कि वह बहुत सुंदर है. कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं, मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे स्वयं से डर लगता है. रंभा ने कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? ठीक है जो मन में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी. इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी रहूंगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे?

आलोचक का बुढ़भस

अनंत विजय

राग दरबारी तो घटिया उपन्यास है. मैं उसे हिंदी के पचास उपन्यासों की सूची में भी नहीं रखूंगा. पता नहीं, राग दरबारी कहां से आ जाता है? वह तीन कौड़ी का उपन्यास है. हरिशंकर परसाईं की तमाम चीजें राग दरबारी से ज़्यादा अच्छी हैं. वह व्यंग्य बोध भी श्रीलाल शुक्ल में नहीं है, जो परसाईं में है. उनके पासंग के बराबर नहीं हैं, श्रीलाल शुक्ल और उनकी सारी रचनाएं. यह बात कही है, हिंदी के बुजुर्ग लेखक एवं कथालोचक विजय मोहन सिंह ने. महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पत्रिका बहुवचन में कृष्ण कुमार सिंह ने विजय मोहन सिंह का साक्षात्कार किया है, जिसमें विजय मोहन सिंह ने ऐसी और भी कई मनोरंजक बातें कहीं हैं. एक जगह विजय मोहन सिंह कहते हैं, नागार्जुन का जिक्र मैंने अपनी किताब में काका हाथरसी के संदर्भ में भी किया था, जो बाद में मैंने हटा दिया. केदार जी उसे पढ़कर दु:खी हो गए थे. उन्होंने ही उसे निकलवा दिया. नागार्जुन की कमजोरियों का हाल तो यह है कि कई जगह उन्हें पढ़ते हुए लगा और मैंने लिखा भी कि वह बेहतर काका हाथरसी हैं. केदार जी इससे दु:खी एवं कुपित हो गए थे कि यह क्या कर रहे हैं? मैंने वह वाक्य हटा ज़रूर दिया, लेकिन मेरी ऑरिजिनल प्रतिक्रिया यही थी. कुल मिलाकर नागार्जुन की कमजोरियां वे नहीं हैं, जो निराला की हैं. इस तरह की कई बातें और फतवे विजय मोहन के इस साक्षात्कार में है, जहां वह प्रेमचंद के गोदान से लेकर शिवमूर्ति तक को खारिज करते हुए चलते हैं. विजय मोहन सिंह का यह पूरा साक्षात्कार पढ़ने के बाद लगता है कि वह हर जगह पर रचनाकारों का सतही मूल्यांकन करते हुए निकल जाते हैं. इस वजह से उनका यह साक्षात्कार सामान्यीकरण के दोष का भी शिकार हो गया है.

जिस तरह से विजय मोहन सिंह ने श्रीलाल शुक्ल के कालजयी उपन्यास-राग दरबारी को घटिया और तीन कौड़ी का उपन्यास कहा है, वह उनकी सामंती मानसिकता का परिचायक है. ऐसी भाषा बोल कर विजय मोहन सिंह ने खुद का स्तर थोड़ा नीचे किया है. साहित्य में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए. किसी भी कृति को लेकर किसी भी आलोचक का अपना मत हो सकता है, उसके प्रकटीकरण के लिए भी वह स्वतंत्र होता है, लेकिन मत प्रकटीकरण मर्यादित तो होना ही चाहिए. अपनी किताब-हिंदी उपन्यास का इतिहास में गोपाल राय ने भी राग दरबारी को असफल उपन्यास करार दिया है. उन्होंने इसकी वजह उपन्यास और व्यंग्य जैसी दो परस्पर विरोधी अनुशासनों को एक-दूसरे से जोड़ने के प्रयास को बताया है. गोपाल राय लिखते हैं, व्यंग्य के लिए कथा का उपयोग लाभदायक होता है, पर उसके लिए उपन्यास का ढांचा भारी पड़ता है. उपन्यास में व्यंग्य का उपयोग उसके प्रभाव को धारदार बनाता है, पर पूरे उपन्यास को व्यंग्य के ढांचे में फिट करना रचनाशीलता के लिए घातक होता है. व्यंग्यकार की सीमा यह होती है कि वह चित्रणीय विषय के साथ स्वयं को एकाकार नहीं कर पाता है. वह सृष्टा से अधिक आलोचक बन जाता है. सृष्टा अपने विषय से अनुभूति के स्तर पर जुड़ा होता है, जबकि व्यंग्यकार जिस वस्तु पर व्यंग्य करता है, उसके प्रति निर्मम होता है. यहां गोपाल राय ने किसी आधार को उभारते हुए राग दरबारी को असफल उपन्यास करार दिया है, लेकिन उन्होंने भी इसे घटिया या तीन कौड़ी का करार नहीं दिया है.

ऐसा नहीं है कि राग दरबारी को पहली बार आलोचकों ने अपने निशाने पर लिया है. जब 1968 में यह उपन्यास छपा था, तब इसके शीर्षक को लेकर श्रीलाल शुक्ल पर हमले और उनके संगीत ज्ञान पर सवाल खड़े किए गए थे. आरोप लगाने वाले ने यहां तक कह दिया था कि श्रीलाल शुक्ल को न तो संगीत के रागों की समझ है और न दरबार की. लगभग आठ-नौ साल बाद जब भीष्म साहनी के संपादन में 1976 में आधुनिक हिंदी उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तो उसमें श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था, दूसरों की प्रतिभा और कृतित्व पर राय देकर कृति बनने वाले हर आदमी को बेशक दूसरों को अज्ञानी और जड़ घोषित करने का हक़ है, कुछ हद तक यह उसके पेशे की मजबूरी भी है, फिर भी किताब पढ़कर कोई भी देख सकता है कि संगीत से इसका कोई सरोकार नहीं है. और, शायद मेरा समीक्षक भी जानता है कि यह राग उस दरबार का है, जिसमें हम देश की आज़ादी के बाद और उसके बावजूद आहत, अपंग की तरह डाल दिए गए हैं या पड़े हुए हैं.

हिंदी के आलोचकों के निशाने पर होने के बावजूद राग दरबारी अब तक पाठकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है. अब भी पुस्तक मेलों में राग दरबारी और गुनाहों का देवता को लेकर पाठकों में उत्साह देखने को मिलता है. इसकी कोई तो वजह होगी कि अपने प्रकाशन के 46 वर्षों के बाद भी राग दरबारी पाठकों की पसंद बना हुआ है. अब तक इसके हार्ड बाउंड और पेपर बैक मिलाकर 72 से ज़्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं. इनमें छात्रोपयोगी संस्करणों की संख्या शामिल नहीं

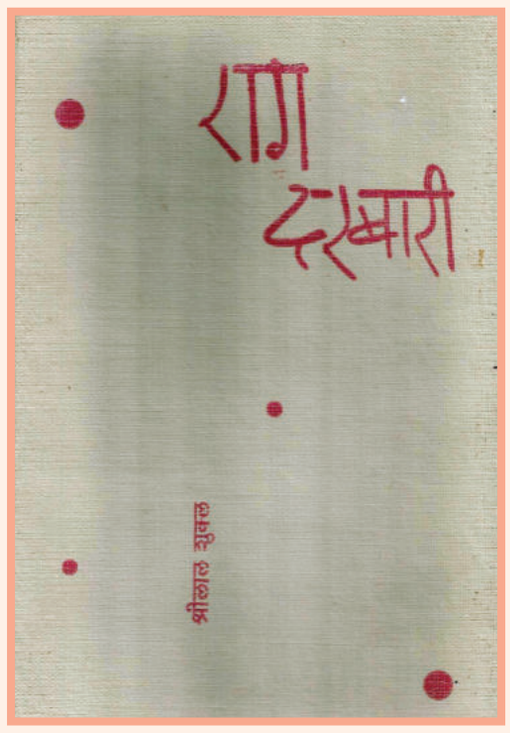

है. यह सही है कि आज़ादी के बाद हिंदी लेखन में सरकारी तंत्र पर सबसे ज़्यादा व्यंग्य हरिशंकर परसाईं ने किया और उनके व्यंग्य बेजोड़ होते थे, मारक भी. लेकिन, हरिशंकर परसाईं के व्यंग्य की तुलना श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के व्यंग्य से करना उचित नहीं लगता है और इस आधार पर राग दरबारी को घटिया व तीन कौड़ी का करार देना अनुचित है. रेणु के उपन्यासों में सरकारी तंत्र का उल्लेख यदा-कदा मिलता है. कुछ अन्य लेखकों ने भी सरकारी तंत्र को अपने कथा लेखन का विषय बनाया, लेकिन पूरे उपन्यास के केंद्र में सरकारी तंत्र को रखकर श्रीलाल शुक्ल ने ही लिखा. इसके बाद गिरिराज किशोर ने यथा प्रस्तावित एवं गोविंद मिश्र ने फूल, इमारतें और बंदर में सरकारी तंत्र का अधोपतन रेखांकित किया. इस पूरे उपन्यास को व्यंग्य के आधार पर देखने की भूल विजय मोहन सिंह जैसा आलोचक करे, तो यह बढ़ती उम्र का असर ही माना जा सकता है. दरअसल, हिंदी में आलोचकों को अर्से से यह भ्रम हो गया है कि वे किसी लेखक को उठा या गिरा सकते हैं. इसी भ्रमवश आलोचक बहुधा स्तरहीन टिप्पणी कर देते हैं और विजय मोहन सिंह की राग दरबारी एवं नागार्जुन के बारे में यह टिप्पणी उसकी एक मिसाल है.

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत कोशिश की थी कि वह जायसी को हिंदी कविता की शीर्ष त्रयी- सूर, कबीर एवं तुलसी के बराबर खड़ा कर दें. रामचंद्र शुक्ल ने जायसी पर बेहतरीन लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बावजूद इसके लोक या पाठकों के बीच वह जायसी को सूर, कबीर एवं तुलसी की त्रयी के बराबर खड़ा नहीं कर सके. दरअसल, आलोचकों की जो दृष्टि है, वह वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जहां तक रचनाकारों की दृष्टि पहुंचती है. या फिर कहें कि आलोचकों की दृष्टि रचनाकारों के बाद वहां तक पहुंच पाती है. आलोचकों के उठाने-गिराने के खेल के बारे में विजय मोहन सिंह ने अपने इस साक्षात्कार में इशारा भी किया है. आलोचकों की अपनी एक भूमिका होती है, उनका एक दायरा होता है, लेकिन जब उनके दंभ से यह दायरा टूटता है, तो फिर इस तरह की फतवेबाजी शुरू होती है कि फलां रचना दो कौड़ी या तीन कौड़ी की है. इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि आलोचना में संवाद कम, वाद-विवाद ज़्यादा होने लगे हैं. यह वक्त आलोचना और आलोचकों के लिए गंभीर मंथन का है कि आख़िर क्यों वे साहित्य की धुरी नहीं रह गए हैं. एक जमाने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि यदि उनकी कविताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुन रहे हैं, तो जैसे समूचा हिंदी जगत सुन रहा है. आज लेखकों और आलोचकों के बीच में यह विश्वास क्यों ख़त्म हो गया? क्या इसके पीछे आलोचक के पूर्वग्रह हैं या फिर यह विजय मोहन सिंह जैसी फतवेबाजी का नतीजा है? विजय मोहन सिंह ने अपने इस साक्षात्कार में कहा है कि मापदंड और कसौटी उन्हें कर्कश लगते हैं. उनके मुताबिक, रचना की समझ के आधार पर रचना का मूल्यांकन किया जाता है. तो क्या यह मान लेना चाहिए कि विजय मोहन सिंह न तो राग दरबारी को समझ पाए और न नागार्जुन की अकाल पर लिखी कविता को? जिस तरह से उन्होंने अपने साक्षात्कार में लेखकों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह आपत्तिजनक है, जैसे राग दरबारी तीन कौड़ी का, नागार्जुन बेहतर काका हाथरसी, शिवमूर्ति औसत दर्जे का कहानीकार. आलोचना और रचना के बीच विश्वास कम होने की यह एक बड़ी वजह है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

किताब मिली

पुस्तक	संपादक
सारांश समय का (साझा कविता संकलन)	बृजेश नीरज एवं अरुण अनंत
प्रकाशक	**मूल्य**
अंजुमन प्रकाशन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	160 रुपये

आज जबकि अपने स्तर पर किसी पुस्तक का प्रकाशन लेखक के लिए काफी कठिन हो गया है, खासकर अल्प संसाधनों वाले लेखकों के लिए, वैसे में साक्षा संकलन का प्रकाशन किसी हद तक राहत प्रदान करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए शब्द व्यंजना ने सारांश समय का नामक एक साझा कविता संकलन प्रकाशित किया है. अंजुमन प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित इस साझा कविता संकलन को संपादित किया है, बृजेश नीरज एवं अरुण अनंत ने. इसमें दो खंड हैं, स्वर एवं अनुगूंज. स्वर के अंतर्गत 57 रचनाकारों की चार-चार और अनुगूंज के अंतर्गत 23 रचनाकारों की दो-दो रचनाओं को स्थान दिया गया है. नए-पुराने, कच्चे-पक्के रचनाकारों को एक मंच पर बैठाने का अद्भुत और श्रमसाध्य कार्य को अंजाम दिया है शब्द व्यंजना ने. यह पुस्तक काव्य प्रेमियों को हर पीढ़ी की सोच, उसके दर्द से अवगत कराने में सफल होगी, ऐसी आशा है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

कहानी

प्रेमचंद

त्रिया चरित्र

पिछली बार आपने पढ़ा कि मगन दास नागर घाट में रहते हुए रंभा के प्यार में इतना खो गया कि उसे अपने घर और वहां वापस लौटने की सुध तक नहीं रही. तभी अचानक एक दिन दरवाजे पर उसके एक सहपाठी ने दस्तक दी, जो अब वकील बन चुका था. मगन दास के वकील मित्र ने उसे घर के समाचार सुनाए, तो उसके होश उड़ गए. सेठ लगन दास का बेटा चेचक का शिकार बन गया और लगन दास ने भी उसके गम में अपने प्राण त्याग दिए. आगे क्या हुआ? पढ़िए, इस बार...

जब मदन दास ने मुस्करा कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं, तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोह में हूं. सेठ मक्खन लाल ने अता-पता बताया. तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया. रंभा अधीर हो रही थी कि आख़िर यह शख्स कौन है और इन दोनों में क्या बातें हो रही हैं? दस बजते-बजते वकील साहब मगन दास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए. उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, यह कौन थे और इनका तुमसे क्या काम था? मगन दास ने जवाब दिया, यमराज का दूत. रंभा बोली, क्या असगुन बकते हो! नहीं-नहीं रंभा, यह असगुन नहीं है, सचमुच मेरी मौत का दूत था. मेरी खुशियों का बाग रौंदने वाला, मेरी हरी-भरी खेती उजाड़ने वाला. रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया, मुझे माफ़ करो. मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं, सेठ लगन दास का बेटा और सेठ मक्खन लाल का दामाद हूं. मगन दास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम, दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल ग़लत निकला. रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ़ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगन दास ने उसे गले लगाकर कहा, हां. रंभा बोली, क्यों? इसलिए, क्योंकि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है. रंभा बोली, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी. कभी इंदिरा की लौंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी. तुम जितनी मेरी मुहब्बत करोगे, उतनी इंदिरा की तो न करोगे, क्यों?

मगन दास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया. मुस्करा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूं कि वह बहुत सुंदर है. कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं, मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे स्वयं से डर लगता है. रंभा ने कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? ठीक है जो मन में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी. इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी रहूंगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगन दास की आंखें डबडबा गईं, बोला, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा. अरे, यह तो मैं तुमसे कह नहीं पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया. बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था. अफ़सोस, सेठ जी के आख़िरी दर्शन भी न कर सका. अपना बाप भी इतनी मुहब्बत नहीं कर सकता. उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है. वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर-चाकर लूटमार मचा रहे हैं. वहां का यह हाल है और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता. दिल तो यहां है, वहां कौन जाए.

रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी. इतने दिन तुम्हारे साथ रही, ज़िंदगी का सुख लूटा. अब जब तक जिऊंगी, इस सुख का ध्यान करती रहूंगी. मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना और इसी झोपड़े में. मगन दास ने बहुत रोका, लेकिन आंसू न रुक सके. बोला, रंभा, यह बातें न करो, कलेजा बैठा जाता है. मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है. तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर. वह शक्ति, वह प्रेम, वह आनंद, जो मुझे यहां मिलता है, कहीं और नहीं मिल सकता. खुशी के साथ ज़िंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है. मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहां दे रखी है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? धन-दौलत को मेरा सलाम है, पर मुझे उसकी हवस नहीं है.

रंभा गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी न बनूंगी. चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मुहब्बत न रहेगी. मगन दास को कोड़ा लगा. जोश से बोला, तुम्हारे सिवाय इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता. रात ज़्यादा हो आई थी. अष्टमी का चांद सोने जा चुका था. दोपहर के कमल की तरह साफ़ आसमान में सितारे खिले हुए थे. किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे ने सुरीलापन एवं अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ-जा रही थी. वैसे, जैसे कि कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ़ खींचने वाले पेड़ों से अपनी ज़िंदगी के गम की कहानी सुना रही हो. मगन दास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई. ■

...क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

कविता

कहीं मैं...

मैं रंग पढ़ रहा था
मैं खुशबू पढ़ रहा था
मैं फूल पढ़ रहा था
मैं ओस पढ़ रहा था
मैं मखमली दूब पढ़ रहा था
मैं तितली पढ़ रहा था
मैं पागल हवा पढ़ रहा था
मैं वसंत पढ़ रहा था
मैं फागुन पढ़ रहा था
मैं मौसम पढ़ रहा था
मैं सर्दी की गुनगुनी धूप
पढ़ रहा था
मैं तप्त जेठ की
छांव पढ़ रहा था
मैं मधुरिय चांदनी पढ़ रहा था
मैं आकाश गंगा पढ़ रहा था
मैं भरी नदी पढ़ रहा था
मैं बेसन की रोटी की गंध
पढ़ रहा था
मैं ताजे हरे धनिये की चटनी
पढ़ रहा था
मैं दूध की सफेद देह
पढ़ रहा था मैं...
...कहीं मैं तुमको तो नहीं पढ़ रहा था

-भारत भूषण आर्य

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly
Chauthi Duniya
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

साल 2014
नए सितारों ने छोड़ी छाप

इस साल बड़े बजट की फिल्में आती रहीं सलमान खान ने हर बार की तरह किक और जय हो जैसी फिल्मों के जरिये बंपर कमाई की. वहीं शाहरुख खान हैप्पी न्यू इयर के साथ मैदान में उतरे और सफलता के झंडे गाड़े. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी क्रिसमस के मौके पर राजकुमार हीरानी के साथ पीके लेकर आए. सलमान की जय हो और रितिक की बैंग-बैंग तथा शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर की कमाई ने नए रिकॉर्ड कायम किए.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साल 2014 बॉलीवुड के लिए सफल साबित हुआ. कुछ फिल्मों ने सफल कारोबार किया तो कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ीं. कुछ सितारों की किस्मत चमकी तो कुछ का करियर डामाडोल रहा. सलमान, शाहरुख और आमिर खान के अलावा यह साल नए सितारों के भी नाम रहा. अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और फवाद खान जैसे सितारों के लिए सफलता देने वाला रहा. इस साल बड़े बजट की फिल्में आती रहीं सलमान खान ने हर बार की तरह किक और जय हो जैसी फिल्मों के जरिये बंपर कमाई की. वहीं शाहरुख खान हैप्पी न्यू इयर के साथ मैदान में उतरे और सफलता के झंडे गाड़े.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी क्रिसमस के मौके पर राजकुमार हीरानी के साथ पीके लेकर आए. सलमान की जय हो और किक तथा शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर की कमाई ने नए रिकॉर्ड कायम किए. सलमान की किक और जय हो की समीक्षकों ने आलोचना की लेकिन कारोबार के मामले में पिछले सभी कीर्तिमान तोड़ डाले. रितिक की इस साल बैंग-बैंग फिल्म रिलीज हुई. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रितिक को काफी गहरी चोटें लगी थीं. बैंग-बैंग को दर्शकों की काफी तारीफें मिलीं और फिल्म ने अच्छा कारोबार किया और साल में कमाई के मामले में तीसरे पायदान पर रही. सौ करोड़ के क्लब में प्रवेश करने वाली फिल्मों के सितारों में नये और पुराने चेहरे शामिल रहे. अर्जुन कपूर-आलिया भट्ट की 2-स्टेट्स, सिद्धार्थ मल्होत्रा-श्रद्धा कपूर की एक विलेन, अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्सन, अक्षय कुमार की हॉली-डे जैसी फिल्में शामिल हैं. अक्षय कुमार की एंटरटेनमेंट और अजय देवगन की एक्शन जैक्सन आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी.■

अभिनेत्रियों ने मनवाया अभिनय का लोहा

साल 2014 में फिल्मों की सफलता में अभिनेत्रियों का भी योगदान रहा. अपनी पारंपरिक छवि से आगे बढ़कर फिल्मों के मुख्य किरदार में अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया. बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरीकॉम पर बनी फिल्म में शीर्ष किरदार को अदा करने वाली प्रियंका चोपड़ा, मर्दानी में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाली रानी मुखर्जी, क्वीन के कंगना रानावत के किरदार की तारीफ हुई. पिछले साल की तरह इस साल भी दीपिका ने कमाल ही किया. हैप्पी न्यू ईयर और फाइंडिंग फैनी हिट रहीं. विद्या बालन के लिए पिछला साल जितना अच्छा था ये साल उतना ही बुरा साबित हुआ. बॉबी जासूस के लिए उन्होंने खूब गेटअप बदले लेकिन दर्शकों ने उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया. आलिया भट्ट और दीपिका पादूकोण ने बेहतरीन अभिनय के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. आलिया की हाइवे, टू स्टेट्स, हमटी शर्मा की दुल्हनिया आदि फिल्में हिट रहीं जबकि दीपिका की हैप्पी न्यू इयर, फाइंडिंग फैनी सफल फिल्में रहीं.■

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

हैप्पी न्यू इयर	383 करोड़
किक	377 करोड़
बैंग-बैंग	340 करोड़
जय हो	183 करोड़
सिंघम रिटर्नस	150 करोड़

आया राम-गया राम

इस साल बड़े बजट की की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं. साजिद खान की हिम्मतवाला और हमशकल्स को लोगों ने नकार दिया. हिम्मतवाला को नकारने के बाद भी साजिद ने हमशकल जैसी फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई लेकिन वह भी दर्शकों को लुभाने में नाकामयाब रही. भारत-पाकिस्तान संबंधों पर बनी प्रेम कहानी टोटल सियापा भी फ्लॉप रही. इसके अलावा यंगिस्तान, ढिशकियाउं, ओ तेरी और सोनम कपूर और आयुष्मान खुराना की बेवकूफियां जैसी फिल्में कब आईं और चली गईं दर्शकों को इसकी खबर ही नहीं हुई. ■

छोटे बजट की फिल्मों ने जीता लोगों का दिल

छोटे बजट की फिल्में एक बार फिर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहीं. बड़े बज़ट और बड़े सितारों वाली मसाला फिल्मों के बीच छोटे बजट की फिल्मों ने अपनी जगह बरकरार रखी. कंगना रानावत की क्वीन, आलिया भट्ट की हाईवे, अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह की डेढ़ इश्किया, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर की फाइंडिंग फैनी, संयज मिश्रा की आंखों देखी, फिल्मिस्तान, विशाल भारद्वाज की हैदर आदि फिल्मों को फिल्म समीक्षकों की वाहवाही मिली. रजत कपूर की कम बजट की आंखों देखी बदकिस्मती का शिकार हुई और बड़ी फिल्मों के बीच कहीं खो गई. संजय मिश्रा के जानदार अभिनय की वजह से इस फिल्म को समीक्षकों ने सराहा. बेहतरीन अदाकारी और कहानी होने के बावजूद छोटे बज़ट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकीं. अमिताभ बच्चन जैसे मंझे हुए कलाकार ने बड़े परदे पर भूतनाथ रिटर्नस के साथ एक बार फिर वापसी की और देश के चुनावों पर कटाक्ष करते हुए दर्शकों का मनोरंजन किया.■

कई नए चेहरों ने दी दस्तक

साल 2014 में बॉलीवुड में कई नए चेहरों ने दस्तक दी. इनमें से कुछ बॉलीवुड परिवार की ही नई पीढ़ी हैं तो कुछ पाकिस्तानी कलाकार. किसी ने मॉडलिंग से फिल्मों में छलांग लगाई तो किसी ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर कदम बढ़ाया. फवाद खान ने सोनम कपूर के साथ फिल्म खूबसूरत से बॉलीवुड में डेब्यू किया. फवाद खान अब पाकिस्तान ही नहीं भारतीय दर्शकों के भी चहेते बन गए हैं. फवाद के दो चर्चित टीवी धारावाहिक जिंदगी गुलजार है और हमसफर को भारत में भी लोगों ने खूब पसंद किया. मॉडल और डांसर डेजी शाह ने साल 2014 में सलमान खान के साथ फिल्म जय हो से बॉलीवुड में डेब्यू किया. अभिनेत्री मिष्टी ने सुभाष घई की फिल्म कांची से बॉलीवुड में डेब्यू किया. फिल्मों में आने से पहले मिष्टी कोलकाता के एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी की टीचर थीं. जैकी श्राफ के पुत्र टाइगर श्राफ ने कृति शैनन के साथ फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया. मॉडल सोनाली राउत ने फिल्म द एक्सपोज से बॉलीवुड में एंट्री की. सोनाली ने साल 2010 में किंगफिशर कैलेंडर का असाइनमेंट जीता था. साल 2014 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ मैक्सिम मैग्जीन के लिए मॉडलिंग भी की थी. आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा की बहन बार्बी हांडा ने भी इस साल डेब्यू किया. बार्बी ने अनुभव सिन्हा की फिल्म जिद से बॉलीवुड में डेब्यू किया. बार्बी एक प्रशिक्षित डांसर हैं. डाबर हेयर ऑयल के विज्ञापन में दोनों बहनें साथ भी नजर जा चुकी हैं. अथिया निखिल आडवाणी की फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया जिसमें उनके साथ सूरज पंचोली हैं. साल 2011 की मिस इंडिया अर्थ हसलीन कौर ने फिल्म करले प्यार करले से बॉलीवुड डेब्यू किया इस फिल्म में उनके साथ सुनील दर्श के बेटे शिव दर्शन थे. फिल्मों में आने से पहले हसलीन ने कई विज्ञापनों में काम किया है. हिमांशु कोहली ने फिल्म यारियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया. एक्टिंग करने से पहले हिमांशु दिल्ली रेडियो मिर्ची में रेडियो जॉकी थे.■

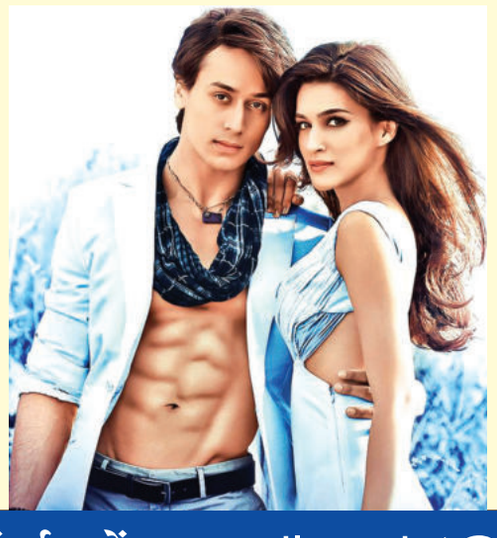

फवाद के दो चर्चित टीवी धारावाहिक जिंदगी गुलजार है और हमसफर को भारत में भी लोगों ने खूब पसंद किया. मॉडल और डांसर डेजी शाह ने साल 2014 में सलमान खान के साथ फिल्म जय हो से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

जानें कैसा रहेगा यह साल

मेष

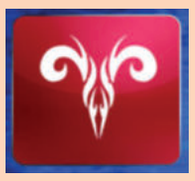

स्वास्थ्य : मेष राशि के जातकों के लिए यह साल स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा. इस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और यदि आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो सबकुछ ठीक रहेगा. लेकिन छठे भाव का राहु कभी-कभी कुछ बाधाएं दे सकता है, इसलिए किसी प्रकार का कष्ट होने पर दवा के साथ दुआ लेना बिल्कुल न भूलें.

कार्यक्षेत्र: मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है. अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कामों में लाभ का इजाफा होगा. कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर पाएंगे.

आर्थिक : मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उनकी आमदनी में निरंतरता बनाए रखेगा. आमदनी के किसी नए स्त्रोत के मिलने की भी उम्मीद है. किसी नए व्यापार की शुरूआत करने के कारण धन खर्च हो सकता है. अचानक कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है. लेकिन धन स्थान पर शनि की दृष्टि व केतु के बारहवें भाव में होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ष आप कोई बैंक बैलेंस न बना पाएं.

शैक्षिक : मेष राशि के छात्र/छात्राओं के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम भी मिलेंगे. लेकिन अध्ययन में लापरवाही न बरतें. छात्रों को सलाह है कि अध्यापकों और प्राध्यापकों से रिश्ते अच्छे रखने का प्रयास करें. उनसे बेवजह बहसबाजी न करें.

वृषभ

स्वास्थ्य : प्रथम भाव में शनि की दृष्टि के कारण बीच-बीच में आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है. राहु की पंचम भाव में उपस्थिति की वजह से आपको पेट से सम्बंधित परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए खान-पान पर संयम रखें व सावधानी बरतें.

कार्यक्षेत्र : वृषभ राशि के लोगों के लिए यह साल कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा. इस साल आपका आत्मविश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा. आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी. व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वर्ष के दूसरे भाग में कुछ बडें कामों में सफलता मिल सकती है. राहु के पचम में होने के कारण कोई गलत मंत्रणा नुकसान पहुंचा सकती है अत: किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले एक से अधिक व्यक्तियों से सलाह जरुर लें.

आर्थिक स्थिति : वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर इस वर्ष आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है. बचत करने में भी आप सफल रहेंगे. अप्रत्याशित ढंग से भी धन की प्राप्ति हो सकती है. लेकिन यदि आप जुआ, लाटरी आदि के माध्यम से कमाई करते हैं तो इनमें बड़ा निवेश करने से बचें. साल के दूसरे भाग में कुछ घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं. घर या वाहन खरीदने का योग है.

शिक्षा : वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति तीसरे भाव में उच्चावस्था में रहेगा. इस वजह से आपका आंतरिक ज्ञान कमाल का रहेगा. केवल आवश्यकता अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने की है. आप अपने ज्ञान और अपनी योग्यता को बाहर निकालने और निखारने का प्रयत्न करें. साल का दूसरा भाग खासकर उन लोगों के लिए और अच्छा रहेगा जो विदेश में जाकर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं.

मिथुन

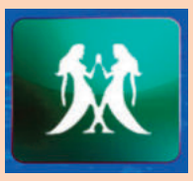

स्वास्थ्य : यदि आप पिछले दिनों से किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. लेकिन शनि के छठे भाव में होने के कारण कुछ पुरानी पद्धति के उपचारों का सहारा लेना बेहतर रहेगा.

कार्यक्षेत्र भविष्यफल : कार्यक्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर यह वर्ष अच्छा रहेगा. दशमेश गुरु उच्चावस्था में रहेगा अत: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूलता ला सकता है. पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं. यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई बेहतर नौकरी मिल सकती है.

आर्थिक भविष्यफल : इस साल आपकी आमदनी में बढ़ोत्तरी संभव है. विशेषकर साल का पहला भाग आर्थिक मामलों के लिए काफी अनुकूल है. चूंकि आपको सफलता मिलने की आशाएं ज्यादा है इसलिए अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखें और शुभ मुर्हूत का ख्याल रखना अति आवश्यक. अप्रत्याशित लाभ भी मिलने की संभावना है. साल के दूसरे भाग में सोच-समझकर जमीन जायदाद में निवेश करें.

शिक्षा : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. करिअर के स्थान का स्वामी बृहस्पति उच्चावस्था में है अत: व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए साल अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा. वहीं साल के दूसरे भाग में विदेश में जाकर शिक्षा लेने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

कर्क

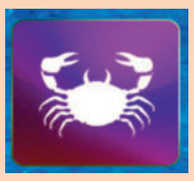

स्वास्थ्य : यह साल कर्क राशि के जातको के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित फल देने वाला होगा. लेकिन मौसम जनित बीमारियों से कभी कभार स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है. इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है. पंचम भाव में शनि की उपस्थिति को देखते हुए खान-पान पर संयम रखना होगा अन्यथा उदर विकार से परेशानी हो सकती है.

कार्यक्षेत्र : व्यवसाय से जुड़े लोग इस साल कुछ विशेष करने के मूड में रहेंगे, लेकिन नौकरीपेशा वाले लोग अपनी उपलब्धियों से कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि उनको मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे. धैर्य के साथ काम करते रहें. अधिक परेशानी होने की स्थिति में स्थान-परिवर्तन के बारे में विचार करें.

आर्थिक : आर्थिक मामलों में कुछ बेहतर उपलब्धियां आपके हिस्से में आ सकती हैं. कहीं से अचानक धन मिल सकता है. किसी लॉटरी या बीमा के माध्यम से भी धनार्जन होने के योग हैं. इस वर्ष धन संचय करने में भी आप सफल रहेंगे. आप कोई बड़ा फायदा दिलाने वाली डील कर सकते हैं. इस साल भूमि भवन आदि ख़रीदने के योग बन रहे हैं.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम फल देने वाला रहेगा. यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह चैतन्य और अनुकूल रहेगा. अध्ययन में आपकी गहरी रुचि रहेगी. यदि आप बैंकिग, मैनेजमेंट या व्यवस्थापन जैसे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं या उस क्षेत्र से जुडे हैं तो भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी.

सिंह

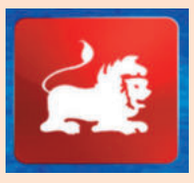

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के लिहाज़ से यह वर्ष कम अनुकूल है. ऐसे में संयमित दिनचर्या व जीवनशैली अपनाकर आप अपने आपको बेहतर रखने की कोशिश करें. किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी विरोधी के कारण मानसिक तनाव न लें. खान-पान पर संयम रखें. किसी भी मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा जिद न करें.

कार्यक्षेत्र : शनि की दृष्टि पूरे वर्ष आपके कर्म स्थान पर रहेगी, वहीं साल के पहले भाव में बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल नहीं है अत: इस समय आपकी सृजनात्मक क्षमता छुपी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंदियों द्वारा रुकावट डाली जा सकती है. व्यलसायिक यात्रा करने से पहले भली भांति जांच कर लें कि वह यात्रा आपके लिए लाभकारी है या नहीं. साल के दूसरे भाग में स्थितियां बेहतर होंगी और पदोन्नति के योग मजबूत होंगे.

आर्थिक : इस साल आर्थिक मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. कुछ खर्चों में अचानक वृद्धि की वजह से आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. अत: पहले से इस मामले को जानकर आप अभी से कुछ अतिरिक्त धन संचय कर सकते हैं. हालांकि साल के दूसरे भाग में स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष मिला जुला साबित होगा. जो लोग विदेश या दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए साल का पहला भाग ज्यादा अच्छा रहेगा. साल का दूसरा भाग प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक अनुकूल रहेगा. आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा.

कन्या

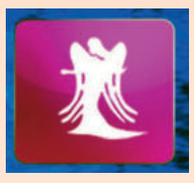

स्वास्थ्य : इस साल आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहना होगा. नियमित तौर पर चिकित्सक से संपर्क करते रहें. कई बार तो बीमारी न होने के बावजूद भी बीमारी होने का भ्रम हो सकता है. जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है उन्हें साल के पहले भाग में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राहु-केतु के साथ-साथ बृहस्पति के गोचर के प्रतिकूल होने के कारण साल के दूसरे भाग में कुछ कष्ट हो सकता है.

कार्यक्षेत्र : साल के पहले भाग में आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ अच्छा करने के प्रयास करेंगे. नए उद्यमों या व्यवसायों से जुड़ने का मौका मिलेगा. नए परिवर्तन अथवा नए काम की शुरुआत होगी. यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह साल इसके लिए अनकूल साबित होगा. साल के दूसरे भाग में विदेशियों या सुदूर स्थलों पर रहने वाले लोगों से आपके व्यवसायिक संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक : आय के लिए समय अनुकूल है. आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है. आप बचत करने में भी सफल रहेंगे. यदि आपके पास कोई पुराना कर्ज है तो साल के पहले भाग में उसे चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि साल के दूसरे भाग में कुछ नए कामों की शुरुआत करने के कारण संचित धन को खर्च करना पड़ सकता है.

शैक्षिक : सीखने-सिखाने के लिए साल का पहला भाग बेहतर रहने वाला है. क्योंकि साल के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके बारहवें भाव में रहेगा और पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा फलस्वरूप उच्चा शिक्षा व विदेश में शिक्षा लेने के लिए यह अनुकूल रहेगा.

तुला

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष कम अनुकूल है. स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही ठीक नहीं रहेगी. मानसिक चिंताओं के कारण तकलीफ संभव है या किसी रिश्तेदार को लेकर चिंता हो सकती है.

कार्यक्षेत्र : साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर ही रहेंगे अत: काम तो बनेंगे ही, लेकिन थोड़े बहुत व्यवधान भी आ सकते हैं. यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

आर्थिक : बृहस्पति की दृष्टि साल के पहले भाग में आपके धन स्थान पर है अत: धनार्जन होना स्वाभाविक है. व्यापार क्षेत्र के लोगों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है. अगर चाहें तो छोटे उद्योगों को लगाने की तरफ भी भविष्य बना सकते हैं. लेकिन शनि की दूसरे भाव में स्थिति को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि शायद आर्थिक मामलों में निरंतरता न रह पाए. हालांकि बीच-बीच में अचानक धन लाभ होने की संभावना जरूर बन रही है.

शैक्षिक : साल का पहला भाग प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को कड़ी मेहनत करने पर सफलता देने का संकेत दे रहा है. यदि आप कॉलेज के छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें. हालांकि उच्च शिक्षा के लिए साल का पहला भाग शुभ रहेगा. वहीं साल के दूसरे भाग में परिणाम ठीक इसके उलट हो जाएंगे. इसके लिए इस बात का ख्याल रखें कि परिणामों को ध्यान में रख कर तैयारी की जाए.

वृश्चिक

स्वास्थ्य : इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. यदि कोई पुरानी बीमारी नहीं है तो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लेकिन यदि कोई पुरानी बीमारी है तो साल के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

कार्यक्षेत्र : यह साल व्यवसाय के लिए काफी अनुकूल है. यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप मेहनत करने में समर्थ हैं तो इस वर्ष मेहनत करने वालों की हार नहीं होगी. बल्कि अच्छे परिणाम मिलेंगे. साल के दूसरे भाग में भी आप पूरे मन से काम में लग जाएंगे. और जब मन से काम करेंगे तो अच्छे परिणामों का मिलना स्वाभाविक है. अगर नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति संभव है.

आर्थिक : धन के लिहाज से यह साल अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा. साल की शुरुआत में यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो थोड़े से प्रयास से वो आपको मिल जाएंगे. इस अवधि में की गई यात्राएं आर्थिक समृद्धि में सहायक होंगी. साल के दूसरे भाग में आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूलता लिए हुए है. घर परिवार के लोग शिक्षा के मामले में यथा शक्ति आपका सहयोग करेंगे. अब यह काफी कुछ आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा. बेहतर हो कि अपनी प्राथमिकता तय करें. यदि आप विदेश जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

धनु

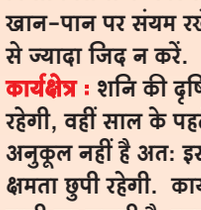

स्वास्थ्य : साल की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा ठीक नहीं रहेगी. स्वास्थ्य का खयाल रखने के साथ-साथ वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें. आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा धीरे-धीरे कम हो रही है. पेट की तकलीफ भी कुछ परेशान कर सकती हैं, लेकिन खान-पान पर संयम रखकर इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

कार्यक्षेत्र : वर्ष के शुरुआती दिनों में बृहस्पति का गोचर अनुकूल न होने के कारण छोटे कामों के लिये भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि दशम भाव में स्थित राहू बड़े प्रपोजल दिलाने में मदद तो कर सकता है लेकिन ध्यान से यह परखना होगा कि उनमें से कितने प्रपोजल सही हैं. लेकिन जल्दबाजी में कोई प्रपोजल स्वीकार न करें.

आर्थिक : धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों के संदर्भ में यह साल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धन का कारक ग्रह साल के पहले भाग में आठवें भाव में रहेगा. अत: आमदनी में निरंतरता नहीं बन पाएगी. इस वर्ष कहीं भी निवेश करने से पहले भली-भांति चिंतन मंथन जरूरी होगा.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सामान्यतय: अनुकूल रहेगा. हालांकि साल के पहले भाग में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं. सफलता के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करना पड़ सकता है.

मकर

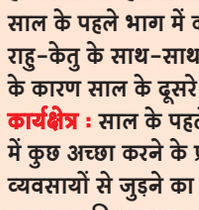

स्वास्थ्य : वर्ष का प्रथम भाग स्वास्थ्य के लिहाज़ से अनुकूल है. अत: कुछ मौसम जनित बीमारियों को छोड़ दिया जाय तो अन्य किसी विशेष बीमारी होने का योग नहीं है. लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में किसी काम में मिली असफलता के कारण आई चिंता आपको थका सकती है.

कार्यक्षेत्र : आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. विशेषकर साल का पहला भाग काफी अच्छा रहेगा. इस समय व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा. साल के दूसरे भाग में काम विलम्ब से पूरे होंगें.

आर्थिक : इस वर्ष आपकी आमदनी के स्त्रोतों में इज़ाफा होता नज़र आ रहा है. धन स्थान का स्वामी शनि लाभ भाव में रहेगा अत: लाभ की संभावनाएं काफी सुदृढ़ रहेंगी. वर्ष के पहले भाग में व्यवसाय के माध्यम से हुए लाभ की वजह से आप अच्छी बचत कर पाएंगे. साल के दूसरे भाग में बृहस्पति के आठवें भाव में चले जाने के कारण आमदनी की गति कुछ धीमी रह सकती है.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा. इस समय बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी अत: आपका ज्ञान आपके मार्ग को सहज बनाता रहेगा. साल के दूसरे भाग में आपको अध्ययन में पूरा ध्यान लगाना होगा. इस साल शोध कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत होगी.

कुंभ

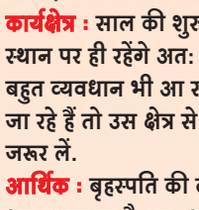

स्वास्थ्य : साल की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कमजोर रह सकती है. पेट की तकलीफें भी आपको परेशान कर सकती हैं. साल का दूसरा भाग आपके लिए खुशियां लिए हुए है. इस समय आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. इसलिए यह जरूरी है कि साल की शुरूआती भाग आप अपने स्वास्थ्य को विशेष तरजीह दें. खान पान का विशेष ख्याल रखें.

कार्यक्षेत्र : वर्ष के शुरुआती दिनों में बृहस्पति का गोचर अनुकूल न होने के कारण छोटे कामों के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि रुकावटों के बाद ही सही लेकिन काम पूरे जरूर होंगे. इसलिए यह जरूरी है कि आप कामों को बीच में न छोड़ें. हतोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को अपने पास भी न फटकने दें. साल के दूसरे भाग में आप नए उद्यम शुरू करेंगे. व्यापार में अच्छा लाभ होगा.

आर्थिक : आर्थिक मामलों के लिए यह साल अच्छा प्रतीत हो रहा है. यदि आप निष्ठा के साथ प्रयास करते हैं तो पैसों को लेकर परेशानी नहीं होगी. लेकिन केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति को देखते हुए आपको बचत करने में कठिनाई हो सकती है.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सामान्यत: अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. वर्ष के दूसरे भाग में चीजें काफ़ी आसान होने के भी योग हैं. विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए भी समय शुभ रहेगा.

मीन

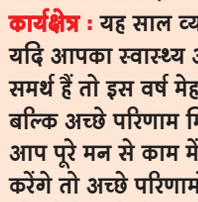

स्वास्थ्य : इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि केतु लग्न पर और राहु सप्तम में है. हालांकि वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति आपके पंचम भाग में रहेगा. अत: बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी. फलस्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज़ से वर्ष का प्रथम भाग अनुकूल रहेगा. लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में स्वास्थ्य चिंतन करना होगा.

कार्यक्षेत्र : आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. विशेषकर साल के पहले भाग में व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है. आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा. व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

आर्थिक : वर्ष के पहले भाग में व्यापार-व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने से भी आप अच्छी बचत कर पाएंगे. आमदनी के स्त्रोतों में बढ़ोत्तरी होगी. अचानक धन लाभ हो सकता है. साल के दूसरे भाग में यदि आपके पास पुराना कर्ज है तो आप इस वर्ष उससे छुटकारा पा सकते हैं.

शैक्षिक : विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. विशेषकर साल के पहले भाग में आप बुद्धिजीवियों की संगति में रहेंगे. शिक्षकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अध्ययन से जुड़े मामलों में सही निर्णय लेंगे. वहीं साल के दूसरे भाग में यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहें हैं तो उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

29 दिसंबर 2014-04 जनवरी 2015 16

चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

2015 कैलेंडर

जनवरी

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

फरवरी

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

मार्च

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

अप्रैल

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

मई

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

जून

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

जुलाई

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

अगस्त

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

सितंबर

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

अक्टूबर

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

नवंबर

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

दिसंबर

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

वर्ष के प्रमुख अवकाश

मिलाद-उन-नबी	04 जनवरी	बुद्ध पूर्णिमा	04 मई	दशहरा	22 अक्टूबर
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	ईद-उल-फितर	18 जुलाई	मोहर्रम	24 अक्टूबर
होली	06 मार्च	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	दीपावली	11 नवंबर
रामनवमी	28 मार्च	जन्माष्टमी	05 सितंबर	गुरु नानक जयंती	25 नवंबर
महावीर जयंती	02 अप्रैल	ईद-उल-जुहा(बक़रीद)	25 सितंबर	मिलाद-उन-नबी	24 दिसंबर
गुड फ्राइडे	03 अप्रैल	गांधी जयंती	02 अक्टूबर	क्रिसमस	25 दिसंबर

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

29 दिसंबर 2014-04 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

मंडल और कमंडल होगा चुनावी मुद्दा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1950 में बिहार में स्थापित धार्मिक न्यास बोर्ड का रवैया अच्छा नहीं है. बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मठ-मंदिरों के महंतों पर अन्याय कर रहे हैं. मठ-मंदिरों को उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं. इसके अधिकारी साधु-संतों पर हुक्म जमाते हैं. पूजा-पाठ में जबर्दस्ती कर रहे हैं. पुरानी परंपराएं तोड़ी जा रही हैं. मंदिरों से जबरन टैक्स वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार ने पूरे देश का नेतृत्व किया है. विश्व के कल्याण का मार्ग बिहार से ही प्रशस्त होगा, लेकिन अफसोस है कि आज बिहार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर हर गांव में संत सक्रिय हो जाएं तो धर्मांतरण पर रोक लग सकती है.

सरोज सिंह

बिहार में चुनावी साल शुरू होते ही चुनावी ऐजेंडे को भी सेट करने की कवायद तेज हो गई है. वैसे तो बिहार में हमेशा से ही चुनावी समीकरण पर जाति का गणित हावी होता आया है. अगर इसके बाद कुछ गुंजाइश बनती है तो वहां पर कानून और व्यवस्था और कुछ जगह रह गई तो विकास का नारा गूंजता है. लेकिन राज्य में इस समय जिस तरह के आयोजनों की भरमार है इससे लगता है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही ऐजेंड़े पर जाने या अनजाने न चला जाय. वैशाली के ऐतिहासिक अभिषेक पुष्करणी के तट पर आयोजित संत समागम में भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की जैसी हुंकार भरी उससे इसके संकेत मिलने लगे हैं. योगी आदित्यनाथ ने दो टूक लहजे में बिहार सरकार पर पहली बार यह आरोप लगाया कि यह सरकार हिंदू विरोधी है. योगी आदित्यनाथ ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड मठ और मंदिरों से प्राप्त आय को मौलवियों और पादरियों में बांट देता है. उन्होंने कहा कि मंदिरों से होने वाली आय से बिहार सरकार मुसलमानों को हज यात्रा कराती है.

योगी आदित्यनाथ ने संतों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी को पहचानें और अपने धर्म को ताकतवर बनाएं. किसी समाज एवं धर्म को समाप्त करने का आसान तरीका इसके धर्म पर प्रहार करना है और बिहार इसका ही शिकार हुआ है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1950 में बिहार में स्थापित धार्मिक न्यास बोर्ड का रवैया अच्छा नहीं है. बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मठ-मंदिरों के महंतों पर अन्याय कर रहे हैं. मठ-मंदिरों को उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं. इसके अधिकारी साधु-संतों पर हुक्म जमाते हैं. पूजा-पाठ में जबर्दस्ती कर रहे हैं. पुरानी परंपराएं तोड़ी जा रही हैं. मंदिरों से जबरन टैक्स वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार ने पूरे देश का नेतृत्व किया है. विश्व के कल्याण का मार्ग बिहार से ही प्रशस्त होगा, लेकिन अफसोस है कि आज बिहार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर हर गांव में संत सक्रिय हो जाएं तो धर्मांतरण पर रोक लग सकती है. पूर्व में मठ एवं मंदिर शस्त्र एवं शास्त्र दोनों के अखाड़े हुआ करते थे, मगर आज यह खत्म हो गया है. गाय और गंगा को बचाने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा नहीं रहेगी तो हिन्दू संस्कृति खत्म हो जाएगी. देखा जाए तो यह पहली बार है जब किसी पार्टी के नेता ने सरकार पर हिन्दु विरोधी होने का आरोप खुलेआम लगाया है. सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहे हैं पर धर्म के आधार पर आरोप एक अलग कहानी है. जदयू और राजद के नेता पहले ही आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक ऐजेंडे को सूबे में लागू करना चाहती है. जदयू प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भाजपा छिपे हुए ऐजेंड़े को लागू करना चाह रही है. सब धर्मों का सम्मान ही हमारी सरकार की पूंजी है. कट्टरवाद को बिहार की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. भाजपा एक दूसरे को लड़ाने की नीति पर चल रही है. भाजपा चाहती है कि प्रदेश में धर्म के नाम पर तनाव फैले. जदयू किसी भी कीमत पर भाजपा के मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी. संजय सिंह कहते हैं कि भाजपा के पास विकास का कोई रोडमैप नहीं है और वह केवल नफरत की राजनीति करती है. लेकिन इसकी यह दाल बिहार में नहीं गलने वाली है. बिहार के लोग समझदार हैं और चुनाव में भाजपा को पूरी तरह नकार देंगे. दरअसल योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद बिहार में एक नई बहस चल रही है. अगर इसी तरह का माहौल आगे भी बनाया गया तो यह तय है कि हिन्दु ध्रुवीकरण की प्रकिया तेज होती जाएगी और इस तरह की कोई भी कोशिश जदयू और राजद के लिए हानिकारक साबित होगी. ऐसा इसलिए है कि इधर जनता परिवार के विलय का मामला भी काफी आगे बढ़ गया है. जानकार सूत्र बताते हैं कि खरमास के बाद यानि की 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन पूरे धूम धड़ाके के साथ जनता दल परिवार के विलय का काम पूरा हो सकता है. राजद और जदयू में भी सहमति बन गई है. सूत्रों पर भरोसा करें तो नए दल का नाम जनता दल रखा जाएगा और इसका चुनाव चिन्ह चक्र होगा. यानि की वीपी सिंह की याद को फिर जिंदा कर दिया जाएगा. इसके पीछे एक वजह यह भी है कि गैरभाजपाई दलों का खासकर बिहार और यूपी के संदर्भ में यह मानना है कि अगड़ी जातियों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में देर सबेर होना तय है. इसलिए अच्छी रणनीति यही होगी की पिछड़ों की राजनीति को ही मजबूत किया जाए और भाजपा से जमकर मुकाबला किया जाए. भाजपा अगर धार्मिक मुद्दों को हवा देती है तो फिर पिछड़ावाद की राजनीति से ही इसका असर कम हो सकता है. यानि की चुनाव को मंडल और कमंडल के दायरे में लाया जाए. अगर इस तरह का सीधा विभाजन नहीं हुआ और पिछड़ों के वोटों में भी भाजपा ने सेंधमारी कर ली तो नतीजे लोकसभा चुनाव की तरह ही आऐंगे और फिर जनता दल परिवार के विलय का बहुत फायदा राजद जदयू या फिर सपा को नहीं मिल पाएगा. राजद नेता प्रगति मेहता कहते हैं कि यह कहना गलत होगा कि हम लोग मंडलवाद की राजनीति कर रहे हैं. हम लोग तो समरस समाज की अवधारणा पर भरोसा करते हैं. यह तो समाज को बांटने वाली भाजपा जैसी पार्टी का दुष्प्रचार है. राजद के लिए हर जाति व धर्म के लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं. हमारा ऐजेंडा देश की एकता और बिहार सहित पूरे देश का विकास है. दरअसल भाजपा अपनी हार से पहले से ही घबरा रही है इसलिए अपने जहर उगलने वाले नेताओं को बिहार भेज रही है. योगी आदित्यनाथ जैसे नेता केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं. राजनीतिक विष्लेशकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की बयानवाजी एक संयोग बस नहीं है. राजद और जदयू के विलय के बाद इसकी ताकत निश्चित तौर पर काफी बढ़ जाएगी. अगर दोनों दलों ने इसके बाद नाराज होने वाले नेताओं को ठीक से मना लिया और पूरी ताकत से चुनाव में उतरे तो भाजपा के लिए जंग आसान नहीं होगी. जातीय गणित जदयू और राजद के पक्ष होगा और यही बात भाजपा को परेशान कर रही है. इसलिए जातीय गणित की काट में गरमा गरम भाषणों का दौर शुरू हो गया है ताकि जनता दूसरे नजरिए से भी चीजों को देखे. भाजपा चाहती है कि एक भ्रम की स्थिति रहे ताकि अंतिम समय में हां और न वाले वोट इसकी झोली में आकर गिरे. राजद और जदयू के प्रस्तावित विलय ने बिहार में भाजपा की राह कठिन कर दी है. इसे भाजपा वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं. इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ बिहार सरकार को पहली बार हिन्दु विरोधी कह रहे हैं तो इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

छात्रों ने लगाये वृक्ष

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया में थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा की देख-रेख में विद्यापति पब्लिक स्कूल पताही के छात्रों द्वारा स्थानीय थाना परिसर में वृक्ष लगाया गया तथा बौद्ध स्तूप परिसर में अभियान चला कर स्तूप परिसर को सफाई की गयी.इस दौरान थाना परिसर में अशोक कर्ण व अन्य छायादार वृक्ष लगाए गए. स्कूली बच्चे जियाउल हक, वर्ग आठ के कुन्दन कुमार एवं प्रशान्त कुमार के साथ आए शिक्षक देव कुमार बनर्जी ने बताया कि विद्यालय प्रोजेक्ट के तहत यह कार्यक्रम बच्चों से कराया जा रहा है. इस कार्यक्रम की शुरुआत बीते 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती के अवसर पर मोतिहारी में दीप जला कर की गयी थी.

भोजपुरी फिल्म को पुरस्कार

मोतिहारी में बनी भोजपुरी फिल्म 'गंगा माई जइसन भउजी हमार' को समानान्तर सिनेमा कैटेगिरी पुरस्कार से नवाजा गया है. मॉरिशस में आयोजित इन्टरनेशनल भोजपुरी फिल्म फैस्टिवल 2014 में यह सम्मान दिया गया है. बीते छह से नौ अक्टूबर तक आयोजित उक्त फैस्टिवल में अन्य फिल्मों के साथ युवराज मीडिया एंड इन्टरटेनमेन्ट के तत्वावधान में डॉ. राजेश अस्थाना द्वारा लिखित-निर्मित-अभिनीत और निर्देशित इस फिल्म में सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को प्रेरित की गयी है. मॉरिशस के पोर्ट स्थित कुदान शहर में आयोजित इक्त समारोह में विभिन्न मुद्दों पर बनी फिल्मों को प्रदर्शित की गयी थी. इस फिल्म में लता भौमिक, ज्योति वर्मा, राजेश कुमार, ओम प्रकाश नुरावासी, विन्देश्वरी प्रसाद, सचिन पांडेय, नवनीधि, रविन्द्र, संयम कुमार व राजेश अस्थाना ने भूमिका नभाई है. फिल्म में संगीत, सूर्यकान्त एवं साहिल, गीतकार, डॉ. राजेश अस्थाना, छायांकन, अनूप वर्मा, संपादन रौशन जमाल, मुख्य सहायक निदेशक राजेश ओझा व सह निर्माता विपुल व डॉ. सीमा रानी है. फिल्म फेस्टिवल में डॉ. अस्थाना को प्रशस्ति पत्र दिया गया.

मोतीझील बचाव का संकल्प

मोतीझील बचाव अभियान समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक गांधी स्मारक में हुई जिसकी अध्यक्षता सुदिष्ट नारायण ठाकुर ने की. बैठक में मोतीझील बचाव के लिए किए गये आन्दोलन को और तेज करने तथा इसे इतिहासिक बनाने के के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में सर्व सम्मति से जलपुरुष राजेन्द्र सिंह को समिति से जोड़कर उन्हें मोतिहारी आमंत्रित करने, मोतीझील के जल श्रोतो को पुर्नजीवित कर इसे साफ कराने के लिए जिला प्रशासन व संबंधित विभागों जैसे मत्स्य, पर्यावरण व लघु सिंचाई विभाग को प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा आगामी 31 दिसम्बर को समिति द्वारा जागरूकता अभियान चलाने तथा आम जनता को मोतीझील की भावना से जोड़ने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाकर काम करने पर सहमति दी गयी. मौके पर समिति के अध्यक्ष अंसारूल हक, डॉ. संजीव कुमार, प्रो. भोलानाथ सिंह, डॉ. दीपक कुमार, कैप्टन अब्दुल हमीद, मुन्ना कुमार, संतोष कुमार रौशन, महासचिव अनिल कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष शमशाद अली खां, रफी अहमद, रंजीत गिरी, विलास कुमार, भगवान प्रसाद, रजनीश कुमार, डॉ. अमित, आशुतोष कुमार, अनिल तिवारी, रोहीत राज समेत बड़ी संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित थे.■

इंतेजारुल हक

चंपारण

जांच के बाद भी घोटालेबाजों पर नहीं होती कार्रवाई

इसका ज्वलन्त नमूना अरेराज अनुमंडल के हरसिद्धी प्रखंड का कनछेदवा व बंजरिया प्रखंड का रोहिनिया पंचायत है. कनछेदवा पंचायत के उपमुखिया व खाद व्यवसायी ब्रजकिशोर सिंह की शिकायत पर जब वर्ष 2013 में पूर्वी चम्पारण पूर्व जिलाधिकारी विनय कुमार ने अक्टूबर में अरेराज के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया.एसडीओ के आदेश पर नियुक्त विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी रईसुद्दीन खां ने जब इस पंचायत में हुए घोटाले की जांच की तो सभी आरोप सही पाया और अनेक गड़बड़ घोटालों का खुलासा किया.

इंतेजारुल हक

पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार व योजनाओं के क्रियान्वयन में मची लूट पर शिकंजा कसने के लिए बिहार की जदयू सरकार भले ही कठोर से कठोर कानून बनाती है और भ्रष्ट मुखियों व अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए निगरानी विभाग का सहारा लेती है किन्तु पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न पंचायतों में मची लूट की खबर नहीं लेती. इस कारण यहां भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने व लाखों रुपये का घोटाला करना या विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में इस तरह से उलझा दिया जाता है कि विरोध करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति साहस न करे. शिकायतें मिलने पर जांच भी होती है, मामले सही पाये जाते हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती. जांच प्रतिवेदन आने बाद संबंधित अधिकारी या तो मैनेज हो जाते हैं या जांच प्रतिवेदन को दबवा दिया जाता है जिससे कोई कार्रवाई नहीं होती.

इसका ज्वलन्त नमूना अरेराज अनुमंडल के हरसिद्धी प्रखण्ड का कनछेदवा व बंजरिया प्रखण्ड का रोहिनिया पंचायत है. कनछेदवा पंचायत के उपमुखिया व खाद व्यवसायी ब्रजकिशोर सिंह की शिकायत पर जब वर्ष 2013 में पूर्वी चम्पारण पूर्व जिलाधिकारी विनय कुमार ने अक्टूबर में अरेराज के अनुमण्डल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया.एसडीओ के आदेश पर नियुक्त विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी रईसुद्दीन खां ने जब इस पंचायत में हुए घोटाले की जांच की तो सभी आरोप सही पाया और अनेक गड़बड़ घोटालों का खुलासा किया. जांच प्रतिवेदन में कार्यपालक दण्डाधिकारी खां ने 35 लाख रुपये की विकास राशि वाले बीआरजीएफ व मनरेगा व नौ योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने व लाखों रुपये का बंदरबाट होने का उल्लेख किया और 20 अक्टूबर 2013 को एसडीओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में मुखिया,रोजगार सेवक,कनीय अभियंता व संवेदक की मिली भगत से आधे-अधूरे काम कराकर सरकारी प्रतिशत राशि की निकासी कर ली गयी है. जांच प्रतिवेदन सौंपे 18 माह गुजर गये किन्तु मुखिया पर तो कार्रवाई नहीं हुई किन्तु इस घोटाले का खुलासा कराने में सहयोग करने वाले उपमुखिया को अनेक तरह से परेशान किया गया और इस पर गोली चलवायी गयी. उपमुखिया ने सूचना के अधिकार के तहत भी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली थी और एक बड़े घोटाला का खुलासा करते हुए इस मामले से अधिकारियों को अवगत कराया था जिस कारण आधा दर्जन से अधिक झूठे मुकदमों में वहां के मुखिया राहुल कुमार सिंह ने उपमुखिया को फंसा दिया. महज आठ हजार की आबादी वाले इस पंचायत के मुखिया राहुल कुमार सिंह ने अपने आठ वर्षो के कार्यकाल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की विकास राशि में अनियमितता की है. यहां यह भी बता दें कि खाद व्यवसायी व उपमुखिया बृजकिशोर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना में जो जानकारी मिली थी इसके अनुसार,वित्तीय वर्ष 2006 से 2011 तक यानी पांच वर्षो के विकास योजनाओं मनरेगा,बीआरजीएफ, हरियाली, सोलर आदि योजनाओं के मद में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और बगैर काम कराये लाखों रुपये का उठाव का खुलासा हुआ था.किन्तु हैरत की बात तो यह है कि इस गड़बड़ी की शिकायत डीएम से लेकर विजिलेंस तक की गयी किन्तु कोई कार्रवाई नही.इस बीच उपमुखिया श्री सिंह ने बताया कि पंचायत के सभी योजनाओं में बड़े पैमाने पर खानापूर्ति की गयी है और राशि का दुरुपयोग किया गया है. वे बताते हैं कि इस लड़ाई में इनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है.अब यही स्थिति बंजरिया प्रखण्ड के रोहिनिया पंचायत की है जहां केवल मनरेगा में लाखों का घोटाला हुआ है और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है.लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसी तरह से जानकार बताते हैं कि दर्जनों ऐसे पंचायत यहां है जहां मुखियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और राशि का बंदरबाट किया है.आखिर जांच प्रतिवेदन आने व शिकायतें मिलने के बावजूद इन मुखियों पर कार्रवाई क्यों नही होती और अधिकारियों की मंशा इस पिछे क्या है?जनता अनेक तरह की चर्चाएं कर रही है और अधिकारियों के इस तरह की कार्यशैली पर सवाल इठा रही है.हालांकि अभी जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव पर सबों की उम्मीदें टीकी हुई है.श्री श्रीवास्तव इस मामले में कितनी दिलचस्पी लेते हैं और घोटालेबाज मुखियों पर कार्रवाई कैसे करते हैं यह अभी समय के गर्भ में है.■

इस लड़ाई में इनका व्यवसाय पुरी तरह से चौपट हो गया है.अब यही स्थिति बंजरिया प्रखण्ड के रोहिनिया पंचायत की है जहां केवल मनरेगा में लाखों का घोटाला हुआ है और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है.लेकिन कोई कार्रवाई नही की गयी.इसी तरह से जानकार बताते हैं कि दर्जनों ऐसे पंचायत यहां है जहां मुखियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और राशि का बंदरबाट किया है.

feedback@chauthiduniya.com

चंपारण के कई लोग विदेशों में बनाये गये हैं बंधक

इंतेजारुल हक

विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों को बेरहमी से लांखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोहों की सक्रियता चम्पारण में इन दिनों काफी तेज हो गयी है. उनकी लगातार बढ़ रही सक्रियता से एक तरफ जहां हजारों बेराजगार ठगी का शिकार तो हो ही रहे हैं साथ ही तो गलत वीजा होने के कारण विदेशों में भी बंधक बनाये जा रहे हैं. आये दिन इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है और इसका खुलासा उस समय हो रहा है जब ठगी का शिकार होने या विदेशों में बंधक बनाये जाने के बाद परिजन अधिकारियों के यहां राहत दिलाने की गुहार लगा रहे हैं. इस धोखा-धड़ी के खेल कई नामी-गिरामी तथाकथित एजेंटों व कम्पनियों की भूमिका होने की बात भी जानकार बताने लगे हैं. पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका प्रखण्ड के पंडरी गांव निवासी शमीम अख्तर को पिछले छह माह से सउदी अरब के जेद्दा में बंधक बनाया गया है. उसके वृद्ध पिता- नसरुद्दीन शाह, मां- तालमून नेशा, पत्नी अकबरी खातून उसकी सकुशल वापसी कराने के लिए बेचैन हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के यहां दर-दर की खाक छान रहे हैं. शमीम ने बंधक बनाये जाने की सूचना जब अपने परिजनों को दी थी तब यह मामला पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया था. शमीम को लगभग ढाई वर्ष पूर्व मुंबई की एक मैनपॉवर कम्पनी 'मनौअरा एसोशिएट, ओवरसीज मैनपावर कन्सलटेन्ट' ने एक विजीटर विजा देकर जेद्दा के 'आईडियल लग्जरी रेस्टोरेन्ट' में कुक के नाम पर भेजा था. कंपनी ने उसे अपने यहां बतौर कर्मी रख भी लिया और विगत दो वर्षों तक वह वहां काम भी किया. बाद में रेस्टोरेंट बंद हो गया. वहां रेस्टोरेन्ट के नाम पर एक कन्स्ट्रक्सन कंपनी खुल गयी.

इसी तरह की घटना सोरपनिया गांव निवासी मो. सत्तार के पुत्र मो. शब्बीर आलम के साथ घटी है.मो. शब्बीर मलेशिया में इसी तरह विजिटर वीजा पर गया था जहां कई महीनों से फंसा हुआ है और इसकी वापसी के लिए उसके परिजन भी दर-दर की ठोकरें खाकर थक गये हैं किन्तु इसकी वापसी नहीं हो पायी है. इस तरह के और भी कई लोग विदेशों में बंधक बनाये गये है जिनके परिजन अधिकारियों के यहां दौड़ते-दौड़ते थक गये हैं. जानकार बताते हैं कि विदेश भेजने का गिरोह इन दिनों पूर्वी चम्पारण के बंजरिया, सुगौली, ढ़ाका, घोड़ासहन, बनकटवा, रक्सौल व रामगढ़वा आदि प्रखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है. प्रत्येक बेरोजगार को सउदी अरब भेजने व अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपये लिये जा रहे हैं. अगर समय रहते प्रशासन अगर सर्तक नही हुआ तो बड़ी संख्या में बेरोजगार ठगी के शिकार तो होंगे ही साथ ही अनेक शबीम व शब्बीर विभिन्न देशों में बंधक बनते रहेंगे. हालांकि शमीम के मामले में पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया है और श्रम अधीक्षक संजीव कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस बीच श्रम अधीक्षक ने बताया कि यह मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. इस कारण विदेश मंत्रालय की हेल्प लाइन मेल पर कागजातों का संकलन व सूचनाओं आदान-प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रशासन हर संभव इसकी वापसी के लिए प्रयास करेगा. परिजनों के मुताबिक शमीम के साथ-गये 25 भारतीय वहां खानाबदोश की जिन्दगी बिताने को विवश हैं जबकि रेस्टोरेन्ट के उपर ही 10 लोगों को बंधक बनाया गया है. शमीम ने वहां भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया था जहां इसे वापस भेजने के नाम पर इससे अब 5 हजार रेयाल (पच्चासी हजार भारतीय रुपये) की मांग की जा रही है. उक्त राशि को पूरा करने में वह अक्षम है.■

फोटो-सउदी अरब में बंधक बने शमीम के परिजनों से मिलते श्रमअधीक्षक

feedback@chauthiduniya.com

गया

प्रेम कुमार की सुशील मोदी से दूरी क्यों

सुशील मोदी से प्रेम कुमार की तल्खी को इसी से समझा जा सकता हैं कि पिछले छह महीने में सिर्फ एक बार पटना में चन्द्रवंशी महासभा के कार्यक्रम में दोनो साथ देखे गये थे. जबकि पूर्व मे दोनों की दोस्ती अटूट थी. सच कहा जाये तो गयावासियों के लिए प्रेम कुमार मजबूरी का नाम है. अब तक कोई अच्छा प्रत्याशी खिलाफ मे नहीं आया. आया भी तो राजनीतिक समीकरण ठीक नहीं रहा, नतीजा रहा कि प्रेम कुमार को सफलता मिलती रही. गया शहर मे ऐसे हिन्दू-मुस्लिम फैक्टर भी प्रेम कुमार की जीत में महत्वपूर्ण रहा है.

सुनील सौरभ

पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी से इन दिनों गया शहर के विधायक पूर्व मंत्री प्रेम कुमार की दूरी बनाने का मतलब आम लोग समझ नही पा रहे हैं. कुछ महीनों से प्रेम कुमार ने भाजपा में अपने संरक्षक कहे जाने वाले सुशील मोदी से अचानक मोह भंग कर लिया है. जबकि पिछले ढाई दशक में शायद ही कोई ऐसा अवसर गया वासियों को देखने को मिला हो, जबकि सुशील मोदी गया आये और इनके साथ प्रेम कुमार नहीं हो. सुशील मोदी के गया दौरे पर प्रेम कुमार एक तरह से साये की तरह इनके साथ रहा करते थे. लेकिन पिछले पांच-छाह माह से एक पार्टी में रहकर भी दोनों गुरु-शिष्य अलग अलग चल रहें हैं. शिष्य तो एक तरह से गुरु के खिलाफ खुलेआम बगावत कर चुनौती भी देने में लगें हैं. प्रेम कुमार ने सुशील मोदी के द्वारा अपने आवास पर जनता दरबार लगाये जाने पर भी सवाल खड़ा करते हुए क्षेत्र मे जनता दरबार लगाने की बात कही थी. जब केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा था कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर भी सी.पी. ठाकुर, चन्द्रमोहन राय, शत्रुधन सिन्हा समेत प्रेम कुमार ने भी आपत्ति जतायी थी. जबकि सच यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ सरकार बनी तो इसमें प्रेम कुमार को प्राय: अच्छा विभाग मिला, इसमें सुशील मोदी की ही देन थी. लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति मे न कोई किसी का शिष्य होता है और नही कोई बड़ा-छोटा, हर कोई मौके की तलाश मे रहता है, एक दूसरे को पटकनी देने में. प्रेम कुमार की भी महत्वाकांक्षा जग उठी . भाजपा में सुशील मोदी विरोधी गुट ने इस बात की हवा दी कि एक क्षेत्र से लगातार छह बार विधायक बनना कोई कम बात नही है, वह भी अतिपिछड़ा वर्ग से आना. इसलिए प्रेम कुमार भाजपा के मुख्यमंत्री दावेदार हो सकते हैं. इसके लिए एक रणनीति के तहत प्रेम कुमार को सुशील मोदी के खिलाफ भड़काया गया. शायद प्रेम कुमार को बात जंच गयी और गुरु-शिष्य का संबंध टूट गया. हाल मे जब सुशील मोदी एक कार्यक्रम में गया आये तो पत्रकारों के पूछे जाने पर जबाब दिया कि राजनीति मे कोई किसी का शिष्य नही होता है. इस कार्यक्रम में प्रेम कुमार नही आये थे. अब तो प्रेम कुमार बकायदा फेसबुक पर अबकी बार प्रेम सरकार का प्रचार कर खुद को भाजपा के भावी मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं. सुशील मोदी से प्रेम कुमार की नाराजगी के कई राजनीतिक कारण है. भाजपा के अंदरखाने की राजनीति की बात करें तो मामला बड़ा है. जदयू से अलग होने के बाद प्रेम कुमार को उम्मीद थी कि सुशील मोदी इन्हे प्रतिपक्ष का नेता बनायेगें. लेकिन बना दिया गया नंद किशोर यादव को. इसके पूर्व भी जदयू के साथ भाजपा सरकार में शामिल थी तो प्रेम कुमार को पथ निर्माण विभाग से हटाकर नगर विकास विभाग दे दिया गया था. पथ निर्माण विभाग नंद किशोर यादव को दिया गया था. बताया तो यह भी जाता है कि जब नंद किशोर यादव को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया था तो प्रेम कुमार बगावत पर उतर आये थे, लेकिन भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया था. सुशील मोदी से प्रेम कुमार की तल्खी को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले छह महीने में सिर्फ एक बार पटना में चन्द्रवंशी महासभा के कार्यक्रम में दोनों साथ देखे गयें थे. जबकि पूर्व में दोनों की दोस्ती अटूट थी.

सच कहा जाये तो गयावासी के लिए प्रेम कुमार मजबूरी का नाम है. अब तक कोई अच्छा प्रत्याशी खिलाफ में नही आया. आया भी तो राजनीतिक समीकरण ठीक नही रहा, नतीजा रहा कि प्रेम कुमार को सफलता मिलती रही. गया शहर मे ऐसे हिन्दु-मूस्लिम फैक्टर भी प्रेम कुमार की जीत में महत्वपूर्ण रहा है.

अब जबकि बिहार भाजपा में सुशील कुमार मोदी विरोधी गुट को इस मामले में सफलता मिल गयी है, तो वही दूसरी ओर प्रेमकुमार भी रोज-रोज पटना में रहकर अखबारों में बयानवाजी कर अपने को भाजपा का मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रुप में खड़ा कर रहे हैं. कभी प्रेम कुमार को राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रुप में मजबूती देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता अखौरी निरंजन कहते हैं कि मौका मिलने के बाद भी प्रेम कुमार ने गया के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने सगे-संबधी और कुछ व्यवसायी दलाल को ही अपने फंड से मजबूत करते रहे. ऐसे में भाजपा के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना, वह भी सुशील मोदी को नजर अंदाज कर, बात मुश्किल है. वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है. अब चाहे जो कारण रहा हो, इतना तय है कि प्रेम कुमार के अभियान में बिहार भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का समर्थन जरुर है. आने वाले विधान सभा चुनाव के दौरान ही पता चल सकेगा कि शिष्य-गुरु में कौन अपनी राजनीति में आगे निकलता हैं या फिर भाजपा की अंदरुनी राजनीति का शिकार होकर हाशिये पर आता है.

feedback@chauthiduniya.com

टकरा सकते हैं रजनीश और ऊषा

स्थानीय निकाय विधान परिषद क्षेत्र बेगूसराय-खगड़िया के वर्तमान पार्षद रजनीश कुमार का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दोनों जिले के विकास के लिए जो कार्य किया है उस पर भरोसा है. यदि पार्टी का निर्देश मिला तो वे चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और विजयी होंगे.

सुरेश चौहान

बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव में भाजपा के वर्तमान विधान पार्षद रजनीश कुमार एवं भाकपा के ऊषा सहनी के बीच आमने-सामने के मुकाबले के प्रबल आसार दिख रहे हैं. दोनों संभावित प्रत्याशियों को अपने पार्टी कैडर एवं जनहित में किए गए विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है कि आगामी चुनाव काफी दिलचस्प होगा. हालांकि दोनों संभावित प्रत्याशियों का कहना है कि अंतिम निर्णय पार्टी पर निर्भर करेगा कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाता है या नहीं. राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गठबंधन एवं विलय की स्थिति में कौन किस दल का प्रत्याशी बनेगा, कहना मुश्किल है. गत चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रजनीश कुमार विजयी हुए थे और भाकपा प्रत्याशी ऊषा सहनी द्वितीय स्थान पर रही थीं. आगामी चुनाव में भी धुर दक्षिणपंथ एवं धुर वामपंथ के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है. क्योंकि क्षेत्र में अभी इन्ही दोनों पार्टियों का आधार मजबूत है.

गत चुनाव में भाजपा अपने दम पर रजनीश कुमार को विधान परिषद भेजने में सफल हुई थी. जबकि इस बार भाजपा का चुनावी गठबंधन लोजपा एवं रालोसपा के साथ होने के कारण प्रत्याशी की स्थिति और सुदृढ़ होगी. दूसरी ओर भाकपा प्रत्याशी को भी माकपा एवं माले का समर्थन प्राप्त हो सकता है. यदि गत लोक सभा चुनाव पर नजर डालें तो भाकपा को माकपा एवं जदयू का पूरा समर्थन प्राप्त था. यदि वह स्थिति कायम रह पाती है तो भाकपा प्रत्याशी को काफी बल मिलेगा. दूसरी संभावना यह भी बनती दीख रही है कि राजद एवं जदयू में यदि विलय होता है या विधान सभा उपचुनाव वाला गठबंधन कायम रहता है तो भाजपा प्रत्याशी को भाकपा प्रत्याशी नेक-टू-नेक फाइट देने की स्थिति में हो सकते हैं बशर्ते वह गठबंधन भाकपा को समर्थन दे. भविष्य के गर्भ में छिपा है कि जय श्रीराम एवं लाल सलाम के टक्कर में क्या गुल खिलेगा? एक ओर भाजपा इस सीटिंग सीट को खोना नहीं चाहेगी वहीं भाकपा अभी नहीं तो कभी नहीं की शैली अपना सकती है.

स्थानीय निकाय विधान परिषद क्षेत्र बेगूसराय-खगड़िया के वर्तमान पार्षद रजनीश कुमार का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दोनों जिले के विकास के लिए जो कार्य किया है उसपर भरोसा है. यदि पार्टी का निर्देश मिलेगा तो वे चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और विजयी होंगे. राजनीश कुमार आरएसएस से हैं. 2005 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. वर्ष 2006 में जिला परिषद के चुनाव में वे पार्षद निर्वाचित हुए. वर्ष 2009 में पार्टी के निदेश पर वे विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में बेगूसराय-खगड़िया सीट के प्रत्याशी बने और विजयी होकर विधान परिषद पहुंचे. भाजपा ने रजनीश कुमार को पार्टी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया. विधान परिषद लोक लेखा समिति के सदस्य बनें, विधान परिषद आपदा प्रबंधन के वे सभापति बनाए गए. पार्टी ने इन्हें भाजपा पंचायती राज मंच का राष्ट्रीय-सह-संयोजक बनाया. वर्तमान में रजनीश कुमार विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक हैं और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है. केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रजनीश कुमार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया है. इसके साथ ही रजनीश कुमार सिमरिया कुंभ सेवा समिति के महासचिव हैं. रजनीश कुमार अपनी कर्मठता, दक्षता एवं सद्व्यवहार के बल पर पार्टी के राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचे हैं. वे विधान पार्षद रहते हुए पंचायती राज के अधीन मिलने वाले अधिकारों को त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं. रजनीश का कहना है कि बरौनी खाद कारखाने को पुन: चालू कराने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण, बीटीपीएस के उद्धार, गरहारा की जमीन पर रेलवे का बड़ा कारखाना लगाने, सिमरिया, जयमंगलागढ़, नमक सत्याग्रह स्थल, काबर झील, हरसाई स्तूप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, गंगा कटाव को रोकने, इससे विस्थापित परिवार को पुनर्वासित करने, मक्के पर आधारित उद्योग लगाने के लिए हमेशा वे आवाज उठाते रहे हैं. इसी प्रकार खगड़िया में मां कात्यायनी स्थल के विकास वेलदौर-खगड़िया पथ, बाढ़ से सुरक्षा आदि जैसे संवेदनशील मुद्दा को परिषद में उठाया है.

दूसरी ओर उषा सहनी का भी राजनीतिक कैरियर काफी बेहतरीन है. वर्ष 2001 से उन्होंने राजनीति की सफर प्रारंभ किया. भाकपा से ही जुड़ने के सवाल पर उनका कहना है कि भाकपा की राजनीति उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है. पिता एवं ससुर दोनों परिवार भाकपा से जुड़ा है. दोनों पक्ष की प्रेरणा, गरीबों की सेवा, भाकपा के सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली तथा पार्टी नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से प्रभावित एवं प्रेरित होकर उन्होंने ज्ञान-विज्ञान समिति से जुड़ते हुए भाकपा की सदस्यता ग्रहण की. भाकपा के अंचल परिषद, जिला एवं प्रदेश परिषद की कार्यसमिति की वे सदस्य बनीं. जिला परिषद के चुनाव में वे बरवरी वार्ड-13 से पार्षद निर्वाचित हुई. जिला परिषद के इपाध्यक्ष पद पर चुनी गयी. वर्ष 2003 में पार्टी ने इन्हें स्थानीय निकाय चुनाव में बेगूसराय-खगड़िया से पार्टी प्रत्याशी बनायी और वे निर्वाचित हुई. पुन: 2009 के उक्त चुनाव में वे पार्टी प्रत्याशी बनी और द्वितीय स्थान पर रही.

उषा सहनी का कहना है कि विधान पार्षद रहते हुए वे परिषद में 10+2 स्कूली शिक्षा प्रारम्भ करने, जुब्बा सहनी के नाम पर भागलपुर केन्द्रीय कारा का नामाकरण करने, महिला थाना स्थापित करने, सिमरिया स्टेशन का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम करने का संकल्प (प्रस्ताव) लायीं. त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय, टीए एवं डी ए देने की मांग परिषद में उठायी. उषा सहनी कहती हैं कि अगामी स्थानीय निकाय चुनाव में यदि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो वे जमकर चुनाव लड़ेंगी. जून-जुलाई 2015 में होनेवाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अभी से दोनों संभावित प्रत्याशी मतदाताओं से जुड़कर अपना पक्ष रखने की मुहिम में जुट गए हैं. बेगूसराय-खगड़िया स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग छह हजार है. राजनीतिक दलों के गठबंधन एवं पार्टी के निर्णय से प्रत्याशी में परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन जो तस्वीर उभर रही है इसमें रजनीश कुमार का मुकाबला उषा सहनी से होने के आसार दिख रहें है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

स्थापना दिवस मनाया

सीतामढ़ी जिला का 43 वां जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित स्टेडियम में आयोजित समारोह का उद्घाटन प्रभारी मंत्री राम लखन राम रमन, गन्ना विकास मंत्री डॉ. रंजू गीता, विधायक राम नरेश यादव व मोतिलाल प्रसाद, विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, जिप अध्यक्ष इंद्राणी देवी, डीएम डॉ. प्रतिमा, एसपी नवल किशोर सिंह समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे.

सीतामढ़ी में रक्तदान

सीतामढ़ी जिला स्थापना दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस व यूथ रेडक्रॉस के तत्वावधान में संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में आयोजित शिविर का उद्घाटन डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया. मौके पर एएसपी संजीव कुमार सिंह, यूथ रेडक्रास के सचिव प्रो. डॉ. राज कुमार गुप्ता, विपुल, अमित कुमार, नीरज प्रकाश, अशोक कुमार आर्या, प्रमोद कुमार व गुरूदीप सिंह ने रक्तदान किया. इस अवसर पर रेडक्रॉस के सचिव डॉ एम ठाकुर व सीएस डॉ एके गुप्ता समेत अन्य थे.

- वाल्मीकि

समिति सदस्यों को सम्मान

सितामढ़ी जिला स्थापना दिवस समारोह के मौके पर दुर्गा पुजा एवं मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने पर दुर्गा पुजा समिति के युगल किशोर प्रसाद, जय नारायण महतो, दुर्गानंद जी, अनिल कुमार सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, राम रतन दास, राम नरेश झा, मनोज कुमार सिंह व राम बचन पासवान के अलावा मोहर्रम में प्रशासन को सहयोग के लिए मो. जमशेद, सोबराती अंसारी, मो अनवारूल, फूल मोहम्मद शाह, मो जमीर शाह, मो अजहर अली, मो शमद व सदीक अंसारी को सम्मानित किया गया.

कवि सम्मेलन का आयोजन

सितामढ़ी जिला स्थापना दिवस पर जिले के अलग-अलग स्थानों पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गीता भवन में आयोजित कवि सम्मेलन का उद्घाटन समाजसेवी नागेंद्र प्रसाद सिंह, लेखिका आशा प्रभात, संगीता चौधरी, प्रो राज कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया. ई. सचिन्द्र कुमार हीरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन गीतकार गीतेश ने किया. मौके पर डॉ आनंद प्रकाश वर्मा, सत्येंद्र मिश्र, इमा शंकर लोहिया, बच्चा प्रसाद बिहवल, सुरेश लाल कर्ण, अलाउद्दीन बिस्मिल, मुरलीधर झा मधुकर समेत अन्य ने अपनी रचनाए प्रस्तुत की.

विधायक का अनशन

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में 15 सूत्री मांगों के समर्थन में क्षेत्रीय भाजपा विधायक राम नरेश यादव ने एक दिवसीय अनशन किया. कार्यक्रम में सीतामढ़ी विधायक सुनील कुमार पिंटू, विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा विधायक दिनकर राम, जिला मुखिया संघ के संयोजक राम प्रवेश यादव व जिला लोजपा अध्यक्ष मोहन झा समेत अन्य मौजूद थे.

- अमरनाथ

भाजपा की कार्यशाला

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला नवगछिया ने समृद्ध बिहार बनाने हेतु बिहारी अतिथि भवन में एक कार्यशाला आयोजित की. जिसे संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री मृत्युंजय झा ने कहा कि 31 मार्च तक अधिक से अधिक सदस्य बनाया जाय. जून जुलाई और अगस्त में पूरे देश में एक साथ पंद्रह लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. लालू और नितीश कुमार चाहे जैसा भी गठबंधन बना ले केंद्र की सत्ता से बीस साल तक भाजपा को हटा नहीं सकता. कार्यशाला को क्रीडा मंच के प्रदेश इपाध्यक्ष वरुण कुमार के अलावा प्रसिद्ध भोजपुरी लोकगायक सुनील छैला बिहारी ने संबोधित किया. मौके पर जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष प्रवीण भगत, महामंत्री चन्द्रकिशोर शर्मा, पुलकित सिंह, नवीन सिंह कुशवाहा, कुणाल गुप्ता, जेम्स, नरेश साह, प्रो. विजय कुमार, प्रो. भोला कुंवर, प्रो. विभान्शु मंडल, आलोक सिंह सहित दर्जनों प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे.

शाहनवाज का जन्मदिन

नवगछिया के तेतरी दुर्गा स्थान परिसर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का जन्मदिन मनाया गया. जिसका आयोजन अधिवक्ता अजित कुमार संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रो भोला कुंवर ने किया. इस मौके पर योगेंद्र टाइगर, सुशील यादव, बनारसी मंडल, मो. जैनूल, वीरेंद्र सिंह सहित एक दर्जन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि भागलपुर की उप महापौर प्रीति शेखर, अश्वनी जोशी मोंटी, भागलपुर जिलाध्यक्ष नभय चौधरी, नवगछिया जिलाध्यक्ष सुबोध कुशवाहा, महामंत्री चन्द्र किशोर शर्मा, जिला मंत्री मुकेश राणा, पूनम चौरसिया, नवगछिया प्रमुख मान्केश्वर सिंह, अनंत साहू, अशोक जयसवाल, श्रवण बिहारी, सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल, केके आजाद के अलावा दर्जनों प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे.

स्वच्छता अभियान में एसपी शामिल

क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा संचालित स्वच्छता जागरूकता अभियान को इस समय मजबूती मिल गयी जब नौगछिया के एसपी शेखर कुमार, पुलिस निरीक्षक रंजन कुमार एवं जगतानंद ठाकुर के अलावा वाणिज्य परिषद के सचिव पवन कुमार सर्राफ, लायन्स क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रो0 राजेन्द्र शर्मा, रंजन केडिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, जिला मंत्री मुकेश राणा, अधिवक्ता कौशलजी सहित कई प्रमुख लोग शामिल हो गए . महाराज जी चौक से स्टेशन रोड एवं स्टेशन परिसर के बाद राजेंद्र कॉलोनी में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया. अभियान में शामिल हुए जीबी कालेज के छात्रों ने भी स्टेशन रोड से मील टोला होते हुए जीबी कालेज परिसर तक की सफाई की. इसके साथ ही संकल्प लिया कि न तो गंदगी फैलाएंगे और न फैलाने देंगे.■

- राजेश कनौडिया

खगड़िया

> सदर अस्पताल में पदस्थापित कर्मी की बात की जाय तो डा0 का स्वीकृत 13 पद है जिसमें 7 पदस्थापित हैं, महिला चिकित्सक का स्वीकृत 3 पद है जिसमें 1 पद स्थापित हैं वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक का स्वीकृत पद 10 है जिसमें 3 पदस्थापित हैं, नर्स का स्वीकृत पद 26 है जिसमें 21, अन्य कर्मी का स्वीकृत पद 29 है जिसमें 18 पदस्थापित हैं. वहीं सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि सभी व्यवस्था को शीघ्र ही दुरूस्त किया जाएगा. इसके लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए जांच और एक्स-रे को चालू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को लिखा गया है तथा नए भवन को चालू करने के लिए उन्होंने कई बार विभाग को पत्र भेजकर राशि आवंटन करने की मांग की है.

जिले के स्वास्थ्य विभाग का गिरा ग्राफ

मनेंद्र कुमार

कभी सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खगड़िया स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लाखों रूपये की लागत से बने सौ शय्या वाले अस्पताल का आलीशान भवन अनुपयोगी साबित हो रहा है. वहीं सदर अस्पताल परिसर में पड़े हाईटेक एम्बुलेंस विभागीय देख-रेख नहीं होने के कारण सड़ रहे हैं. जानकारी के अनुसार यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस पूर्व इस्पात मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलौली को रोगी के लिए सेवा प्रदान वास्ते विभाग के द्वारा दिया गया था. इस एम्बुलेंस की कीमत लगभग 40 लाख बतायी जा रही है. जिसमें गंभीर रोग से ग्रसित रोगियों को रेफर करने के बाद चलती अत्याधुनिक एम्बुलेंस में ऑपरेशन सहित जांच की व्यवस्था की गई थी. इसलिए इस एम्बुलेंस को मिनी अस्पताल माना जा रहा था. लेकिन विभागीय कुव्यवस्था के कारण 2005 में प्रदत्त इस एम्बुलेंस सड़ने की कगार पर है. वर्ष 1981 में खगड़िया को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था. लेकिन इस समय अनुमंडलीय अस्पताल का ही दर्जा दिया गया था. लेकिन तत्कालिन सरकार के द्वारा सदर अस्पताल का दर्जा देते हुए 50 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन इसके बावजूद भी जिले के स्वास्थ्य सुविधा को विस्तार करते हुए इस अस्पताल के पीछे 72 एकड़ के विशाल भू भाग में सौ शैय्या वाले हाईटेक अस्पताल का निर्माण किया गया था. लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग के गलत रवैये के कारण आजतक उक्त भवन में सदर अस्पताल को शिट नहीं किया जा सका है.

जबकि इसमें अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई है. लेकिन इस भवन को चालू नहीं होने से वर्तमान सदर अस्पताल में मारा-मारी की समस्या बनी रहती है. वहीं विभागीय सूत्रों के अनुसार इस भवन को चालू करने मे तकनीकि समस्याएं बताई जा रही है. वहीं उक्त हाईटेक अस्पताल में गहन चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है. जिसमें दो सर्जन को पदस्थापित किया गया है. लेकिन हमेशा छुट्टी में रहने के कारण लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है. गौरतलब बात है कि दांत, कान और आंख विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहने के बावजूद भी मरीजों का ईलाज नहीं हो पाता है. इस विभाग की समस्या उपकरण का अभाव बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिकोण से 2010 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खगड़िया जिले का 2012 में बीसवां स्थान था. जबकि वर्तमान की बात की जाय तो इस अस्पताल का इस वर्ष का रेंकिंग ही नहीं हो पाया है. जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि गोगरी अनुमंडल में स्थित रेफरल अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय है. वहां चिकित्स का अभाव कौन कहे बल्कि दवा भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जबकि बिहार सरकार के द्वारा सदर अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुविधाओं से लैस कर दिया गया है. लेकिन एक वर्ष के दरम्यान ही इसका स्थान खिसक कर बहुत ही नीचे चला गया इसका क्या कारण है उसके सवाल पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौन धारण कर लेते हैं. बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं. लेकिन असलियत बात है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत बहुत ही जर्जर है. अधिकांश स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर एएनएम फरार रहती है साथ ही साथ दवा का भी अभाव रहता है. जिस कारण राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इसका स्थान धीरे-धीरे खिसक रहा है. बल्कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था कागज पर दो वर्षों तक बहुत ही बेहतर रहा है. जबकि जमीनी बात की जाय तो जिले में कहीं भी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है. वहां जिले के कई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 24 घंटे चालू कर दिया गया है तथा उक्त अस्पताल में हजारों रुपये साफ-सफाई तथा रोशनी के नाम पर खर्च किये जा रहे हैं लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण उक्त अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी नदारत दिख रहे हैं. जिले से बीस किमी0 की दूरी पर अवस्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीसकरपुरा का जयाजा लिया जाय तो एक आयुष चिकित्सक के सहारे अस्पताल का संचालन किया जा रहा है. उक्त अस्पताल के आयुष चिकित्सक मनीष कुमार का कहना है कि होमियोपैथिक के डाक्टर हैं लेकिन दवा अभाव के कारण रोगियों का समुचित ईलाज नही कर पाते हैं. जबकि इस क्षेत्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का ईलाज जिला मुख्यालय में कराना पड़ता है. जो कि गरीब लोग सही ईलाज से वंचित रह जाते है.

इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अलौली विधानसभा के जदयू विधायक रामचन्द्र सदा का कहना है कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल रानीसकरपुरा में है. जिससे दर्जनों गांवों के लोग ईलाज कराने आते हैं जबकि उक्त क्षेत्र महादलित का है. लेकिन चिकित्सक का पदास्थापन नहीं होने के कारण लोगों को ईलाज कराने में कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के निदान के लिए उक्त अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकें. वहीं सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का कहना है कि मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थानांतरण रानीसकरपुरा तथा गोगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्थानांतरण महेशखूंट में होना जरूरी है. जिसका प्रस्ताव 2009 में ही जिला संचालन समिति को प्राप्त हो चुका था. लेकिन दुःख की बात है कि आज तक उक्त जगहों पर पीएचसी का संचालन नही हो पाया है. श्री चौधरी का कहना है कि सरकार के द्वारा सिर्फ प्रस्ताव ही लिया जाता है बल्कि स्थल पर कार्य नहीं किया जाता है. बतातें चलें कि 2009 के तत्कालीन सिविल सर्जन यूसी मिश्र ने प्रत्रांक 1053,1054/2009 के माध्यम से रानीसकरपुरा एवं महेशखूंट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की अनुमति मांगी थी. इधर जिले में स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाय तो एक सदर अस्पताल, एक अनुमंडलीय अस्पताल, सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौबीस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दर्जनों स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं जिसमें संविदा पर चिकित्सकों की बहाली होने से मरीजों को लाभ मिल रहा है पर आज भी चिकित्सकों की कमी बरकरार है. उम्मीद की जा रही है कि चिकित्सकों की और बहाली कर लाभ पहुंचाया जा सकेगा. मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में 28 हजार लोगों पर एक डॉक्टर प्रतिनियुक्त है जिसमें संविदा पर 44 एवं रेगुलर के 91 पद सृजित हैं. लेकिन इसके विरूद्ध संविदा पर 38 एवं रेगुलर 25 चिकित्सक तैनात हैं. ऐसे में पूरी चिकित्सा व्यवस्था संविदा पर बहाल चिकित्सकों पर निर्भर है. जबकि महिला चिकित्सकों की घोर कमी है. जिले में 2 सर्जन चिकित्सक बहाल है. वहीं सदर अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में कहने को 40 प्रकार की दवा दी जा रही है पर समय समय पर इनमें से प्रमुख दवाएं मरीजों को बाजार से खरीदनी पड़ती हैं इतना ही नहीं इमरजेंसी में भर्ती किये गए मरीजों के परिजनों को दवा के लिए बाजार का सहारा लेना पड़ता है. जबकि सदर अस्पताल में एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, पेथोलौजी एवं इसीजी की सुविधा उपलब्ध है. वहीं सदर अस्पताल परिसर में स्पेशल न्यू बोर्न केयर कार्नर की शुरूआत की गई है.

सदर अस्पताल में पदस्थापित कर्मी की बात की जाय तो डा0 का स्वीकृत 13 पद है जिसमें 7 पदस्थापित हैं, महिला चिकित्सक का स्वीकृत 3 पद है जिसमें 1 पद स्थापित हैं वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक का स्वीकृत पद 10 है जिसमें 3 पदस्थापित हैं, नर्स का स्वीकृत पद 26 है जिसमें 21, अन्य कर्मी का स्वीकृत पद 29 है जिसमें 18 पदस्थापित हैं. वहीं सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि सभी व्यवस्था को शीघ्र ही दुरूस्त किया जाएगा. इसके लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए जांच और एक्स-रे को चालू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को लिखा गया है तथा नए भवन को चालू करने के लिए उन्होंने कई बार विभाग को पत्र भेजकर राशि आवंटन करने की मांग की है. लेकिन राशि का आवंटन नहीं किया जा सका है. जिस कारण नए भवन को चालू नहीं किया जा सका है. इसके बावजूद भी सदर अस्पताल भी कई व्यवस्थाओं से लैस होगा. लोगों को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए. जल्द ही सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर स्वास्थ्य केन्द्र की जांच करेंगे. इसके बाद एक रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेगें. जिससे की काम में और तेजी लाया जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त कर दिया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : बदहाली के कगार पर ज्ञान का खजाना

> धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों से पूर्ण सीतामढ़ी जिले में दशकों पूर्व समाजसेवियों ने साहित्य के विकास को लेकर अलग - अलग स्थानों पर पुस्तकालयों की स्थापना की थी. लेकिन समय गुजरने के साथ ही लगभग अधिकांश पुस्तकालय नाम मात्र के ही रह गए हैं. वर्तमान में शहर के मध्य स्थित सनातन धर्म जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गीता भवन ही साहित्यकारों के लिए ज्ञान का खजाना रह गया है. इसके अलावा स्थापित तकरीबन सभी प्रखंडों की पुस्तकालय अतीत की कहानी बन कर रह गई है...

वाल्मीकि कुमार

भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित सीतामढ़ी जिले में हिंदी साहित्य के विकास को लेकर दशकों पूर्व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हर संभव प्रयास किया था. आजादी पूर्व से लेकर अब तक जिले के अलग-अलग स्थानों पर पुस्तकालयों की स्थापना की गई, लेकिन समुचित देखभाल का अभाव के साथ ही सरकारी एवं प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा का आलम है कि वर्तमान में गिने-चुने को छोड़ अधिकांश पुस्तकालय महज एक दिखावा बन कर रह गया है. जिले की सबसे पुरानी सनातन धर्म जिला केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1925 में शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया था. जबकि आजादी के बाद शिक्षक तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के तत्कालीन विधान पार्षद स्व. सावलिया बिहारी लाल वर्मा ने वर्ष 1959 में जिला मुख्यालय डुमरा में गीता भवन का नींव डाला था. वर्तमान में सनातन धर्म पुस्तकालय में जहां विभिन्न प्रकार के तकरीबन 27 हजार से अधिक पुस्तके हैं, वही गीता भवन में 5 हजार से अधिक केवल धार्मिक पुस्तके मौजूद हैं. सामाजिक सद्भाव का केंद्र माना गया गीता भवन में केवल गीता से संबंधित पुस्तकों की संख्या दो हजार से अधिक बताई जाती हैं. गीता भवन परिसर में प्रतिदिन एक ओर जहां धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है, वहीं दूसरी ओर नवाज भी होती रहती है. लेकिन किसी को भी एक दुसरे से कोई गिला सिकवा नहीं रहता है.

जिले के पुस्तकालयों की दशा पर भी एक नजर डालने की आवश्यकता है. सनातन धर्म जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के नए भवन का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1957 में कराया गया. पुस्तकालय अधीक्षक पटना के पत्रांक 4727, दिनांक 28.02.57 द्वारा अनुमंडलीय पुस्तकालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक 895, दिनांक 15.11.77 के द्वारा इसे जिला केन्द्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त है. जहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 482, दिनांक 06.12.12 के अनुसार 15 सदस्यीय प्रबंधकारिणी समिति गठित है. पुस्तकालय के समुचित देखभाल एवं संचालन के लिए पुस्तकाध्यक्ष, सौर्टर, रात्रि प्रहरी सह माली की प्रतिनियुक्ति पूर्णकालिक की गई हैं. इस पुस्तकालय में मौजूद करीब 27 हजार पुस्तकों में धार्मिक, साहित्य, आलोचना, काव्य, उपन्यास एवं छात्रोपयोगी के अलावा विभिन्न प्रकार की पत्र एवं पत्रिकाएं भी शामिल है. सनातन धर्म पुस्तकालय में 8 संरक्षक सदस्य, 62 आजीवन एवं 50 से अधिक सामान्य सदस्य हैं. वर्तमान में प्रो उमेशचंद्र झा, शिव नारायण मिश्रा, हरिहर प्रसाद, उमेश कुमार भवसिंका, उषा भवसिंका, सीमा गुप्ता, संगीता चौधरी, डॉ दीपक चौधरी, नृपेंद्र कुमार झा व अभय कुमार वियाहुत बतौर सदस्य है. पुस्तकाध्यक्ष के रूप में नवीन कुमार सेवा दे रहे है.

इस पुस्तकालय की स्थिति भी बदहाली के अंतिम पायदान को चुमने ही वाली थी कि वर्ष 1997 में प्रो उमेशचंद्र झा, प्रो शेष नारायण झा एवं उमेश कुमार भवसिंका ने पुस्तकालय के अस्तित्व रक्षा की दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाया. लायंस क्लब सेंट्रल के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दीपक कुमार चौधरी के सौजन्य से मुख्य भवन का जीर्णोद्धार कराया गया. साथ ही तत्कालीन विधान पार्षद डॉ रामचंद्र पूर्वे की निधि से वर्ष 1999 में पुस्तकालय परिसर कई अन्य कार्य भी कराये गए. वर्ष 2001 में पुस्तकों के रख रखाव हेतु गोदरेज आलमारी, स्टील रैक एवं जेनरेटर सेट राम स्वार्थ राय के सहयोग से उपलब्ध कराया गया. वर्ष 2008 -09 से लेकर अब तक कई अन्य कार्य भी कराये गए हैं, लेकिन अब तक इस पुस्तकालय में छात्रा एवं महिलाओं के लिए अलग वाचनालय की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी है. पुस्तकालय के सदस्य प्रो उमेशचंद्र झा की माने तो विकास की अगली कड़ी में उक्त वाचनालय का निर्माण पहली प्राथमिकता में शामिल होगी.

जिला मुख्यालय स्थित गीता भवन की ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रहनारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया व आचार्य जेवी कृपलानी सरीखा हस्तियों की लिखित प्रशंसा पत्र अब भी गीता भवन में बतौर धरोहर मौजूद है. गीता भवन के वर्तमान व्यवस्थापक डॉ आनंद प्रकाश वर्मा की माने तो अब भी करीब 5 हजार धार्मिक पुस्तकें गीता भवन में मौजूद हैं. बताया जाता है कि वर्ष 1991-92 से पूर्व तक बिहार सरकार के पुस्तकालय विभाग से कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती रही हैं. लेकिन अब कोई पूछने वाला भी नहीं है. स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन पुस्तकालयों की वर्तमान दशा से अनजान बनी हैं. नतीजतन अब इन ऐतिहासिक धरोहरों की हिफाजत एक गंभीर चुनौती बनने लगी है. डॉ वर्मा बताते हैं कि गीता भवन में प्रतिदिन निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाता है. दातव्य चिकित्सालय, जिला विकलांग संघ कार्यालय, महिला सिलाई-कटाई प्रशिक्षण के अलावा गरीब छात्रों को निःशुल्क आवास तक मुहैया कराया जा रहा है. मौजूद एक हॉल में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. साथ ही सामाजिक स्तर पर शादी समेत अन्य अवसरों पर गीता भवन आम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है. बताया जाता है कि सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर समुचित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण किताबी ज्ञान सरोवर अब सूखने के कगार पर पहुंच गया है.

इसके अलावा सोशल क्लब, बथनाहा प्रखंड मुख्यालय स्थित नरसिंह पुस्तकालय, नवयुवक पुस्तकालय पुपरी, हरिहरपुर चंदई कार्यालय चौक पुस्तकालय, झझिहट एवं पोखरभिंडा पुस्तकालय समेत अन्य महज अब नाम का पुस्तकालय रह गया है. जानकारों की मानें तो सोशल क्लब में अब प्राथमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है. वहीं बथनाहा का नरसिंह पुस्तकालय में पैक्स कार्यालय व सरपंच कचहरी का संचालन किया जा रहा है. पुपरी में एक निरक्षर व्यक्ति मोहन मिश्र ने पुस्तकालयों के अस्तित्व रक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किया. लेकिन इसकी तमाम मेहनत बेकार साबित होकर रह गई. बेलसंड अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद पुस्तकालय का वर्तमान में कोई पता भी बताने वाला नहीं है. पुस्तकालयों की दशा पर साहित्यकार डॉ राम बहादुर राय का कहना है कि समय रहते अगर पुस्तकालयों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले दिनों में साहित्य साधना भावी पीढी के लिए कठिन साबित होगी. साथ ही जिले में साहित्य के विकास पर ग्रहण भी लग जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

29 दिसंबर–04 जनवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति का दो दिवसीय सम्मेलन प्रसिद्ध धर्मस्थल विंध्याचल में हुआ, जिसमें विधानसभा मध्यावधि चुनाव की संभावना जताते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया गया है. भाजपा की इस रणनीति पर तीखा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसका कार्यकाल पूरे पांच साल का है. लेकिन भाजपा कुर्सी पाने के उतावलेपन में संविधान को तोड़ने और लोकतंत्र का हाथ मरोड़ने का इरादा जता रही है.

प्रभात रंजन दीन

मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटने का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी दी है या चुनौती, इसकी राजनीतिक समीक्षा हो रही है. मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध धर्मस्थल विंध्याचल में भाजपा कार्यसमिति के दो दिवसीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई और उस अनुरूप चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया. समाजवादी पार्टी ने भाजपा की इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता मिलने से आपा खो बैठी भाजपा अब उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार की बाहें मरोड़ने की तैयारी कर रही है. भाजपा उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रही है.

विंध्याचल के देवराहा हंसबाबा आश्रम में हुई भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटने के आह्वान के साथ ही सड़क पर संघर्ष तेज करने का फैसला किया गया. भाजपा ने यह तय किया कि भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त उत्तर प्रदेश के नारे के साथ वह सड़कों पर उतरेगी. भ्रष्ट इंजीनियर यादव सिंह व सपा सरकार के भ्रष्ट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घोटालों को केंद्रित करके व्यापक आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया गया. भाजपा को कहीं न कहीं यह भरोसा है कि अखिलेश सरकार अपने अंतर्विरोधों के चलते अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी. अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने भाजपा के चुनाव विशेषज्ञ ओम माथुर की मौजूदगी में भाजपा नेताओं की चिंतन बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने की रणनीति बनाने के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहा. बैठक में माथुर ने कहा भी कि उत्तर प्रदेश में वातावरण भाजपा के पक्ष में है. अब केवल कार्यकर्ताओं की संकल्प-शक्ति को एकजुट करने की जरूरत है. पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था से अधिक प्रभावी मुद्दा सपा-बसपा का भ्रष्टाचार रहेगा, जिस पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करने की जरूरत है. यह विचार बना कि नरेंद्र मोदी तरह सारे कार्यकर्ता न खाएंगे और न खाने देंगे के मंत्र के साथ माहौल तैयार कर जनता का विश्वास जीत लें, तो उत्तर प्रदेश भी भाजपामय हो जाएगा.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने सपा, बसपा व कांग्रेस की तिकड़ी के खात्मे का एलान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अब आर-पार की लड़ाई को तैयार हैं. सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के धन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं. आपसी मतभेदों में फंसी सरकार किसी भी दिन खुद ही धराशाई हो जाएगी. प्रदेश अध्यक्ष ने 31 दिसम्बर तक यूपी में भाजपा के सदस्यता-अभियान का रिकॉर्ड बनाने का भी दावा किया. उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद जनसमस्याओं को लेकर सड़कों पर आर-पार की लड़ाई के लिए उतरा जाएगा. आपको याद ही होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती भी उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के गिरने व सत्ताधारी दल के दो दर्जन से ज्यादा विधायकों के उनके सम्पर्क में होने का दावा कर चुकी हैं.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री रमापति शास्त्री ने संयुक्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राजनीतिक मसलों के साथ खेती और किसानों की समस्याओं का खास तौर पर उल्लेख किया गया है. बैठक में पारित संयुक्त प्रस्ताव से भाजपा के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ मिशन 2017 का एजेंडा भी स्पष्ट हुआ है. प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना ने संगठन की मजबूती में प्रभावी होने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका को जरूरी बताया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही व रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के बिजली संकट, जर्जर सड़कें व बेकाबू अपराध जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाने का निर्णय किया. आंदोलन को धारदार बनाने के लिए कानपुर के विधायक सतीश महाना के संयोजन में समिति का गठन किया गया. इसमें सह संयोजक अशोक कटारिया, सुरेश खन्ना, हनुमान मिश्र व विमला बाथम को शामिल किया है. समिति एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देकर आंदोलन के मुद्दे और कार्यक्रम तय करेगी. प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को जनता के सम्पर्क में रहने की हिदायत दी और कहा कि सदस्यता अभियान में बूथों पर प्रत्येक कार्यकर्ता मौजूद रहकर कम से कम सौ सदस्य बनाएं.

केंद्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि कार्यकर्ता पहले खुद को मजबूत करें, एकता दिखाते हुए संघर्ष की राह पकडें, तब सत्ता का लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा. यूपी के प्रभारी ओम माथुर का मानना था कि जब सबको काम मिलेगा तो खींचतान व गुटबाजी जैसी समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी. संगठन में सबको साथ लेकर व काम देकर लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा. कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को राजनीतिक समीक्षक नेताओं के घिसे-पिटे भाषणों का पुलिंदा बताते हैं. उनका मानना है कि राजनीतिक प्रस्ताव पिछले कुछ दिनों के दरम्यान हुए भाजपा नेताओं के भाषणों और बयानों का महज संशलिष्ट दस्तावेज है. प्रस्ताव में स्पष्ट राजनीतिक रणनीति का नितांत अभाव है. भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरणों के साथ समाजवादी पार्टी की घेरेबंदी की बातें जरूर हुईं पर कोई ठोस फार्मूला या रणनीति नहीं दिखी. यादव सिंह व गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जांच की मांग की गई, लेकिन जांच के लिए भाजपा कोई कानूनी या राजनीतिक पहल करेगी, इस बारे में कोई बात नहीं हुई. राजनीतिक प्रस्ताव में विक्टोरिया की बग्घी पर चढ़ कर जन्मदिन मनाने के लिए मुलायम को निशाने पर लिया गया लेकिन सादगी की कोई अपनी (भाजपाई) नजीर पेश नहीं की गई. बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा के बड़े-बड़े नेता कार्यसमिति की बैठक को छोटा ही समझते हुए आने की औपचारिकता निभा कर चलते बने. अधिकांश बड़े नेता तो प्रदेश कार्यसमिति से गायब ही रहे. जो आए भी वह झलक दिखाकर चले गए. केंद्रीय मंत्रियों में रामशंकर कठेरिया व संतोष गंगवार तो उद्घाटन के साथ ही चल पड़े. कलराज मिश्र भी उद्घाटन के बाद थोड़ी देर के लिए पहुंचे. साध्वी निरंजन ज्योति भी थोड़ी ही देर के बाद निकल गईं. रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आए ही नहीं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने भी आने की जहमत नहीं उठाई. वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश सिंह दूसरे दिन समापन सत्र में नहीं दिखे.

कार्यसमिति की बैठक का पहला सत्र पदाधिकारियों की बैठक और एजेंडा सदस्यता अभियान पर था. इसमें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने और स्वच्छता अभियान पर विशेष चर्चा की गई. बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मीडिया के लिए दिखावटी स्वच्छता अभियान चलाने से परहेज करने की सख्त हिदायत दी और कहा कि 25 दिसम्बर के बाद लोगों को ऐसा लगे कि कोई स्थान यदि साफ है, तो वह भाजपा के चलते है. माथुर ने कहा कि सुशासन, विकास व राष्ट्रवाद प्रदेश भाजपा के अभियान का फार्मूला होगा. कार्यसमिति की बैठक की जिस तरह तैयारियां की गई थीं, उससे लोगों को यही लगा था कि विंध्याचल में भाजपा के आला नेताओं का जमावड़ा रहेगा और खूब चहल-पहल रहेगी. लेकिन यह सब केवल तैयारियों तक ही रह गया. विंध्याचल के बघरा तिवारी गांव स्थित देवराहा हंसबाबा आश्रम भगवा और कमल निशान के झंडे बैनर से पाट दिया गया था. विंध्याचल अमरावती चौराहे से बघरा तिवारी आश्रम तक लगभग सात किलोमीटर लंबे मार्ग को केसरिया झंडे व कमल के फूल के बैनर से सजाया गया था. जगह-जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी न अन्य वरिष्ठ नेताओं का पोस्टर बैनर दिखाई दे रहा था. यह अजीबोगरीब संयोग ही है कि मथुरा में हुई कार्यसमिति की पिछली बैठक के समय देश-प्रदेश में लव-जिहाद का मामला गर्म था, तो इस बार विंध्याचल में हुई कार्यसमिति की बैठक के समय देश-प्रदेश में धर्मांतरण का मसला गर्म रहा. लेकिन उस समय भी लव-जिहाद के मुद्दे को औपचारिक नहीं बनाया गया और इस बार भी धर्मांतरण के मसले को औपचारिक विचार-विमर्श में शामिल नहीं किया गया. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मसले को भाजपा ही पुरजोर तरीके से उठाती रही है.

बहरहाल, कार्यसमिति की बैठक में राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताए जाने को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति किसी भी तरह सत्ता हथियाने का माध्यम है. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार है जिसका कार्यकाल पूरे पांच साल का है, लेकिन भाजपा कुर्सी पाने के उतावलेपन में संविधान को तोड़ने और लोकतंत्र का हाथ मरोड़ने का इरादा जता रही है. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति अभी से मध्यावधि चुनाव की तैयारी का प्रस्ताव कर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से भी दो कदम आगे चली गई है. भाजपा के पास प्रदेश की प्रगति के लिए कोई एजेंडा नहीं है. जनहित के किसी मुद्दे पर कार्यसमिति में चर्चा नहीं हुई. ■

feedback@chauthiduniya.com

21 साल बाद विंध्यधाम में आया राम और गया राम

अटल-आडवाणी युग में वर्ष-1993 में विंध्याचल के मुजफ्फरगंज स्थित खेतान स्मृति भवन में पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में भाजपा के दिग्गज पदाधिकारियों के साथ ही कई केंद्रीय नेता भी शामिल हुए थे. कार्यसमिति के सदस्यों में इस बार भी आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन वे सब केवल आया राम और गया राम ही साबित हुए. ■

जब मोदी भी बनाए गए थे पेज प्रभारी

भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने अपने सम्बोधन में कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के एक-एक पेज का प्रभारी बनाने की नसीहत दी और कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी पेज प्रमुख बनाया था. एक पेज पर जितने वोटर थे उनसे तीन-तीन बार मिलकर वोट के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई थी. मोदी ने इसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन भी किया था. ■

विंध्याचल के देवराहा हंसबाबा आश्रम में हुई भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटने के आह्वान के साथ ही सड़क पर संघर्ष तेज करने का फैसला किया गया. भाजपा ने यह तय किया कि भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त उत्तर प्रदेश के नारे के साथ वह सड़कों पर उतरेगी.

राज्यपाल के बयान पर बवाल

राम मंदिर का निर्माण शीघ्र होना चाहिए

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने दो संवेदनशील मसलों पर दो संवेदनशील बयान दिए और उन पर कई प्रतिक्रियाएं भी आईं. राज्यपाल ने कहा कि जनता की भावना का आदर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शीघ्र होना चाहिए. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का यह बयान तब आया जब पूरे देश में धर्मांतरण के मसले पर विवाद छिड़ा हुआ था. फिर नाईक ने यह भी कह दिया कि धर्मांतरण गलत नहीं है, अगर वह पूर्ण रूप से वैचारिक हो तो. क्योंकि विचार करने के बाद ही बाबा साहब अंबेडकर ने भी धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया था. राज्यपाल के इन दोनों बयानों से सुगबुगाहट तो फैली, लेकिन इस बहस में राजनीतिकों के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ. सपा नेता आजम खान ने अपने स्वभाव और लोगों की अपेक्षा के मुताबिक ही अपना बयान जारी किया. कुछ अन्य नेताओं ने भी राज्यपाल के बयान पर टिप्पणियां कीं, जिनमें कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं. फैजाबाद में पिछले दिनों राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द बनना चाहिए. राम मंदिर बनाना लोगों की इच्छा है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए. भव्य राम मंदिर का निर्माण जनभावना के अनुरूप है इसलिए अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए. पिछले महीने भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या गए राज्यपाल ने कहा था कि यह राम मंदिर का मसला अगले पांच साल में सुलझ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे शांति से सुलझाने की योजना पर काम कर रहे हैं.

राज्यपाल के इस बयान पर निंदा प्रस्ताव जारी हो ही रहे थे कि उन्होंने धर्मांतरण मसले पर भी अपनी बेबाक राय देकर विपक्षियों की माथे पर बल बढ़ा दिया. राज्यपाल ने इलाहाबाद में कहा कि धर्मांतरण मसले को सियासी तूल देना ठीक नहीं है. धर्मांतरण कतई गलत नहीं होता. संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था. धर्मांतरण हमेशा विचारों के आधार पर ही होना चाहिए. नाईक ने कहा कि धर्मांतरण में कुछ भी गलत नहीं होता है, यह सिर्फ विचारों का बदलाव होता है. धर्मांतरण राजनीतिक संघर्ष का नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव का मसला है. नाईक ने भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अंबेडकर का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था. वह संविधान निर्माता थे, फिर भी उन्होंने विचारों में बदलाव की वजह से धर्म परिवर्तन किया. यूपी में धर्मांतरण के जरिए समाज को बांटने की कोशिश के सवालों पर नाईक ने कहा कि इसे सही और सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की जरूरत है.

अयोध्या में राम मंदिर बनाने की हिमायत करने वाले राज्यपाल राम नाईक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा नेता मायावती ने कहा कि जबतक अदालत का कोई फैसला नहीं होता, तब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता. एनीसीपी के नेता तारिक अनवर ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसी मांग करना राज्यपाल के पद की अवहेलना है. सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है. यह संघ के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है. लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना इसका उद्देश्य है. भाकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर

बैठे व्यक्ति द्वारा विवादित मुद्दे पर बयान देना गलत है. सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राम नाईक ने किस चीज को लेकर यह बयान दिया है. व्यक्तिगत तौर पर दिया है या किसी और नजरिए से, पर ऐसे बयान से बचना चाहिए. मामला सुप्रीम कोर्ट में है ऐसे में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए. बाद में नरेश अग्रवाल ने यह भी कहा कि राम नाईक का बयान संविधान की अवमानना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. राज्यपाल के तौर पर ऐसा बयान देने से नाईक को परहेज करना चाहिए. वह अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर आसीन हैं. सपा के ही एक अन्य नेता अबू आजमी ने कहा कि राम नाईक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता हर रोज साम्प्रदायिक बयान दे रहे हैं.

जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि यूपी के राज्यपाल को हटाने के लिए हम लोग राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है.

नाईक की टिप्पणी पर बाबरी मस्जिद मामले के सबसे पुराने वादी हाशिम अंसारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि हम वार्ता की मेज पर आने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बातचीत शुरू करने से पहले केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों को सजा हो. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने तो राज्यपाल राम नाईक को यूपी का गवर्नर कम, अयोध्या मंदिर का पुजारी अधिक बता दिया. आजम खान ने कहा कि राम नाईक गवर्नर कम, अयोध्या मंदिर के पुजारी ज्यादा लगते हैं. वे अयोध्या के पुजारी की तरह ही बोल रहे हैं. आजम ने इसके साथ ही भाजपा नेता उमा भारती, साक्षी महाराज, महंत आदित्य नाथ पर भी जमकर निशाना साधा और अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दोषियों को सजा देने की मांग की. धर्मांतरण के मसले पर भी आजम ने तल्ख टिप्पणियां कीं.

दूसरी ओर भाजपा और शिवसेना ने नाईक के बयान को सही ठहराते हुए कहा है कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है. भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि क्या राम का नाम लेना गलत है. क्या राम का मंदिर बनाना गलत है. करोड़ों लोगों की भगवान राम पर श्रद्धा क्या गलत है. इसे गलत बताना विपक्ष का दीवालियापन है. विपक्ष को जनता के सामने सही मुद्दे उठाने चाहिए और दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए. राज्यपाल राम नाईक के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा, आरएसएस और शिवसेना ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है. भाजपा नेता [illegible] पाठक ने कहा कि हर कोई चाहता है कि राम मंदिर बने. [illegible] के बयान में कुछ भी गलत नहीं है. उधर, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल राम नाईक राम मंदिर आंदोलन के वक्त सक्रिय थे. अभी हमारे पास राम मंदिर बनाने का मौका है. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राम मंदिर का मसला अदालत में है और यह बातचीत के माध्यम से भी हल हो सकता है. हमने पहले भी कहा है कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाना चाहिए. ■

दलितों को बनवाया था ईसाई और बौद्ध

भाजपा के मौजूदा सांसद दलित नेता उदित राज ने सात वर्ष पहले हजारों दलितों का ईसाई और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कराया था. उस धर्मांतरण कार्यक्रम का बाकायदा आयोजन भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के 50 साल पूरे होने के मौके पर नागपुर में किया गया था. तब इस कार्यक्रम पर कोई बवाल नहीं मचा था. यह आयोजन एक रैली की शक्ल में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हजारों लोग पहुंचे थे. उस समय उदित राज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के परिसंघ के नेता बने हुए थे. उन्होंने उस समय दावा किया था कि धर्मांतरण सभा में ढो से ढाई हजार लोगों ने ईसाई और बौद्ध धर्म अपनाया. उदित राज ने कहा था, हमने गुजरात की मोदी सरकार को इस धर्मांतरण के जरिए बताने की कोशिश की है कि ईसाई और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से बेहतर हैं. धर्मांतरण कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के परिसंघ ने साझा तौर पर किया था. नागपुर की उस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म स्वीकार किया था. इस समारोह में अमेरिका और ब्रिटेन के 30 से अधिक प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस आयोजन पर वे सब चुप्पी साधे थे, जो आज खूब बोल रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकार की खामोशी से हाइकोर्ट नाराज

सीबीआई से जांच क्यों नहीं..!

वैष्णवी वंदना

भ्रष्टाचार के इंजीनियर यादव सिंह की करतूतें और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की बेरुखी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है. अब तो अदालत भी पूछने लगी है कि यादव सिंह की करतूतों की सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से यादव सिंह मामले में जवाब-तलब किया है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि यादव सिंह प्रकरण की क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराई जाए?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की बेंच ने समाजसेवी नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह नोटिस जारी की है. याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडेय का कहना था कि यादव का काला कारोबार पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती और वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में फला-फूला. यादव सिंह के पास से बड़े पैमाने पर काला धन व जवाहरात बरामद होने के कई दिन तक राज्य सरकार कार्रवाई के बजाय बगलें झांकती रही. सरकार यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रही है. इससे आगे भी निष्पक्ष जांच होने में संदेह है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए. जनहित याचिका में कहा गया है कि यादव सिंह से जुड़े घोटाले में सरकार की निष्क्रियता साफ नजर आ रही है. यादव सिंह को मुलायम, मायावती और अखिलेश के शासनकाल में राजनेताओं और बड़े अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिला. याचिका में यह भी विकल्प दिया गया कि किसी निष्पक्ष रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक समिति बनाई जाए जो इस मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करे.

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार खुद कार्रवाई कर रही है. लिहाजा, पीआईएल खारिज होने योग्य है. लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से भी जवाब मांगा है. साफ है कि यादव सिंह मामले पर अखिलेश सरकार की खामोशी का ही नतीजा है कि हाईकोर्ट को जवाब मांगना पड़ा है. हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा है कि यादव सिंह का करोड़ों का घोटाला उजागर हो जाने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए. हाईकोर्ट ने सरकारी दामाद के नाम से पहचाने जाने वाले नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह को पक्षकार बनाए जाने की भी मंजूरी दे दी है.

आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह और उसकी अरबों रुपये की काली सम्पत्ति पर यूपी सरकार का रवैया भले ही नरम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ब्लैक-मनी पर निगरानी के लिए बनी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है. एसआईटी के निर्देश पर इन्कम टैक्स (आईटी) और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी)

यादव सिंह और उसके करीबियों के खिलाफ जांच में मिल रहे तथ्यों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ साझा करेगी. एसआईटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एमबी शाह और उपाध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अरिजित पसायत ने लखनऊ में यादव सिंह के खिलाफ जांच का नेतृत्व कर रही सीबीडीटी की अध्यक्ष अनीता कपूर और इन्कम टैक्स के डीजी कृष्णा सैनी को निर्देश दिया है कि वह जांच में सामने आ रहे तथ्यों की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा करें, जिससे प्रवर्तन निदेशालय यादव सिंह व उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ कर कार्रवाई कर सके. यूपी के कई राजनेताओं और नौकरशाहों को एसआईटी की सक्रियता से झटका लगा है.

दूसरी तरफ सामाजिक-राजनीतिक धरातल पर भी यादव सिंह का कारनामों की सीबीआई से जांच कराने की मांग बढ़ती जा रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में जरा भी नैतिकता है तो वे तुरंत यादव सिंह के कारनामों की सीबीआई से जांच कराएं और उनकी डायरी में जिन नेताओं और अफसरों के नाम हों उन्हें न केवल उजागर करें बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश भी करें. उन्होंने कहा कि यादव सिंह ने प्रदेश के विकास का पैसा लूटा है. यह पैसा नेताओं और अफसरों की शह पर लूटा गया है. मुख्यमंत्री अगर नैतिक रूप से ईमानदार हैं, तो उन्हें पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार का सच सामने आ सके. डॉ. बाजपेयी ने कहा कि यादव सिंह प्रकरण में न तो सपा साफ-साफ कुछ बोल रही है और न ही बसपा ने कोई प्रतिक्रिया जताई है. कांग्रेस के नेता भी खामोश हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे यादव सिंह की डायरी के नामों का खुलासा करें और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें. बाजपेयी ने कहा कि सपा के बड़े नेताओं से यादव सिंह के रिश्ते धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. बसपा की ही तरह सपा के बड़े नेताओं से भी नोएडा अथॉरिटी के घोटालेबाज यादव सिंह के नजदीकी रिश्ते हैं. भ्रष्टाचार पर सपा और बसपा नेताओं में मिलीभगत है. दोनों एक-दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं. ऐसी कई घटनाएं हैं जो यादव सिंह और सपा नेताओं के रिश्तों को साबित करती हैं. यादव सिंह के खिलाफ पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, पर वह इंटरपोल को नहीं मिला. सपा सरकार चुप्पी साधे बैठी रही. इसके लगभग एक साल बाद सरकार ने उसे तीन-तीन प्राधिकरणों की जिम्मेदारी सौंप दी. यही नहीं, यादव सिंह के खिलाफ बैठाई गई सीबी-सीआईडी जांच रिपोर्ट में उसे निर्दोष साबित कर दिया गया. बाजपेयी ने सवाल उठाया कि वह रिपोर्ट अगर सही थी तो फिर अब हो रही जांच में अनियमितताएं कैसे सामने आ रही हैं. जाहिर है, सपा सरकार ने बसपा से मिलीभगत के चलते यादव सिंह को संरक्षण दिया.

नोएडा घोटाला प्राधिकरण

जून 2012 में नोएडा विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह का किया घोटाला विशाल आकार का है. घोटाले में यादव सिंह के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीओ कैप्टन एसके द्विवेदी और चेयरमैन मोहिंदर सिंह का नाम भी जुड़ा है. घोटाले का खुलासा होने के बाद भी यादव सिंह ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले आठ दिनों में ही 965 करोड़ रुपये का घोटाला कर डाला था. उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण का सालाना बजट लगभग 2,000 करोड़ का है, लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार के चहेते अधिकारी यादव सिंह ने आला अफसरों से मिल कर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की जमीन में हेराफेरी की. घोटाले में तिरुपति कंस्ट्रक्शंस और जीएसपी कंस्ट्रक्शंस के नाम हैं. दोनों कम्पनियों को नोएडा अथॉरिटी ने बाद में काली सूची में डाला. यादव सिंह ने कुछ ठेकेदारों से मिल कर एक ही झटके में 200 करोड़ का घोटाला कर दिया. उसने बिना काम के ही ठेकेदारों को 964-बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ का भुगतान कर दिया था.

नोएडा में करोड़ों की सरकारी जमीन का एक और घोटाला सितम्बर 2012 में खुल कर सामने आया था. जांच से पता चला था कि ग्रेटर नोएडा में 1800 बीघा जमीन ही सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब हो गई है. इस सरकारी जमीन का बाजार भाव करीब 350 करोड़ रुपये आंका गया था. नोएडा में 1994 में भी भूखंड घोटाला हुआ था. तब नीरा यादव नोएडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं. नीरा यादव ने अपनी दो बेटियों सुरुचि और संस्कृति के नाम व्यावसायिक भूखंड आवंटित करवाए थे. दोनों बेटियों का कारोबार दिखाया जबकि जांच में पता चला था कि तब सुरुचि दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में और संस्कृति किसी ब्रितानी कॉलेज में पढ़ रही थीं. 16 अक्टूबर 2002 को सीबीआई ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था जिसमें नीरा के साथ-साथ तत्कालीन डिप्टी सीईओ आईएएस राजीव कुमार भी आरोपी बनाए गए थे. 7 दिसम्बर 2010 को सीबीआई की विशेष अदालत ने नीरा और फ्लेक्स ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक चतुर्वेदी को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी. नोएडा भूमि घोटाले में नवम्बर 2012 में उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव और आईएएस राजीव कुमार को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन-तीन साल की कैद की सजा दी. दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नीरा ने भूमि उपयोग बदलने के लिए तत्कालीन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव से मिल कर साजिश रची थी. वही राजीव कुमार आज अखिलेश सरकार में खास नौकरशाह बने हुए हैं.

नौकरशाहों से मिलीभगत कर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सिंचाई विभाग की 20 हजार करोड़ की जमीन बिल्डरों के हाथों कौड़ियों में बेच डाली थी. इस घोटाले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ-साथ नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अध्यक्ष मोहिंदर सिंह और सीईओ कैप्टन एसके द्विवेदी शामिल थे. नोएडा में करीब डेढ़ सौ फार्म हाउसों की जमीन आवंटन का एक बड़ा घोटाला सितम्बर 2012 में सामने आया. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. नोएडा में मायावती सरकार ने 2009-10 और 2010-11 में फार्म हाउस योजना के लिए 12 गावों के किसानों की उपजाऊ जमीनें अधिगृहित कर दस-दस हजार वर्ग मीटर के डेढ़ सौ भूखंड सस्ती दरों पर कम्पनियों और रसूखदारों को दे दिए थे. अपने चहेतों की तिजोरियां भरने के लिए सरकारी तिजोरी को अरबों रुपये का चूना लगाया गया. दिसम्बर 2012 में नोएडा के घोटालों की सूची में 3,800 करोड़ रुपये का एक और बड़ा मामला जुड़ा, वह था लीज बैक घोटाला. इसमें तीन लाख 81 हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन बाहरी लोगों समेत तीन निजी कम्पनियों के नाम कर दी गई थीं.

न्यूज चैनल में लगा है यादव सिंह का पैसा

यादव सिंह के घोटालों की कमाई एक नेशनल न्यूज चैनल में भी लगी है. काले धन की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) इस बात की भी जांच कर रही है. पता चला है कि यादव सिंह ने अपनी पत्नी कुसुमलता के माध्यम से अपनी काली कमाई के एक बड़े हिस्से को एक नेशनल न्यूज चैनल में इनवेस्ट किया है. यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता को इस चैनल में निदेशक जैसी कोई अहम भूमिका दी गई है. मीडिया से बचने के लिए मीडिया को उपकृत करने के इरादे से यादव सिंह ने चैनल में पैसा लगाया था. उसकी कोशिश थी कि जिस तरह उसने नेताओं और नौकरशाहों को अपने पैसे से खरीद रखा था, उसी तरह वह मीडिया को भी अपनी जेब में रखे. जिस चैनल में उसने पैसा लगाया वह चैनल राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर शीर्ष निजी समाचार चैनलों में स्थान रखता है. ■

मैत्रेय परियोजना के साथ शत्रुता निभाती सरकार

शत्रुंजय सिंह रैकवार

प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो पर प्रदेश के विकास के मामलों में सबका रवैया एक ही जैसा रहा है. भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रस्तावित मैत्रेय परियोजना की दुर्दशा देख कर ऐसा ही लगता है. वर्ष 2000 से मैत्रेय परियोजना के कुशीनगर में लागू होने की जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो जनपद ही नहीं पूरे पूर्वांचल में कुशीनगर के सिंगापुर हो जाने की चर्चा शुरू हो गई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में कुशीनगर के स्थापित होने की उम्मीदें एक सपने की तरह यहां के लोगों में पलने लगीं. लेकिन प्रदेश के नेताओं और नौकरशाहों ने अपनी कार्यशैली से मैत्रेय परियोजना की ऐसी-तैसी कर दी. आज 13 वर्ष बीत गए. मैत्रेय परियोजना जहां से शुरू हुई थी, वहीं पर थमी हुई है. बदला है तो केवल परियोजना का आकार और प्रकार. राज्य सरकार तथा मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट के बीच 9 मई 2003 में हुए एमओयू में संशोधन करने तथा अनुपूरक एमओयू करने को मंजूरी दे दी गई है. अब संशोधित व अनुपूरक एमओयू के मुताबिक मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट को 250-300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. महात्मा बुद्ध की स्थापित की जाने वाली मूर्ति की ऊंचाई 500 फीट के स्थान पर अब 200 फीट होगी. अब यह मूर्ति कांस्य के बजाय कंक्रीट और सीमेंट से बनेगी और कांस्य में कवर होगी. मैत्रेय परियोजना हेतु भूमि का हस्तान्तरण सरकार मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट को लीज डीड के माध्यम से करेगी.

तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रस्तावित 400 करोड़ की महत्वाकांक्षी मैत्रेय परियोजना के शिलान्यास को भी एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत कब होगी किसी को पता नहीं. जबकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों लखनऊ के एक शिलान्यास कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष अधिकारियों से पूछा था कि उद्घाटन की तारीख बताई जाए, केवल शिलान्यास से काम नहीं चलने वाला. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना की आधारशिला रखी थी तो विकास के सपने भी दिखाए थे. जिले की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदलने की बातें कही थीं. विकास के लिहाज से पिछड़े कुशीनगर इलाके में विश्व स्तरीय अस्पताल व विश्वविद्यालय आदि के निर्माण की बात से लोगों में उम्मीद जगी थी कि हालात अब बदलेंगे. लेकिन अफसोस है कि तस्वीर बदलने का कोई प्रयास नहीं हो रहा तो तकदीर कैसे बदल जाएगी. मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास होने के बावजूद एक साल से परियोजना का थोड़ा भी काम नहीं होना बेहद शर्मनाक भी है और हास्यास्पद भी. इससे सूबे में संचालित अन्य योजनाओं की गति का भी पता चलता है. प्रशासन व किसानों के बीच तकरीबन एक दशक तक चले विवाद के पश्चात बनी सहमति के बाद 13 दिसंबर 2013 को महत्वाकांक्षी मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुशीनगर आए थे. परियोजना को विकासपरक बताते हुए उन्होने यहां के लोगों को भरोसा दिलाते हुए वादा किया था कि परियोजना को जमीन पर शीघ्र उतारने को लेकर कवायद अंतिम दौर में है. संस्कृति विभाग ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है. मकसद है इस पिछड़े इलाके में विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना. पर मुख्यमंत्री की यह बातें केवल तकरीरी होकर रह गईं. मुख्यमंत्री के हाथों रखी गई आधारशिला के साथ ही शिलान्यास के पत्थरों पर अंकित उन शब्दों के मायने धुंधले पड़ने लगे हैं.

37 देशों में काम, यूपी में आराम

मैत्रेय परियोजना कुशीनगर महायान शाखा संरक्षण परिसंघ (एफपीएमटी-फाउन्डेशन फॉर प्रिजरवेशन ऑफ महायान ट्रेडिशन) द्वारा संचालित एक परियोजना है. एफपीएमटी की स्थापना तिब्बती धर्मगुरु लामा तिबुतेन येशे ने 1964 में की थी. इस संस्था का मानना है कि लोगों में प्रेम, दया, करुणा जैसे उदात्त भावों को जगाने के लिए मैत्रेय की विशाल प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए. इस उद्देश्य के लिए मैत्रेय परियोजना इंटरनेशनल की स्थापना की गई और दुनिया के कई देशों में मैत्रेय की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया. कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना को संचालित करने के लिए मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट बनाया गया है जो यूपी में एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है. इसके अध्यक्ष संजीव चौधरी हैं. इसी संस्था द्वारा बिहार के बोधगया में भी मैत्रेय परियोजना संचालित की जा रही है. वहां भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किए जाने का विचार है. एफपीएमटी दुनिया के 37देशों में काम कर रहा है और दर्जन भर कल्याणकारी परियोजना चला रहा है. इसका कार्यालय अमेरिका में है. इसके आध्यात्मिक निदेशक लामा जोंपा रिनपोछे हैं. मैत्रेय परियोजना की वेबसाइट पर कहा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध का भावी अवतार मैत्रेय के रूप में होगा. कुशीनगर में बुद्ध शाक्य मुनि ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. बौद्ध धर्मग्रन्थों के मुताबिक आने वाले समय में कुशीनगर मैत्रेय बुद्ध के जीवन काल में पुनः महत्वपूर्ण स्थल बन जाएगा. इस वेबसाइट में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का विचार था कि धार्मिक मूर्तियां, स्तूप तथा चित्र जैसी धार्मिक वस्तुएं ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिनसे लोगों को आध्यात्म की राह मिलती है.

बुद्ध की स्थली पर ईसाई बनाने का धंधा

भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल पर ईसाई मिशनरियां प्रलोभन देकर गरीबों का खुलेआम धर्मांतरण करा रही हैं, लेकिन आगरा में धर्मांतरण पर चीखने-चिल्लाने वाले लोगों को कुशीनगर की हरकतें नहीं दिखतीं. आगरा में धर्मांतरण को लेकर जिस समय हो-हल्ला हो रहा था, उसी समय कुशीनगर के गांव गंगुआ मठिया में ईसाई मिशनरियां पांच हिंदू परिवारों के 27 लोगों को ईसाई धर्म कबूलवा रही थीं. ग्रामीण बताते हैं कि बिहार सीमा से सटे कुशीनगर के गांव गंगुआ मठिया के दिलीप गुप्ता के घर एक पादरी का छह माह से आना-जाना था. वे सुबह-सुबह लोगों को एकत्रित कर ईसा मसीह की प्रार्थना वगैरह कराते थे. लोगों ने एक सुबह देखा कि दिलीप गुप्ता के घर पर गांव के प्रभु प्रजापति, किशन गुप्ता, मालती गुप्ता व रमावती गुप्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ ईसा मसीह की प्रतिमा रख कर विशेष प्रार्थना कर रहे हैं. बाद में अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच गए. इसके बाद धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला जिला मुख्यालय तक पहुंचा. ग्राम प्रधान अजय खरवार ने बताया कि दिलीप गुप्ता मुम्बई में नौकरी करता है. उसने एक साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था. गांव में एक मिशनरी के पादरी का आना-जाना लगा रहा. पादरी के साथ अन्य लोगों का भी गांव में आना-जाना लगातार बना रहा. वे गांव के भोले-भाले लोगों को समझाते रहे और अपने प्रभाव में लेते रहे. पादरी और दिलीप ने लोगों को आर्थिक सुधार और बेहतर इलाज जैसे प्रलोभन देकर ईसाई बनाने में भूमिका निभाई. उनकी इस कोशिश से चार हिंदू परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया. धर्म परिवर्तन की सूचना पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उप-जिलाधिकारी श्रीप्रकाश शुक्ल ने गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल भी की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिलाधिकारी लोकेश एम. कहते रहे कि मामला नया नहीं, पुराना है. जिला प्रशासन की लापरवाही से गांव के लोगों का धर्मांतरण कराने वाला पादरी पकड़ा नहीं जा सका और दिलीप गुप्ता समेत अन्य लोग भी फरार हैं.

इस बीच हिंदू संगठनों ने गांव में जल्द घर वापसी कार्यक्रम आयोजित कर सभी को हिंदू बनाने की तैयारी का ऐलान किया है. गांव में हलचल बढ़ने पर कई भाजपा नेताओं ने भी प्रधान से फोन पर जानकारी ली. साथ ही ईसाई बने सभी परिवारों को जल्द हिंदू धर्म में वापस लाने की योजना बताई. ■

भूरा का फरार होना पुलिस की लापरवाही है

चौथी दुनिया ब्यूरो

भूरा फरारी कांड को लेकर पुलिस अब तक जांच की दिशा तय नहीं कर पाई है. अभी प्राथमिक रूप से पुलिस के पास ऐसी एक भी जानकारी या सुराग नहीं जिसके आधार पर आगे बढ़ सके, जिसके कारण उत्तराखंड पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है. इस मामले में कोई भी अधिकारी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है. भूरा फरारी कांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. राज्य की जनता के मन में उत्तराखंड के डीजी और एसएसपी की कार्यप्रणाली को लेकर ही अनेक सवाल उठ रहे हैं. आम जनता के मन में यह बात साफ हो गई है कि यह पुरा मामला डीजी और एसएसपी दोनों दिग्गजों की दृष्टिकोण की कमी के कारण ही घटीत हुई. बिना सरकारी वाहन के गैर राज्य, गैर जनपद में एक कुख्यात अपराधी को पेशी पर भेजा ही क्यों गया. खबर है कि भूरा अपने साथियों को साथ में चल रहे एक सिपाही के फोन से ही मैसज भेज कर अपने लोकेशन की जानकारी दे रहा था. साथ में चल रहे सिपाहियों को भूरा ने पूरी दावत देने के साथ सर्दी भगाने(शराब) की दवा भी दे रखी थी, जिससे लूटेरों को सरकारी अत्याधुनिक हथियार लूट कर ले जाने में कोई खास असुविधा नहीं हुई. जांच में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज पुलिस अधिकारी जुटे हैं. इसके बाद भी सभी के हाथ खाली हैं. इसका मूल करण आज भी इस मामले में जुटे आला अफसरों ने अपने पुलिस कर्मियों का आत्म निरीक्षण भी नहीं किया. साथ में गए पुलिस कर्मियों के मोबाइल ही अगर कब्जे में तत्काल ले कर जांच शुरू की होती तो अब तक परिणाम ही कुछ और होते. पुलिस अब तक इन लोगों तक नहीं पहुंची जिनका इस कांड से संबंध है.

बदमाश अमित भूरा फरार हो गया. सुशील राठी गैंग का कुख्यात बदमाश भूरा के साथ ही दो एके-47 जैसे हथियार भी लूट ले गए. सफेद रंग की स्कार्पियों सवार बदमाशों ने तब टक्कर मार दी जब पुलिस की टीम भूरा को कोर्ट ले जा रही थी. टक्कर के बाद स्कार्पियों से उतरे बदमाशों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च का स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम दिया. इधर भूरा के साथ पेशी ड्यूटी वाले पुलिस कर्मियों ने स्थानीय बागपत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद नाकेबंदी कर भूरा को पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस को सफलता नहीं मिली. अमित भूरा के फरारी के बाद पुलिस महकमे में भय का माहौल है. यह माहौल पुलिस के खुद की सुरक्षा के साथ ही बड़ी वारदात को लेकर भी है. भूरा का अब तक का इतिहास बताता है कि वह जेल से भागने के बाद हमेशा बड़ी वारदातओं को अंजाम देता रहा. इस लिहाज से पुलिस न सिर्फ सुरक्षा को लेकर चौकन्नी है. गिरफ्तारी के प्रयास में कई पुराने पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. भूरा पर नजर रखने वालों की माने तो फरारी के बाद तुरंत वह वारदात को अंजाम दे सकता है. इसके लिए वह उत्तराखंड के बजाए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब के किसी शहर को निशाना बना सकता है. उसकी कार्यशौली की जानकारी रखने वालों की माने तो जेल से भागने के पहले ही भूरा ने अपना शिकार तय कर लिया होगा. बड़े शिकार को रडार पर लेने के बाद ही उसने फरार होने की योजना बनाया होगा. इसके चलते वह हथियारों की खेप व वाहन वारदात वाले स्थान पर पहुंचा चुका होगा. अब वह सिर्फ इसे अंजाम देने की बाट जोह रहा होगा. इन आशंकाओं के चलते हरिद्वार के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में दहशत का माहौल है जहां भूरा का दबदबा रहा है. इसके चलते पुलिस कई रणनीति पर एक साथ काम कर रही है. बताया जा रहा कि पहले भूरा की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले कुछ मुखबिरों पर पुलिस की पैनी निगाह है. इसके साथ पुलिस के जवान गुप्त रूप से तैयार हैं. भूरा ने किसी तरह से उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो पुलिस उसे दबोच लेगी. सूबे के कई दिग्गज, सन्त, महन्त, राजनेता, बड़े व्यापारियों की दिन की चैन रात की नींद हराम हो गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चोराबाड़ी ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन का शिकार

चौथी दुनिया ब्यूरो

पिछले साल केदारनाथ की आपदा के लिए जिम्मेदार चोराबाड़ी ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के असर का शिकार हो रहा है. वर्ष 1962 से लेकर 2012 तक यह ग्लेशियर करीब 344 मीटर सिकुड़ चुका है और तो और इसका फ्रंट एरिया भी एक फीसद सिकुड़ चुका है. वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी के हालिया अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है. चोराबाड़ी ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम होता है. अलकनंदा आगे जाकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, जहां उसका नाम गंगा पड़ता है. ग्लेशियर के आकार पर जलवायु परिवर्तन के असर के अध्ययन के लिए जीपीएस आंकड़े और सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट का इस्तेमाल किया गया. हिमालयी हिमनदों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर रहा है, क्योंकि एक तो ये क्षेत्र बहुत दुर्गम है, दूसरे इन क्षेत्रों के मौसमी आंकड़े व जलवैज्ञानिक आंकड़े नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले ये मिलते ही नहीं हैं. ऊपर से इस सीमांत इलाकों की नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डाटा क्लासीफाइड श्रेणी में आता है. अध्ययन करने वाले दल में डॉ. डीपी डोभाल, मनीष मेहता, कपिल केसरवानी, भानुप्रताप, अमित कुमार व अक्षय वर्मा आदि शामिल थे. वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी लंबे समय से चोराबाड़ी ग्लेशियर का मॉनीटरिंग कर रहा है. अध्ययन के दौरान 1962 से लेकर 2012 तक चोराबाड़ी ग्लेशियर की लंबाई और फ्रंट एरिया में आए बदलावों की पड़ताल की गई. अध्ययन से पता चला कि चोराबाड़ी ग्लेशियर के क्षेत्रफल में इस अवधि में काफी कमी आई है. ग्लेशियर अपने फ्रंट एरिया का एक फीसद और अपनी 344 मीटर लंबाई खो चुका है. 1962 से लेकर 2003 तक ग्लेशियर ने 262 मीटर लंबाई खो दी यानी 2003 से 2012 के एक दशक में ग्लेशियर 82 मीटर सिकुड़ गया है. दिलचस्प बात यह है कि चोराबाड़ी पर जलवायु परिवर्तन का असर दो अलग- अलग तरीकों से हुआ है. जहां 1962 से लेकर 1990 तक यह धीरे-धीरे सिकुड रहा था, वहीं 1990 से लेकर 2012 तक ग्लेशियर के सिकुड़ने में तेजी आई है. ■

मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने की तैयारी

प्रदेश की हरीश सरकार और प्रदेश कांग्रेस संगठन दोनों ने केंद्र की मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने की तैयारी कर ली है और यह जंग दिल्ली की सड़कों कर लड़ी जाएगी. राज्य के हितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर सत्याग्रह कर अपनी मंशा साफ कर दिया. विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के हालिया बयानों और पीएम को भेजे गए पत्र से यह साफ है कि प्रदेश सरकार व कांग्रेस संगठन अब केंद्र की मोदी सरकार को किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है. इस पूरी जंग को परोक्ष रूप से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है. केंद्रीय योजना आयोग, हाइड्रो प्रोजेक्ट के बाद अब ईको सेंसिटिव जोन को लेकर भी मुख्यमंत्री रावत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. हाल में केंद्रीय योजना आयोग के विकल्प को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक और इसके बाद इंटीग्रेटेट माउंटेन इनिशिएटिव की ओर से आयोजित 11 हिमालयी राज्यों की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत योजना आयोग को खत्म करने के केंद्र के एक तरफा फैसले का विरोध कर चुके हैं और इसे संघीय व्यवस्था पर चोट बताया, उन्होंने केंद्र के फैसले से हिमालयी राज्यों को भारी नुकसान की आशंका भी जताई है. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे पर यह सवाल उठा रहे हैं. मुख्यमत्री हरीश रावत ने गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर हलफनामे पर आपत्ति जताई और हाइड्रो प्रोजेक्टो को रोके जाने से उत्तराखंड को हो रहे नुकसान की भरपाई की मांग तक कर डाली. वह इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए पहले ही कह चुके हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट रुकने से उत्तराखंड को हर साल 1800 करोड़ का नुकसान हो रहा है. वह कह चुके हैं कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर अन्यायपूर्ण रूख से राज्य के सभी महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, जो पूरा खेल प्रधानमत्री मोदी के इशारे पर खेला जा रहा है. जिसका देश की ऊर्जा सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय है. इसी तरह गंगा की सफाई के लिए वह प्रदेश के लिए 10 हजार करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं तो 2014-15 के लिए भी चार हजार करोड़ का पैकेज मांग चुके हैं. मुख्यमंत्री हरीष रावत ने उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक ईको सेंसिटिव जोन को लेकर केंद्र के खिलाफ नया मोर्चा खोला है. उन्होंने ईको सेंसिटिव जोन के पक्षधरों पर तंज कसते हुए कहा कि ईको सेंसिटिव जोन का मास्टर प्लान बनाना आसान नहीं है. उन्होंने यह सलाह तक दे डाली कि जो लोग ईको सेंसिटिव जोन के प्रेणता माने जा रहे हैं, वही इसका मास्टर प्लान बनाकर दे दें. प्रदेश की उपेक्षा के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक दिवसीय सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदेशभर के सभी कांग्रेसी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक व नगर अध्यक्ष, जिला व ब्लॉक व नगर सदस्यता प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रमुख, पूर्व प्रमुख, अनुसांगिक संगठनों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, दर्जा प्राप्त कांग्रेससियों सहित पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. 1-उत्तर-पूर्व के राज्यों की तरह सभी उत्तराखंडियों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण 2- उत्तराखंड को फिर से अगले 10 वर्षों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज 3-मुख्यमंत्री के गंगा को प्रदूषण मुक्त करने व जल संवर्धन के प्रथम चरण प्रस्ताव को मंजूरी 4-पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन बोनस के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी 5-2014 में आई आपदा से राहत व पुनर्वास के लिए 4000 करोड़ की मदद 6-आईडीपीएल से एचएमटी जैसे उपक्रमों के पुनर्जीवन के लिए आर्थिक पैकेज 7-प्रदेश में गंगा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 10 हजार करोड़ का पैकेज जोन को लेकर भी मुख्यमंत्री का कड़ा रुख सरकार की भावी रणनीति की ओर इशारा कर रही है. ■

-चौथी दुनिया ब्यूर्रो

> खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करने वाले ओम शंकर द्विवेदी ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को भी खनन मंत्री के भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए मंत्री की सम्पत्ति की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है. इस सिलसिले में ओमशंकर द्विवेदी ने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और खनन मंत्री की अवैध कमाई के कई सुबूत मीडिया के सामने पेश किए. द्विवेदी ने यह भी कहा कि लोकायुक्त से शिकायत में 943 करोड़ की सम्पत्ति की बात कही गई थी.

भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अखिलेश सरकार के खनन मंत्री

गायत्री प्रजापति

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जिन खामियों की ओर लगातार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ध्यान दिलाते रहे और मुख्यमंत्री लगातार जिसकी अनदेखी करते रहे, वही खामियां अब अपने-आप ही उभर कर सतह पर आने लगी हैं. मुलायम बार-बार यह कहते रहे कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जन-विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. अब जब विधानसभा चुनाव का समय भी नजदीक आने लगा है, उस समय अखिलेश सरकार के मंत्रियों के भ्रष्ट कारनामे पार्टी पर संकट लेकर आने वाले हैं. इनसे समय रहते उबर लिया गया होता तो चुनाव के समय कम से कम छवि पर संकट नहीं छाता. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे चहेते मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार की गाथाएं अब सत्ता गलियारे से लेकर सड़क-चौराहे तक सुनाई दे रही हैं. प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार की कहानियां अब तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताईं जा रही हैं. अब यह भी खुलासा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आइकॉन बने यादव सिंह की डायरी में भी गायत्री प्रजापति जैसे मंत्रियों के नाम सुशोभित हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसे यादव सिंह के मामले में चुप्पी साधे रहे और पत्रकारों को मिठाई खिलाते रहे, उसी तरह गायत्री प्रजापति के मसले पर भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं. जबकि अखिलेश भी यह समझ ही रहे हैं कि अब गायत्री भी प्रजापति को बचा नहीं पाएंगी.

पार्टी के भीतर ही गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार को लेकर खुली चर्चाएं होने लगी हैं. मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त के यहां आय से अधिक सम्पत्ति की जांच शुरू होने के बाद अब यह चर्चा जोरों पर है कि आरोपों से घिरे अपने खास मंत्री को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंत्री के पद से बेदखल करते हैं कि नहीं. मुख्यमंत्री की तमाम पारदर्शिता प्रजापति के नाम पर दांव पर लगी है. सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है. गायत्री पर लगे आरोपों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गंभीरता से लिया है और वे मुख्यमंत्री के निर्णय की तरफ देख रहे हैं.

आप यह याद करते चलें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति का कद पार्टी और सरकार में कैसे बढ़ती चली गई. अमेठी के विधायक गायत्री प्रजापति को सरकार बनते ही मंत्री नहीं बनाया गया था. जब पहली बार फरवरी 2013 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब 11 मंत्रियों के साथ गायत्री को भी राज्यमंत्री बनाया गया. लेकिन सरकार को गायत्री प्रजापति के हुनर का पहले से पता था. खनन जैसा महत्वपूर्ण धन-उत्पादक विभाग दिए जाने से गायत्री की कद का लोगों को पता चल गया. बसपा सरकार में यह विभाग कभी मायावती के करीबी रहे स्वनामधन्य बाबू सिंह कुशवाहा के पास था. खनन मंत्री बनने के बाद प्रजापति ने 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने की राजनीति शुरू कर दी. उस समय सपा प्रमुख मुलायम प्रजापति की इन कोशिशों से खुश हुए और उसे जनवरी 2014 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया. कैबिनेट मंत्री बनने से खनन विभाग के जरिए प्रजापति की धन-उत्पादकता और तेजी से बढ़ती चली गई. लोकसभा चुनाव में अति-पिछड़ों को लुभाने की अतिरिक्त हेलीकॉप्टरी-शक्ति देने के बावजूद फेल हो जाने वाले गायत्री प्रजापति के अतिरिक्त हुनर के कारण ही मंत्री वाली औकात कहीं से भी कम नहीं हुई.

मंत्री बनने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति न रह कर अरबपति हो गए. उनकी सम्पत्ति 500 गुणा से ज्यादा हो गई. गायत्री के भ्रष्टाचार के बारे में लोकायुक्त से की गई शिकायत में कहा गया है कि भूतत्व और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जब विधानसभा चुनाव में नामांकन किया था तब उनकी सम्पत्ति 1.81 करोड़ रुपये थी. लोकायुक्त ने भी इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि की है. मंत्री बनने के बाद गायत्री ने 942.57 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बनाई. साक्ष्य के रूप में अमेठी, लखनऊ सदर और मोहनलालगंज में प्रजापति द्वारा अपने-अपने परिवारीजनों, रिश्तेदारों और करीबियों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज लगाए गए हैं. यह शिकायत प्रतापगढ़ के ओम शंकर द्विवेदी ने की है. शिकायत के साथ हाईकोर्ट के वकील अजय प्रताप सिंह राठौर ने अपना वकालतनामा भी लगाया है. उन्होंने 1725 पन्ने साक्ष्य के रूप में संलग्न किए हैं.

खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करने वाले ओम शंकर द्विवेदी ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को भी खनन मंत्री के भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए मंत्री की सम्पत्ति की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है. इस सिलसिले में ओमशंकर द्विवेदी ने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और खनन मंत्री की अवैध कमाई के कई सुबूत मीडिया के सामने पेश किए. द्विवेदी ने यह भी कहा कि लोकायुक्त से शिकायत में 943 करोड़ की सम्पत्ति की बात कही गई थी. लेकिन 13 दिसम्बर तक कई और सम्पत्तियों का ब्यौरा मिल गया. सम्पत्तियों के खुलासे का सिलसिला जारी है. अब तक गायत्री की 1350 करोड़ की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री मिल चुकी है. लोकायुक्त के यहां सुनवाई में यह साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे. गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की जांच की औपचारिकताएं शुरू करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर शिकायत के समर्थन में साक्ष्य दाखिल करने को कहा है. इसके बाद ही परिवाद दर्ज करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी. प्रतापगढ़ के ओमशंकर द्विवेदी ने लोकायुक्त के यहां दाखिल शिकायत में इल्जाम लगाया है कि मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पद का दुरुपयोग कर अपने सम्बन्धियों, ड्राइवर और नौकरों के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति जुटा ली है. शिकायत के साथ संलग्न 1725 पेज के साक्ष्य की पड़ताल के बाद ही लोकायुक्त ने मामले में प्रारंभिक जांच शुरू की है. लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने कहा कि गायत्री प्रजापति खिलाफ दाखिल 23 पेज की शिकायत के साथ 1725 पेज साक्ष्य हैं, जिसकी प्रारम्भिक जांच हो रही है. मंत्री पर सीधा इल्जाम नहीं है, लेकिन बेटों, पत्नी, ड्राइवर और दोस्तों पर लगे आरोप काफी गम्भीर हैं. उनकी हिस्सेदारी वाली कम्पनियों के पंजीयन के समय और अब की पूंजी का ब्यौरा जुटाया जा रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.

उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रसाद ने 2012 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में 1.83 करोड़ की सम्पत्ति दिखाई थी. शिकायतकर्ता द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष दिया गया वह शपथ पत्र झूठा है. गायत्री ने अपने बेटों अनिल व अनुराग प्रजापति की एक भी सम्पत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र में नहीं दिया है. जबकि वह भी करोड़ों में है. द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की शिकायत वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से भी करेंगे. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि गायत्री प्रसाद के दो ड्राइवरों के पास ही 40 करोड़ की सम्पत्ति है. जबकि उनके परिवार वालों के नाम से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी काफी जमीनें हैं. अखिलेश सरकार के खनन मंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोपों की लम्बी सूची है. प्रजापति पर लखनऊ में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉट बेचने का भी आरोप लगा था.

इसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति पर अमेठी में तहसील की सरकारी जमीन पर कब्जा करने, कागजात में हेराफेरी करने और स्टाम्प चोरी करने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं. इससे पहले अमेठी की एक विधवा ने भी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति पर एक महिला का अपहरण करने का भी आरोप लग चुका है.

लोकायुक्त के समक्ष शिकायत करने वाले ओमशंकर द्विवेदी ने दावा किया है कि वर्ष 2002 तक गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी के ग्राम परसांवा के बीपीएल कार्ड धारक थे. 2012 में वे एपीएल कार्डधारक बने. गायत्री की सालाना आय 24 हजार रुपये होनी थी. बावजूद इसके उनकी कम्पनियों व परिवार के सदस्यों के मालिकाना अधिकार वाली कम्पनियों ने कुछ अरसे में 105 भूखंडों की खरीद-फरोख्त की. मंत्री के परिवारिक सदस्यों के पास इंडीवर, फार्च्युनर, बीएमडब्लू जैसी 11 कीमती गाड़ियां हैं. लोकायुक्त के यहां दी गई शिकायत में उन गाड़ियों के नम्बर नहीं दिए गए हैं. हीरे, सोने व चांदी के गहनों की कीमत भी लाखों में है. लखनऊ के आलमबाग के प्रजापति भवन की अस्थाई और अमेठी की मूल निवासी श्रीमती गुड्डा ने मंत्री के कथित ड्राइवर रामराज के पक्ष में एक रजिस्टर्ड मुख्तारनामा किया है, जिसमें उसे देशभर में उनके नाम से सम्पत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार दिया गया है. गुड्डा खुद एपीएल कार्ड धारक हैं. इल्जाम यह भी है कि गुड्डा जिस प्रजापति भवन में रहती है, उसके कर्ताधर्ता मंत्री गायत्री प्रजापति ही हैं और गुड्डा उनकी विश्वसनीय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

और भी अकूत सम्पत्तियों का खुलासा

शिकायतकर्ता ओमशंकर द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के जरिए प्रजापति परिवार की 1,350 करोड़ रुपये की सम्पत्ति के दस्तावेज जुटाए हैं. इनमें लखनऊ सदर, मेरठ, मोहनलाल गंज, फतेहपुर में खरीदी गई सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी शामिल है. बसपा के पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा का फतेहपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रजापति ने खरीदा है. प्रजापति का ड्राइवर रामराज 37 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का मालिक है. इसी तरह दूसरे ड्राइवर राम सहाय के पास सात करोड़ 80 लाख रुपये की सम्पत्ति है. बेटे अनुराग के नाम पर छह करोड़, 50 लाख रुपये की सम्पत्ति है. दूसरे बेटे अनिल के पास करीब तीन करोड़ 48 लाख रुपये की सम्पत्ति है, जिसकी जायदाद की कीमत 32 करोड़, 18 लाख रुपए है. इसी तरह भाई, पत्नी और कम्पनियों के नाम पर बेहिसाब सम्पत्ति है. विकास वर्मा कम्पनियों का कामकाज संभालता है.

सम्पत्ति का आकलन

नाम	दस्तावेजी मूल्य	वास्तविक मूल्य
महराजी देवी :	1.40 करोड़	5 करोड़
अंकिता :	50 लाख,	दो करोड़
अनुराग :	17.50 करोड़	65 करोड़
अनिल प्रजापति :	34.88 करोड़	
श्रीमती गुड्डा :	27.86 करोड़	37.46 करोड़
राम सहाय व रामराज :	20.69 करोड़	26.90 करोड़
रिश्तेदार :	330.20 करोड़	931.80 करोड़

कम्पनियों में बेनामी निवेश का आरोप

1. डीसेन्ट कांट्रैक्टर्स कम्पनी : निदेशकों में अनिल प्रजापति भी (खनन मंत्री गायत्री प्रसाद का बेटा)
2. एमजी कॉलोनाइजर्स : निदेशक गायत्री प्रसाद प्रजापति
3. ड्रीम्ड डिस्टीनेशन्स कम्पनी : मुख्य निदेशक अलोक श्रीवास्तव
4. शुभांग एक्सपोर्ट्स कम्पनी : निदेशक में अनुराग प्रजापति (खनन मंत्री का दूसरा बेटा)
5. लाइफ क्योर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर : निदेशकों में अनुराग प्रजापति